राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

बेटी के जन्म के बाद बदल गई रोहित की जिंदगी

>> 12

वर्ष 3 अंक 8

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, मंगलवार , 18 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

लोकतंत्र के प्रहरी

आपातकाल के 44 साल

छह माह तक पता ही नहीं चला कहां ले गई पुलिस

आपातकाल के दौरान 11 माह तक अंबाला जेल में बंद रहे झज्जर के लाला श्यामसुंदर गोयल का परिवार आज भी 25 जून की काली रात को याद कर सिहर उठता है। पत्नी प्रेमवती ने सात बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन किसी के सामने दुख नहीं रोया। ● पेज 13

हमारी सरकार

नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री

20 फीसद राजनेता 80 फीसद समाजसेवी

● पेज 5

सरोकार

कोल डस्ट के प्रदूषण से मिलेगी निजात

धनबाद : कोयला खदानों के कारण उड़ने वाली कोल डस्ट को यदि ठोस में बदल जाए तो प्रदूषण से थर्रा रहे धनबाद जैसे शहरों को संजीवनी मिल जाएगी। इस सोच को संभव कर दिखाया है केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है। इसके तहत हवा में उड़ने वाली धूल को ठोस रूप दिया जा सकता है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

बिहार में लू से 64 और की मौत, अब तक 242 मरे

गया : बिहार में लू से होने वाली मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। सोमवार को भी सूबे में 64 की मौत हो गई। गया में आठ, नवादा में 10, सासाराम में 17, औरंगाबाद में पांच, समस्तीपुर में तीन, मुंगेर में पांच और नालंदा, हाजीपुर, छपरा, बेगूसराय, बक्सर व अरवल में 16 की जान गई। शनिवार से बिहार में 242 की मौत हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मची हुई है। मौत के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

भारत को नाटो मित्र जैसा दर्जा देने का प्रस्ताव सीनेट में पेश

वाशिंगटन : रूसी हथियारों की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भले ही चिक-चिक चल रही हो लेकिन दोनों देशों के संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाने की मुहिम में कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद सीनेट (संसद) में भारत को नाटो सहयोगियों की बराबरी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव लाए हैं।

क्रिकेट महाकुंभ
अफगानिस्तान vs इंग्लैंड
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : मैनचेस्टर
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

दिया भरोसा ▶ 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर पीएम ने बढ़ाया सहयोग का हाथ

विपक्षी दलों को देंगे पूरी अहमियत : मोदी

कहा, संख्याबल नहीं, विरोधी दलों का हर शब्द सरकार के लिए मूल्यवान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

17वीं लोकसभा के आगाज के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि लोकसभा के भीतर सत्तापक्ष संख्याबल में भले ही भारी हो, लेकिन विपक्ष की आवाज भी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा, सरकार विपक्ष को पूरी अहमियत देगी। विपक्ष का हर शब्द सरकार के लिए मूल्यवान होगा। वहीं, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार संसद का 'रबर स्टांप' की तरह इस्तेमाल नहीं करेगी और अहम विधायी कार्यों में विपक्ष को साथ लेकर चलेगी।

> जब हम संसद आते हैं तो हमें पक्ष और विपक्ष को भूल जाना चाहिए और मुद्दों पर निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए राष्ट्र के व्यापक हित में काम करना चाहिए।
> – प्रधानमंत्री मोदी

संसद परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा, 'उन्हें संख्या बल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है और उनकी हर बात को गंभीरता से लिया जाएगा।' उम्मीद है कि विपक्ष सदन में सक्रिय ढंग से अपनी बात रखेगा और कार्यवाही में शामिल होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की सक्रियता और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने उम्मीद जताई है कि इस बार सरकार 16वीं लोकसभा की तरह विपक्ष को दरकिनार कर अहम विधायी बिलों को पास कराने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि विपक्ष के सुझावों व मांगों को तरजीह देगी। शर्मा ने कहा, पिछली बार संख्याबल के आधार पर सरकार ने लोकसभा को 'रबर स्टांप' की तरह इस्तेमाल किया था और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की थी और उसके सुझावों व मांगों को अनसुना करती रही थी। इससे पहले, मोदी ने कहा, इस बार की लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक है। आजादी के बाद यह पहला मौका है कि संसद के निचले सदन के लिए सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं चुन कर आई हैं। उनकी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से काम किया था। यही कारण रहा कि दशकों बाद लोगों ने दोबारा किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस भेजा है।

17 वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (बाएं) और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। एएनआइ

उत्साह के साथ हुआ 17वीं लोकसभा का आगाज

नई दिल्ली : सांसदों के शपथग्रहण के साथ ही 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में वरिष्ठता क्रम में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली। शपथग्रहण के पहले प्रधानमंत्री विपक्षी बेंच की ओर जाकर भतृहरि मेहताब, मुलायम सिंह से होते हुए सोनिया गांधी की सीट तक गए, कुछ क्षण तक बातचीत की और फिर अपनी सीट पर लौट आए। (पेज-3)

जेपी नड्डा बने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गृह मंत्रालय के साथ-साथ पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल रहे अमित शाह की व्यस्तता को देखते हुए जेपी नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। चुनाव होने तक शाह अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। हालांकि, यह भी तय माना जा रहा है कि दिसंबर-जनवरी में सांगठनिक चुनाव के बाद नड्डा औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा में पहली बार कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।

दैनिक जागरण ने पिछले बुधवार को जानकारी दी थी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जरूरत महसूस हुई तो संसदीय बोर्ड इस बाबत फैसला लेगा। सोमवार को यह तय हो गया। अमित शाह की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में नड्डा के नाम पर मुहर लग गई। राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह ने पांच साल तक बहुत ही सफलता से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी की जीत सुनिश्चित की। संसदीय बोर्ड चाहता था कि सांगठनिक चुनाव होने तक वह अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालते रहें, लेकिन खुद शाह की ओर से संसदीय बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने प्रस्ताव किया कि सरकार के कामकाज की व्यस्तताओं के कारण पार्टी के दैनिक कामकाज के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो। उन्होंने ही नड्डा का नाम प्रस्तावित किया और सभी ने उस पर मुहर लगा दी। दरअसल, सांगठनिक चुनाव अब महज कुछ महीने दूर है। अगले महीने से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और उसके बाद प्रदेशों में संगठन चुनाव की शुरुआत होगी। आधे से अधिक राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराया जा सकता है।

नड्डा का जेपी आंदोलन से निकल भाजपा के शीर्ष पद तक का सफर पेज>>3

पुलवामा में विस्फोटक लदी गाड़ी से फिर सेना के वाहन पर हमला

घायलों में छह सैन्यकर्मी और दो ग्रामीण, आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल इलाके में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को उड़ाने के लिए विस्फोटकों से लदे वाहन से हमला किया, जिसमें छह फौजी और दो ग्रामीण घायल हो गए। कहा जा रहा है यह हमला आतंकी नवीद ने किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वह आइईडी तैयार करता नजर आया था।

जानकारी के अनुसार, पुलवामा में शाम करीब छह बजे सेना की 44 आरआर के जवानों का एक दल नियमित गश्त पर था। जब यह दल अरिहाल पुल के पास पहुंचा तो वहां आतंकियों ने पहले से सड़क किनारे खड़े अपने वाहन बम में कथित तौर पर रिमोट से धमाका कर दिया, जिससे सैन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद वाहन से बाहर निकले सैन्यकर्मियों पर खेतों में छिपे आतंकियों ने गोलियां भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई किए जाने पर आतंकी भाग निकले। हमले की सूचना मिलते ही निकटवर्ती शिविरों से पुलिस और सेना के जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके से मिले सुराग के आधार पर कहा जा सकता है कि आतंकियों ने किसी वाहन बम का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह वाहन कैसा था, यह जांच का विषय है। एफएसएल की टीम ने मौके से कुछ सैंपल जांच के लिए हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आइईडी धमाके में क्षतिग्रस्त सेना का वाहन। जागरण

जवानों को आई हैं मामूली चोट : रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन से गश्तीदल को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाबलों की सतर्कता के चलते वह नाकाम रहे। सभी जवान सुरक्षित हैं। कुछ को मामूली चोट पहुंची है। उन्होंने बताया कि हमले की चपेट में आने वाला वाहन कैस्पर नहीं है। यह बख्तरबंद वाहन था।

पाक ने दिया था इनपुट : ज्ञात हो, गत दिनों पाकिस्तान ने भारत सरकार को सूचित किया था कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए वाहन हमले की तरह ही आतंकी निकट भविष्य में एक और हमला अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। बता दें कि पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे।

काकपोरा और त्राल में भी आतंकी हमले : आतंकियों ने सोमवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी के शिविर और काकपोरा में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमले किए। इन हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हमले लगभग एक घंटे के अंतराल पर हुए।

अनंतनाग में 12 घंटे चली मुठभेड़ में आतंकी ढेर, मेजर शहीद

श्रीनगर : अनंतनाग जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच 12 घंटे चली मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकी मारा गया। कार्रवाई के दौरान मेजर केतन शर्मा (29) शहीद हो गया, जबकि कैप्टन रैंक के अधिकारियों समेत चार सैन्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। (पेज-6)

अब संस्कृत भाषा में भी जारी होंगे सीएम योगी के भाषण और संदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सूचना विभाग हिंदी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत में जारी करेगा विज्ञप्ति
- भाषण और संदेशों को लिखने के लिए सरकार रखेगी भाषा विशेषज्ञ

विकास और हिंदुत्व योगी सरकार का एजेंडा है। धार्मिक सरोकारों को महत्व देने के साथ ही सरकार ने संस्कृत भाषा को भी प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर से भाषण व संदेश हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत में भी तैयार किया जाएगा। निदेशक, सूचना शिशिर ने बताया कि भाषण और संदेश लिखने के लिए हिंदी में दो और अंग्रेजी व संस्कृत के एक-एक विशेषज्ञ रखे जाएंगे। सरकार की विज्ञप्ति भी संस्कृत भाषा में जारी होगी।

सोमवार को सरकार की ओर से संस्कृत भाषा का पहला प्रेस नोट भी जारी किया गया। नीति आयोग की बैठक की यह प्रेस विज्ञप्ति संस्कृत भाषा में है। संस्कृत का दिन-प्रतिदिन के जीवन में उपयोग भले न हो लेकिन, इस भाषा की पुरातन मान्यता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रयागराज कुंभ से लेकर दीपावली और होली समेत कई प्रमुख पर्वों को भव्यता दी है। सरकार ऐसे आयोजनों का संस्कृत भाषा में प्रभावी ढंग से प्रचार करेगी। प्रदेश में संस्कृत के कक्षा आठ से कक्षा 12वीं तक 1150 संस्कृत विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में करीब 90 हजार बच्चे पढ़ते हैं।

ममता झुकीं, सातवें दिन डॉक्टरों की हड़ताल खत्म

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पश्चिम बंगाल के हर सरकारी अस्पताल में तैनात होगा सुरक्षा अधिकारी
- जूनियर डॉक्टरों की साथियों से काम पर लौटने की अपील, नहीं दर्ज होगा केस
- आज से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने के आसार

पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार सातवें दिन खत्म हो गई। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व डॉक्टरों के प्रतिनिधिदल के बीच डेढ़ घंटे बैठक चली। ममता ने डॉक्टरों की सारी मांगें मानते हुए ड्यूटी के दौरान उनकी पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने प्रत्येक सरकारी अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी घोषणा की।

बैठक के बाद जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी और आंदोलन कर रहे अपने साथियों से जल्द से जल्द काम पर लौटने की अपील की। अब मंगलवार से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने के आसार हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में भर्ती हमले में जख्मी डॉक्टर परिबाह मुखर्जी से भी मिलीं और उनका हालचाल पूछा। इस बीच सोमवार को भी दिनभर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं, जिससे मरीज व उनके परिजनों की परेशानी जारी रही। उत्तर बंगाल व मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा के अभाव में दो बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही बिना इलाज मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। (पेज-4)

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- मरीज संग दो लोगों को वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
- बाहरी लोगों के सरकारी अस्पतालों में प्रवेश रोकने को कदम उठाया जाएगा।
- अस्पतालों में हमले रोकने के लिए 'जीरो टोलेरेंस पॉलिसी' अपनाई जाएगी।

> ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, यह देखना सरकार का काम है। जब किसी का कोई अपना मरता है तो आवेश में आकर उनके परिजन ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। हालांकि सभी को दोष देना सही नहीं है। –ममता बनर्जी

अमेरिका में भारतवंशी परिवार के चार सदस्यों की गोली मारकर हत्या

- आयोवा प्रांत में आइटी पेशेवर, उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटे घर में मृत मिले

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के आयोवा प्रांत में 44 वर्षीय भारतवंशी आइटी पेशेवर व उनके परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेक्नोलाजी सर्विस ब्यूरो में कार्यरत चंद्रशेखर सुनकारा, उनकी पत्नी लावण्या (41) और 15 और 10 साल के दो नाबालिग बेटे शनिवार को घर में मृत पाए गए।

आयोवा सार्वजनिक सुरक्षा विभाग (डीपीएस) के अधिकारियों के मुताबिक, वेस्ट डेस मोइनेस पुलिस शनिवार सुबह 10 बजे 65वें स्ट्रीट के 900 ब्लाक में पहुंची। पुलिस को घर में दाखिल होने पर चार शव मिले। हालांकि पोस्टमार्टम नहीं होने से मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी के शरीर पर गोलियों के घाव पाए गए हैं। आयोवा सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने बयान में कहा है, 'हम दिल से सुनकारा परिवार और उनके मित्रों के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।'

वेस्ट डेस मोइनेस पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दो बच्चों के साथ चार सदस्यों वाला परिवार घर में गेस्ट की तरह रह रहा था। संभवतः चारों की गोली मारकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। सार्जेंट डान वाडे ने कहा है, 'इस त्रासदी से परिवार, मित्र, सहकर्मी और परिवार को जानने वाले हर कोई प्रभावित होंगे। हम जांच में जुटे हैं। सुबूत जहां तक उपलब्ध हो सकेंगे वहां तक हम सवालों का उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि समुदाय को डरने का कोई कारण नहीं है।'

एनबीसी न्यूज ने कहा है कि शव देखने के बाद एक रिश्तेदार मदद के लिए बाहर भागा और एक राहगीर को पाया। राहगीर ने 911 पर कॉल किया। अभी तक किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है। आयोवा अपराध अनुसंधान को इसकी जांच सौंपी गई है।

मौसम की चाल

स्काईमेट का पूर्वानुमान जारी, खरीफ फसलों की बोआई के लिए अच्छा समय, दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई के पहले पखवाड़े में जमकर बरसेगा

जून के आखिरी सप्ताह में झमाझम होगी बारिश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून की धीमी चाल के बावजूद जून के आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश का अनुमान है, जो खरीफ फसलों की बोआई के लिए उचित समय होगा। मौसम एजेंसी स्काईमेट के पूर्वानुमान के मुताबिक जुलाई के पहले पखवाड़े में मानसून की झमाझम बारिश हो सकती है। भारत में बरसने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रारंभिक चरण में बहुत धीमा रहा है, जिसके चलते अब तक होने वाली बारिश में 43 फीसद की कमी दर्ज की गई। मानसूनी बादलों की चाल भी संतोषजनक नहीं रही है।

स्काईमेट के आंकड़ों के मुताबिक जून के पहले पखवाड़े में मध्य भारत, जहां की खेती वर्षा पर ही आधारित होती है, में 58 फीसद तक कम बारिश हुई। पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में 45 फीसद तक कम बारिश दर्ज की गई। जबकि दक्षिण-पश्चिम भारत में 21 फीसद कम बरसात हुई है।

पूर्वी-मध्य भारत में अच्छी बारिश होगी : स्काईमेट के एमडी जतिन सिंह के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं की जो स्थितियां बनी हैं उससे पूर्वी और मध्य भारत क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावना है। किसानों के लिए खरीफ सीजन की फसलों की बोआई के लिए जून के आखिरी सप्ताह से उचित समय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के किसानों को अगले सप्ताह से शुरू होने वाली मानसूनी बारिश से फसलों की बोआई का लाभ मिल सकता है। यहां के किसानों के लिए यह बरसात किसी वरदान से कम नहीं होगी।

सोयाबीन की सिंचाई नहीं करने की सलाह : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां सिर्फ दो दिनों की बारिश के बाद भी तापमान 40 डिग्री सेल्यिस के आसपास रहने का अनुमान है। इस तरह के मौसम में जहां सोयाबीन की बोआई हो चुकी है, उन्हें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। बिहार और झारखंड में धान की रोपाई का समय है, जहां बारिश जमकर होगी। इससे धान की फसल को लाभ होगा। पंजाब और हरियाणा में 21 से 30 जून के बीच रुक-रुक कर अच्छी बारिश हो सकती है, जिसका लाभ यहां के किसानों को धान की रोपाई में मिल सकता है।

मुंबई में 25 जून को भारी बारिश का अनुमान: मुंबई में भी 25 जून को भारी बारिश हो सकती है। यह इस मानसून सीजन की सबसे बड़ी बरसात हो सकती है। अगर मुंबई प्रशासन पहले से सतर्क हो जाता है तो मुंबई के लोगों लिए आगामी सप्ताह शानदार रहेगा। अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। (पेज-7 भी देखें)

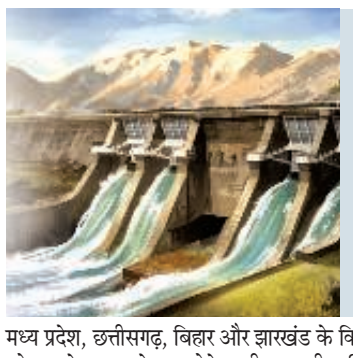

91 जलाशयों का जलस्तर घटा

स्काईमेट के मुताबिक देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कम बारिश का सबसे बुरा असर जलाशयों पर पड़ा है। देश के प्रमुख 91 जलाशयों का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसका असर यहां के जनजीवन पर पड़ा है। विशेषतौर पर केंद्रीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 12 बड़े जलाशय हैं, जिनका जलस्तर नीचे खिसक गया है। पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के जलाशयों में भी जलस्तर पिछले 10 साल के औसत जल स्तर से नीचे हो गया है।

18 सौ अनधिकृत कॉलोनियां हैं दिल्ली में। इनमें करीब 40 लाख की आबादी रहती है। एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण ये कॉलोनियां लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रही थीं और हर चुनाव में ही मुद्दा बनती रही हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 जून 2019

चालक से मारपीट मामले में दो एएसआइ समेत तीन निलंबित

गिरी गाज ▸ पुलिसकर्मियों ने की थी चालक और उसके नाबालिग बेटे की पिटाई, दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी लटकी तलवार, थाने पर जमे रहे लोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुखर्जी नगर में सड़क पर ग्रामीण सेवा चालक व उसके बेटे से मारपीट मामले में उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्या ने दो एएसआइ संजय मलिक व देवेंद्र और सिपाही पुष्पेंद्र को निलंबित कर दिया। इस प्रकरण में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। सोमवार को बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर लोग थाने के बाहर दिनभर जमे रहे।

रविवार को ग्रामीण सेवा चालक व उनके पुत्र की पिटाई को लेकर लोगों ने रात भर हंगामा किया। शालीमार बाग के एसीपी केजी त्यागी व अन्य पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। उग्र भीड़ ने मुखर्जी नगर लाल बत्ती के पास रिंग रोड पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

चालक सरबजीत व उनके बेटे की बीच सड़क पर पिटाई के बाद मुखर्जी नगर इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर दो वाहनों में पुलिसकर्मी भेजे गए, लेकिन उन्हें देखते ही उग्र भीड़ डंडे लेकर दौड़ पड़ी और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों को वहां से लौटना पड़ा। गुस्साए लोगों ने डंडे से पुलिस वैन के शीशे भी तोड़ डाले। स्थिति तब काबू में आई, जब मुखर्जी नगर थाने में बैठी जिला पुलिस उपायुक्त ने देर रात ही तीन पुलिसकर्मियों के निलंबन का आदेश दिया। इसकी कॉपी कुछ देर में ही सार्वजनिक भी कर दी गई।

पुलिस के ललकारने पर गाड़ी से बाहर आए थे सरबजीत : पुलिस के अनुसार, सरबजीत ने तलवार से पुलिसकर्मी के सिर पर वार कर दिया, तब उसके साथ ऐसा सुलूक किया गया। लेकिन घटना को लेकर वायरल वीडियो को देखकर पुलिस का तर्क गले नहीं उतर रहा है। वीडियो के अनुसार, चालक ने तलवार निकाली तो वहां मौजूद ईआरवी (जिसे ग्रामीण सेवा चालक सरबजीत ने टक्कर मारी थी) पर तैनात पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाने के लिए थाने के अंदर चले गए। इस बीच सरबजीत को उनका बेटा खींचकर ले जाकर ग्रामीण सेवा में बैठा देता है। कुछ ही देर में आठ-दस पुलिसकर्मी हाथों में डंडा लिए बाहर आते हैं और ललकराते हुए आगे बढ़ते हैं तो सरबजीत वाहन से बाहर आते हैं।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मुखर्जी नगर में ग्रामीण सेवा चालक सरबजीत और उसके 16 साल के बेटे की पुलिस द्वारा की गई पिटाई के मामले की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। इस मामले में घायल पुलिसकर्मियों व सरबजीत की शिकायत के आधार पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें घायल पुलिसकर्मियों के बयान पर सरबजीत पर हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों पर दर्ज किए गए केस की जांच अब अपराध शाखा करेगी। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे रिपोर्ट तलब करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

सरबजीत से मिलने उनके घर पहुंचे केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुखर्जी नगर में ग्रामीण सेवा चालक की पिटाई पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में दिल्ली पुलिस की बर्बरता बहुत निंदनीय है। मैं इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। दिल्ली पुलिस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा करने वालों को अनियंत्रित हिंसक डकैतों में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

दरअसल, मुख्यमंत्री सोमवार को गांधी विहार गए और उन्होंने ग्रामीण सेवा चालक सरबजीत सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं उपराज्यपाल, डीसीपी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त से अपील करता हूं कि हमले के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दी जाए। पुलिस को किसी भी नागरिक के साथ अमानवीय बर्ताव की छूट नहीं दी जा सकती। दिल्ली में अपराध की बढ़ती दर के बारे में एलजी और गृहमंत्री को बहुत सख्त होना पड़ेगा। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि जहां तक मुझे याद है दिल्ली में भाजपा के सात सांसद चुने गए थे, क्या उनका कुछ अता-पता है? उनकी पार्टी की पुलिस आम आदमी को सड़क पर घसीट रही है। कोई सांसद कुछ करेगा या सब अगले चुनाव तक कमेंट्री करके पैसा कमाने में व्यस्त हैं? आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी कहा कि ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां एक व्यक्ति को निर्ममतापूर्वक पीटा जा रहा है। जिनके ऊपर आपकी रक्षा की जिम्मेदारी है, वही पुलिस आपके लिए खतरा बन गई है। गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले।

मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और विधायक जरनैल सिंह, जगदीप सिंह, पंकज पुष्कर और अखिलेश पति त्रिपाठी भी सरबजीत सिंह से मुलाकात करने मुखर्जी नगर पहुंचे थे। सरबजीत सिंह के घर पर उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया।

सरबजीत के घर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने उनका हालचाल जाना। फोटो : सौजन्य दिल्ली सरकार

हालात तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में : चालक सरबजीत और उनके बेटे की पिटाई के बाद बिगड़े हालात सोमवार को नियंत्रण में रहे, लेकिन मुखर्जी नगर इलाके में स्थिति तनावपूर्ण रही। सोमवार को भी थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस कारण इलाके में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पारा मिलिट्री के जवानों ने शाम को थाने के सामने डटे लोगों को हटा दिया और फ्लैग मार्च भी किया।

कैप्टन बोले, उचित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएं शाह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

दिल्ली में सिख ग्रामीण सेवा चालक को पीटने के मामले में पंजाब का सियासी पारा गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना को बर्बरतापूर्ण और शर्मनाक बताया है। आम आदमी पार्टी ने आरोपित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है तो अकाली दल ने कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाए।

मुख्यमंत्री अमरिंदर ने पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस ने सरबजीत और उनके बेटे की बर्बरतापूर्वक पिटाई कर शर्मनाक कृत्य किया है। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से गुजारिश है कि उचित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएं। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषी पुलिस वालों को बर्खास्त कर उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। उधर, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि दोषी पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उन पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाए।

अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

▸ सुखबीर बादल बोले-बर्खास्त किए जाएं आरोपित पुलिसकर्मी

एसजीपीसी ने लिया नोटिस, केंद्रीय गृह सचिव को लिखा पत्र

जासं, अमृतसर : एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने घटना की कड़ी निंदा की है। लोगोंवाल ने कहा कि अल्पसंख्यक सिखों के साथ इस तरह का अन्याय किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। दोषी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इस मामले को लेकर जो भूमिका अदा की गई है, वह प्रशंसनीय है।

न्यूज गैलरी

एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में दंपती समेत चार गिरफ्तार

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी में कस्टम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक किलो 779 ग्राम सोना मिला है, जिसकी कीमत 52 लाख रुपये से ज्यादा है। आइजीआइ एयरपोर्ट की ज्वाइंट कस्टम कमिश्नर अनुभा सिन्हा ने बताया कि घटना 14 जून की है। एयर इंडिया की उड़ान बैंकॉक से दिल्ली आई थी। इससे उतरे चार संदिग्ध एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जुगत में लगे थे। कस्टम अधिकारियों की उन पर नजर थी। जैसे ही उन्होंने ग्रीन चैनल पार किया, उनके सामान की तलाशी ली गई। उनके पास से सोने के चार टुकड़े और एक चेन बरामद हुई। आरोपितों में पति और पत्नी, जबकि अन्य एक उनका रिश्तेदार और दूसरा पड़ोसी है। (जासं)

छह सालों में सबसे ठंडा रहा 17 जून का दिन

नई दिल्ली : दिल्ली में सोमवार को मौसम सुहावना ही बना रहा। बादल छाए रहने से धूप के तेवर भी हल्के रहे। तापमान में 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। आलम यह रहा कि पिछले छह सालों में 17 जून का दिन सबसे ठंडा दर्ज किया गया। अभी दो तीन दिन मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। सोमवार का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से छह डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि इस मौसम का सामान्य तापमान है। नमी का स्तर 45 से 65 फीसद तक रहा। मालूम हो कि पिछले सप्ताह तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। (राब्यू)

धोखाधड़ी के आरोपित मोंटी चड्ढा को सशर्त जमानत

नई दिल्ली : 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपित वेव ग्रुप के मालिक मोंटी उर्फ को साकेत स्थित अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। वह बगैर इजाजत विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा। मोंटी चड्ढा के वकीलों ने सोमवार को अदालत में याचिका दायर कर जमानत देने के संबंध में पक्ष रखा। अभियोजन की भी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बांड जमा करने की शर्त पर मोंटी को जमानत देने का आदेश दिया। (राब्यू)

तीन श्रेणियों में नियमित की जाएंगी अनधिकृत कॉलोनियां

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लंबी रस्साकशी के बाद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के दिन अब बहुरने वाले हैं। इनके विकास का खाका तैयार है। अगले माह इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल जाएगी। ऐसी तमाम कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटकर नियमित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ही हरी झंडी देने जा रही है।

इस रिपोर्ट में दिल्ली की सभी 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली श्रेणी में वे कॉलोनियां होंगी जो सरकारी जमीन पर बसी हैं। दूसरी श्रेणी में वे कॉलोनियां शामिल रहेंगी जो ग्राम सभा की उस जमीन पर बसी हैं, जिस पर सरकार कब्जा नहीं ले सकी। तीसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियों रहेंगी। पहली श्रेणी में रहने वालों को नाममात्र के शुल्क पर मालिकाना हक दिया जाएगा। मकान का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से कम है तो सर्किल रेट का एक फीसद और अगर इससे ज्यादा है तो दो फीसद की दर से भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में मालिकाना हक का शुल्क तय करने पर विचार चल रहा है। इस श्रेणी की कॉलोनियों को एलजी की मंजूरी से शहरीकृत गांव में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि तीसरी श्रेणी के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। सूत्र बताते हैं कि एलजी की रिपोर्ट में डीडीए की भी इस संदर्भ में बड़ी भूमिका तय की गई है। सबसे पहले डीडीए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की मदद से इन कॉलोनियों की रिमोट सेंसिंग और ड्रोन के जरिये मैपिंग करेगा, ताकि उनका डाटा अपडेट किया जा सके। इसके बाद डीडीए एक सिंगल विंडो या पोर्टल शुरू कर शुल्क लेने की व्यवस्था करेगा।

तीन कॉलोनियों को राहत नहीं : एलजी ने अपनी रिपोर्ट में तीन बड़ी कॉलोनियों सैनिक फार्म, महेंद्रू एन्क्लेव और अनंतराम डेयरी को नियमित करने की कोई सिफारिश नहीं की है। दरअसल, ये वे कॉलोनियां हैं, जो वन विभाग, यमुना खादर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन पर बसी हुई हैं।

बाइक बोट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड हैं 172 लग्जरी कारें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

बाइक बोट कंपनी ने जनता से ठगे गए पैसे से ऑडी, जगुआर, रेंज रोवर और फार्चूनर जैसी 172 लग्जरी कारें खरीदी हैं। सभी गाड़ियां कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। प्रापर्टी, खदान व विश्वविद्यालय में मोटी रकम निवेश की गई। गौतमबुद्ध नगर स्थित दादरी के कोट गांव में बाइक बोट का ऑफिस किराये पर लिया गया था। पांच दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद सोमवार को कंपनी के मालिक संजय भाटी को जेल भेज दिया गया। पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड अर्जी दाखिल करेगी।

गौरतलब है कि दादरी के कोट गांव स्थित बाइक बोट कंपनी ने सवा दो लाख निवेशकों से अरबों की ठगी की है। दोगुना मुनाफे का लालच देकर बाइक किराये पर लगाने के नाम पर ठगी की शुरुआत की गई थी। कंपनी के मालिक संजय भाटी ने कुछ दिन पहले गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय में समर्पण किया था। कंपनी के फ्रेंचाइजी हेड विजय पाल कसाना को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। विजय पाल को तीन दिन व संजय भाटी को पांच दिन तक रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने निवेशकों को दिए जाने वाले चेक व कई अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। बरामद दस्तावेज दादरी कोतवाली के मालखाने में रखवाए गए हैं। जांच बढ़ने के साथ ही बाइक बोट कंपनी के जाल में फंसे निवेशकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के अलावा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपित संजय भाटी अलग-अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हेड व निदेशकों को लग्जरी कार गिफ्ट करता था। उनको झांसा दिया जाता था कि जितने ज्यादा निवेशक वे कंपनी के लिए लाएंगे, उनको उतनी ही महंगी कार गिफ्ट में दी जाएगी।

खरीदी गई थी दस हजार बाइक : करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपित संजय भाटी ने करीब दस हजार बाइक कंपनी के नाम से खरीदी थीं। इन्हें अलग-अलग प्रदेशों में सड़क पर उतारने की तैयारी थी। इनमें से करीब पांच हजार बाइक के रजिस्ट्रेशन का काम भी पूरा कर लिया गया था। शेष पांच हजार बाइक का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो सकता था। आरोपित संजय भाटी ने अपने बेटे गर्वित के नाम पर कंपनी बनाई थी। इसे संचालित करने के बाद बाइक बोट के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बेटे की साढ़े तीन साल की उम्र में आकस्मिक मौत हो गई थी।

▸ कंपनी के मालिक संजय भाटी की पांच दिन की रिमांड पूरी

▸ कंपनी ने सवा दो लाख निवेशकों से अरबों की ठगी की

संजय भाटी की रिमांड पूरी हो गई है। उसको फिर से रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी।

-वैभव कृष्ण, एसएसपी, गौतमबुद्धनगर

अब गो वे कंपनी ने 17 हजार से अधिक निवेशकों से की करोड़ों की ठगी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

बाइक बोट के बाद गो वे स्कूटर टैक्सी के नाम पर 17 हजार से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी मालिक कार्यालय पर ताला लगाकर फरार हो गया। पति-पत्नी ने मिलकर ठगी का यह धंधा ग्रेटर नोएडा के साइट फोर स्थित कार्यालय से शुरू किया था। बुलंदशहर निवासी दीपेश शर्मा ने कंपनी मालिक अनिल सेन व उसकी पत्नी मीनू के खिलाफ कासना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपित पति-पत्नी की तलाश में पुलिस की टीम दिल्ली-एनसीआर में दबिश दे रही है।

ग्रेटर नोएडा में गो वे स्कूटर टैक्सी की शुरुआत 2018 में की गई। एक स्कूटर टैक्सी के नाम पर 62 हजार रुपये जमा कराए गए और एक साल में दो गुना वापस करने का वादा किया गया। कंपनी मालिकों को जब लगने लगा कि उनकी कंपनी डूब रही है तो उन्होंने निवेशकों को रिटर्न देना बंद कर दिया। भुगतान नहीं होने पर एक साल बाद पहली एफआइआर दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा में इन दिनों टैक्सी के नाम पर लोगों से ठगी का धंधा जोरों पर है। कमर्शियल बेल्ट में भी ऐसी कंपनी चल रही है जो कि निवेशकों से रकम ठग रही हैं।

आदेश की नाफरमानी से हाई कोर्ट नाराज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय रिज क्षेत्र में 1.4 लाख पौधे लगाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यह पौधे नहीं लगाए गए। इस आदेश की नाफरमानी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन विभाग को जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने वन विभाग से कहा कि आप पौधे लगाने के आदेश को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के नागरिकों की जिंदगी आपके लिए मायने नहीं रखती। देखिए, शहर में कितनी गर्मी है, पौधारोपण को टालना छोड़िए और इसे तत्काल पूरा करिए।

पीठ ने यह कड़ा रुख तब दिखाया, जब दिल्ली सरकार ने पीठ के समक्ष जानकारी दी कि उन्होंने अब तक महज 3500 पौधे लगाए हैं और 2500 पौधे सप्ताह के अंत तक लगा दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि 15 जून तक 30 हजार पौधे लगाने के आदेश दिए गए थे और सप्ताह के अंत तक छह हजार पौधे लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वन विभाग ने बताया कि 30 मई के आदेश के बाद उन्होंने केंद्रीय रिज क्षेत्र में पौधारोपण के लिए सर्वे किया और 2500 अन्य पॉकेट की भी पहचान की।

▸ केंद्रीय रिज क्षेत्र में 1.4 लाख पौधे लगाए जाने के दिए थे निर्देश

हालांकि, उन इलाकों में पौधों को पानी मैनुअल तरीके से ही दिया जा सकेगा। उन्होंने इसके साथ ही बाकी बचे पौधों को दक्षिण रिज क्षेत्र में लगाने की अनुमति देने की मांग की। पीठ को विभाग अपनी दलीलों से संतुष्ट नहीं कर सका।

वन विभाग का रुख है कि केंद्रीय रिज के चट्टानी इलाके में मिट्टी की ढीली और पतली परत है, जहां 11 मार्च को अदालत द्वारा आदेश दिए जाने के बाद इतनी बड़ी संख्या में तीन वर्षीय पौधे लगाना मुश्किल होगा। वन विभाग ने पीठ से उसके 11 मार्च और 30 मई को दिए आदेशों को संशोधित कर दक्षिणी रिज क्षेत्र में पौधे लगाने की अनुमति मांगी है। रिज प्रबंधन बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने सुझाव दिया कि कुछ पौधारोपण को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने वन विभाग को केंद्रीय रिज क्षेत्र में 5000 और दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग 50000 पौधे लगाने का निर्देश दिया। ऐसे में कुल 1.4 लाख पौधे में से 61 हजार पौधे इस तरह से लगाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान वन विभाग ने कहा कि जहां पौधे लगाए गए हैं, वहां की ड्रोन के माध्यम फोटोग्राफी गर्मी के कारण नहीं हो पा रही है। इस पर पीठ ने कहा कि फोटोग्राफी के लिए कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि एक विवाह समारोह में लोग कई एंगल से ड्रोन के माध्यम से फोटो खींचते मिल जाएंगे, उनमें से ही कुछ लोगों को 10 हजार रुपये का भुगतान करें और वे आपके लिए पूरे रिज को कवर कर देंगे।

क्या था हाई कोर्ट का आदेश : हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भारतीय दवा फर्म वेंकटनारायण एक्टिव इंग्रिडिएंट प्राइवेट लिमिटेड को केंद्रीय रिज में 1.4 लाख पौधे लगाने के आदेश दिए थे। साथ ही वन विभाग को निर्देश दिया था कि वह इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

आठ रनवे का होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर में प्रस्तावित देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आठ रनवे का निर्माण होगा। इससे पहले यहां यूपी कैबिनेट ने कुल छह रनवे के निर्माण को मंजूरी दी थी। तीनों प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में यहां उपलब्ध जमीन के आधार पर मुख्यमंत्री ने दो और रनवे बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इससे यहां अब आठ रनवे बनने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद टीईएफआर में दो और रनवे जोड़ दिए जाएंगे।

एयरपोर्ट निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। 2020 तक कंपनी का चयन कर निर्माण शुरू किया जाएगा। करीब आधा दर्जन से अधिक कंपनियों ने नियाल के साथ काम करने के लिए संपर्क किया है। इससे पहले यहां 2022 तक दो रनवे तैयार कर यहां से उड़ान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। दो रनवे से हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद बाकी के छह और रनवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा के दौरान यहां प्रस्तावित कुल छह रनवे के निर्माण के बाद बची हुई जमीन को भी उपयोग करने के लिए कुल आठ रनवे बनाने पर सहमति दे दी। वहीं एयरपोर्ट के चार रनवे का टेक्निकल इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर) बनने का काम भी शुरू हो गया है। इसे बनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूसी कंपनी को दी गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के पास पर्याप्त जमीन है। यहां चार रनवे का काम साथ पूरा किया जा सकता है।

नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से 2022 में शुरू होंगी उड़ानें

आइपीयू के 36 कोर्सों में मिलेगी ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) के कार्यवाहक कुलपति प्रो. आशुतोष मोहन ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस वर्ष ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा का विस्तार किया गया है। पिछले सत्र में जहां दस अलग-अलग कोर्सों में ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा थी, इस वर्ष यह संख्या बढ़ाकर 36 कर दी गई है। स्टूडेंट हेल्पलाइन को भी बेहतर किया जा रहा है।

नामांकन प्रक्रिया को लेकर द्वारका स्थित गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपी यूनिवर्सिटी) में प्रेसवार्ता आयोजित हुई। इसमें बताया गया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने कई ऐसे व्यावसायिक कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। योग की लोकप्रियता व इसमें रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस सत्र में एमएससी (योग) कोर्स की शुरुआत की गई है। योग में ही विश्वविद्यालय ने पीजी डिप्लोमा का नया कोर्स भी शुरू किया है।

मिशन एडमिशन

परास्नातक, एमफिल व पीएचडी के विद्यार्थियों को भी मिलेगा लाभ, इसी हफ्ते कटऑफ की तारीखें की जाएंगी जारी

अब सभी पाठ्यक्रमों के लिए 22 जून तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की तिथि 22 जून तक बढ़ा दी है। दाखिला समिति के अध्यक्ष व स्टूडेंट वेलफेयर के डीन प्रो. राजीव गुप्ता ने बताया कि स्नातक, परास्नातक, एमफिल व पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। कटऑफ से संबंधित नई तारीखें भी इसी हफ्ते जारी कर दी जाएंगी।

पहले परास्नातक और एमफिल-पीएचडी पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून थी। पहली कटऑफ सूची 20 जून को आनी थी। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स व बीकॉम ऑनर्स जैसे पाठ्यक्रमों के पात्रता मानदंड को इस वर्ष बदले जाने के खिलाफ छात्र दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने स्नातक पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन तिथि 22 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। सोमवार को डीयू ने सभी पाठ्यक्रमों की तारीखों को 22 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि जून के चौथे हफ्ते में पहला कटऑफ जारी हो सकता है। आमतौर पर स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन की तिथि समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पहला कटऑफ जारी किया जाता है।

एडमिशन ब्रांच गठित करने की मांग : डीयू में सोमवार दोपहर बाद चार बजे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी पाठ्यक्रमों की न्यूनतम पात्रता पिछले शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के तहत ही रहेगी। हाई कोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने डीयू प्रशासन से एडमिशन ब्रांच गठित करने का अनुरोध किया। यह ब्रांच सालभर दाखिले से जुड़ी नीति, सुधार की दिशा में काम करते हुए सभी हितधारकों से संवाद करके प्रवेश नीति बनाए।

डीयू में सर्वर डाउन, दाखिला फॉर्म भरने में आ रही समस्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातक पाठ्यक्रमों के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है, लेकिन अब भी छात्र नियमों व दाखिला पोर्टल पर फॉर्म भरने को लेकर परेशान हो रहे हैं। सोमवार को परास्नातक एवं एमफिल-पीएचडी के छात्रों को भी फॉर्म भरने में परेशानी हुई। छात्रों ने कहा कि ऐसा भी समय आया, जब सर्वर ही डाउन हो गया। इस वजह से फॉर्म भरने में देरी तो हुई ही, दस्तावेज भी अपलोड नहीं किए जा सके।

छात्रों की शिकायत है कि डीयू में एमफिल-पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन में दूसरे विश्वविद्यालयों की तुलना में लंबी फॉर्म प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। कुछ अनावश्यक क्रम भी थे, जिन्हें आसान किया जा सकता था। कई बार वेबसाइट का सर्वर डाउन होने से परेशानी हुई।

डीयू अधिकारियों ने कहा कि दाखिला पोर्टल में बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण फॉर्म भरने में देरी हो रही है। आवेदन शुल्क रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन नहीं, बल्कि पहले जमा कराएं।

परास्नातक में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने की मांग : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) ने डीयू प्रशासन से मांग की है कि परास्नातक पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन की तिथि चार दिन बढ़ाई जाए। डूसू ने कहा कि बीते दो दिनों से वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते समय छात्रों को परेशानी हो रही है। कई छात्र तो आवेदन ही नहीं कर पाए इसलिए डीयू प्रशासन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाए। डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि दाखिला पोर्टल पर लगातार आ रही समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत है। हमने सोमवार को छात्रों की प्रवेश संबंधी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी हैं।

एम्स ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों से हाथापाई, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सड़क हादसे में घायल मरीज को पहले देखे जाने को लेकर एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के जूनियर डॉक्टरों और मरीज के तीमारदारों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज व हाथापाई की। इसके विरोध में सोमवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। पुलिस ने डॉक्टरों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित राजकुमार, अमन व विकास को गिरफ्तार किया, जबकि उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे एम्स ट्रॉमा सेंटर में दुर्घटना में घायल एक मरीज पहुंचा। उस समय एक अन्य गंभीर मरीज का उपचार किया जा रहा था। राजकुमार, अमन और विकास ने अपने मरीज का उपचार पहले करने को लेकर डॉक्टरों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध में इन्होंने गाली-गलौज कर डॉक्टरों से हाथापाई भी की। एम्स रेजिडेंट

1921 से 1927 के दौरान हुआ था संसद भवन का निर्माण। इस वृत्ताकार भवन का व्यास 560 फीट है। लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैले संसद भवन के 12 दरवाजे हैं, जिनमें से पांच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं।

संसद का पहला दिन कैमरे की नजर में

नई दिल्ली में 17वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (टीवी ग्रेब)। प्रेट्र

शपथ ग्रहण के दौरान राजनाथ सिंह (टीवी ग्रेब)।

शपथ लेते राहुल गांधी (टीवी ग्रेब)। एएनआइ

सोमवार को 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार सत्र के दौरान अलग-अलग अंदाज में दिखे। एएनआइ

नई दिल्ली में सोमवार को संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद आजम खां। प्रेट्र

संसद सत्र में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। उनके पुत्र चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्य। प्रेट्र

पश्चिम बंगाल के मंत्रियों का जय श्रीराम से स्वागत किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : पश्चिम बंगाल से आने वाले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी का साथी भाजपा सांसदों ने 'जय श्री राम' नारे के साथ स्वागत किया। जिस समय दोनों शपथ लेने पहुंचे उसी समय भाजपा सांसदों ने नारे बुलंद किए। इस नारे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्पष्ट संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जय श्रीराम नारा लगाने पर नाराजगी जाहिर करने के लिए जानी जाती हैं।

राज्य के 24 परगना जिले में 31 मार्च को जिस समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, उस समय जय श्रीराम नारा लगाने पर कम से कम सात लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोगों को जय श्रीराम का नारा बुलंद करते देखा गया। क्रुद्ध होकर ममता कार से बाहर आईं और अपने सुरक्षा अधिकारियों से इसमें शामिल लोगों का नाम दर्ज करने को कहा था।

संसद सत्र ▸ प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने दिलाई प्रधानमंत्री मोदी समेत 313 सांसदों को शपथ

उत्साह के साथ हुआ 17वीं लोकसभा का आगाज

प्रधानमंत्री ने दिए विपक्ष को साधने के संकेत, राहुल गांधी की गैरमौजूदगी को लेकर उठे सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सांसदों के शपथग्रहण के साथ ही 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में वरिष्ठता क्रम में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली। शपथग्रहण के पहले प्रधानमंत्री विपक्षी बेंच की ओर जाकर भतृहरि मेहताब, मुलायम सिंह से होते हुए सोनिया गांधी की सीट तक गए, कुछ क्षण तक बातचीत की और फिर अपनी सीट पर लौटे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा में पिछली लोकसभा की कड़वाहट को भूल कर सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया।

प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, भाजपा और राजग के सदस्यों ने उनके स्वागत में मेजें थपथपाई और मोदी-मोदी के नारे लगाए। उसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली।

सोमवार को प्रधानमंत्री सहित जिन 313 सांसदों को शपथ दिलाई गई उनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। शेष सदस्यों को मंगलवार को शपथ दिलाई जाएगी। पहले सदन में राहुल की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठे थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सदन के भीतर सवाल किया कि राहुल गांधी कहां हैं? लेकिन दोपहर बाद राहुल गांधी सदन के भीतर मौजूद दिखे और सदस्यता की शपथ भी ली। अंग्रेजी में शपथ लेने के बाद वह अपनी सीट को ओर बढ़ गए तब सामने बैठे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका कि रजिस्टर में हस्ताक्षर करें। उसके बाद सचिवालय के सदस्य ने उन्हें बताया कि अध्यक्ष के आसन की परिक्रमा करते हुए अपनी सीट पर जाएं। इससे पहले राहुल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह चौथी बार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे।

प्रधानमंत्री के शपथ से पहले जो जोश दिखा वह राहुल को अमेठी से हराकर सदन में पहुंची स्मृति ईरानी के वक्त भी दिखा। प्रधानमंत्री समेत दूसरे भाजपा सदस्यों ने बहुत देर तक मेजें थपथपाई। प्रधानमंत्री मोदी समेत अधिकांश नवनिर्वाचित सांसदों ने हिंदी में शपथ ली। हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, श्रीपद नाइक और अपनी सादगी के कारण चर्चा में रहे बालाघाट से पहली बार सांसद बने प्रताप सारंगी व प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संस्कृत में शपथ ली। दूसरे कई सांसदों ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली।

नाम बदलने के कारण प्रज्ञा ठाकुर के शपथ ग्रहण पर हुआ विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ नाम में आध्यात्मिक गुरु का नाम जोड़ा, विपक्ष ने जताई आपत्ति

भोपाल से कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को हराकर पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने शपथ ग्रहण में विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल शपथ के सेट फार्मेट से हटकर उन्होंने अपना नाम लिया जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। उन्होंने अपने नाम के साथ अपने अध्यात्मिक गुरु का नाम उपनाम के रूप में जोड़ा था। विपक्षी सांसदों का कहना था कि शपथ सिर्फ उसी नाम के साथ लिया जा सकता है, जिससे नामांकन भरा गया हो। विरोध और हंगामे के बीच ठाकुर ने कहा कि यह उनका पूरा नाम है और उन्होंने शपथ के लिए भरे गए फार्म में अपने पूरे नाम का उल्लेख किया है।

प्रज्ञा ने उपनाम के रूप में स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी के नाम का उल्लेख किया। विपक्ष की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि यह उनके नाम का हिस्सा है। इसके बाद विपक्ष से हंगामा शुरू हो गया और सत्तापक्ष से भी नारे लगने लगे।

इसके बाद प्रोटेम स्पीकर विरेंद्र कुमार ने लोकसभा महासचिव से नाम की जानकारी मांगी। इसके बाद उन्होंने व्यवस्था दी कि रिटर्निंग अधिकारी ने जिस नाम के साथ चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया है, केवल वही नाम लिया जा सकता है। प्रज्ञा ठाकुर ने शपथ के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। विपक्ष की ओर से इसपर भी आपत्ति जताई गई और फारमेट का ध्यान रखने को कहा। लेकिन उसके बाद से बहुत देर तक हर भाजपा सदस्य के शपथ लेने के बाद सत्तापक्ष से भारत माता की जय के नारे लगते रहे।

संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करती भोपाल से भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

शपथ ग्रहण समारोह में दिखी भाषाई सतरंगी छटा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी की अनिवार्यता का जो दक्षिण भारत के राज्य मुखर विरोध करते रहे, उसी केरल के कांग्रेस सांसद कोडीकुनील सुरेश ने 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन हिंदी में शपथ ग्रहण करके सबको आईना दिखाया है। 17वीं लोकसभा में चुनकर पहुंचे सदस्यों ने भाषा की सतरंगी छटा बिखेरी।

हिंदी में शपथ लेने वाले दिग्गज
नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)
अमित शाह (केंद्रीय गृहमंत्री)
राजनाथ सिंह (केंद्रीय रक्षा मंत्री)

पंजाबी का सुनाई दिया सुर
केंद्रीय मंत्री का अंग्रेजी में शपथ ग्रहण करने वाली अकाली दल से लोकसभा पहुंचीं हरसिमरत कौर ने संसद सदस्यता की शपथ पंजाबी में ली।

मराठी का बिगुल
शिवसेना से संसद पहुंचे अरविंद सावंत ने मराठी में शपथ ग्रहण किया।

कोकणी में शपथ
श्रीपाद नाईक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय

डोगरी में ली शपथ
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से आते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी में शपथ ग्रहण किया।

संस्कृत में शपथ
हर्षवर्धन : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
अश्विनी चौबे : राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रताप चंद्र सारंगी : राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय

खींचा ध्यान
केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और 17वीं लोकसभा में चुने गए सदस्य कोडीकुनील सुरेश ने न तो अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किया और न ही अपनी मातृभाषा मलयालम में। हिंदी में शपथग्रहण करके उन्होंने सभी सदस्यों का ध्यान खींचा।

लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हो सकते है कांग्रेस के नेता

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

▸ के. सुरेश को मिल सकती है उपनेता की जिम्मेदारी
▸ कांग्रेस हाईकमान जल्द कर सकता है नामों का एलान, दौड़ में फिलहाल और भी कई नाम शामिल

लोकसभा में नेता के चयन को लेकर कांग्रेस का असमंजस खत्म होता दिख रहा है। फिलहाल यदि कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल से पांचवीं बार जीत कर आए अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया जा सकता है। हालांकि इस दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने-जाने वाले चौधरी को इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है।

पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही लोकसभा में उपनेता के रूप में के. सुरेश को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टी को लोकसभा में नेता और उपनेता के चयन को लेकर यह कवायद तब करनी पड़ रही है, जब 16 वीं लोकसभा में पार्टी के नेता और उपनेता दोनों को ही 17 वीं लोकसभा के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। 16 वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जबकि उपनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। दोनों को ही इस बार चुनाव हार गए।

पार्टी सूत्रों की मानें तो संसद सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में पार्टी जल्द से जल्द अपने नेता और उपनेता के नामों की घोषणा करेगी। वैसे भी 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव को देखते हुए इससे पहले कांग्रेस को यह घोषणा करनी है। पार्टी ने इसके लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को अधिकृत किया है।

लोकसभा में कांग्रेस नेता की दौड़ में चौधरी का नाम इसलिए भी सबसे मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही उनके पास संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव भी है। वह केंद्र और राज्य दोनों में मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में वह पश्चिम बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उस समय इस पद से हटा दिया था। बावजूद इसके वह कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे।

जनमत संग्रह से हो चुनाव में ईवीएम या मतपत्र के इस्तेमाल का फैसला

▸ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा, जब मैं कानून मंत्री था तब मैंने बनाई थी एक कमेटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर गंभीर संदेह हैं। यह तय करने के लिए जनमत संग्रह होना चाहिए कि चुनाव ईवीएम से हों या मतपत्रों से कराए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जनमत संग्रह भी मतपत्र के जरिये ही होना चाहिए और देश की जनता जिसके पक्ष में निर्णय दे, आगे से चुनाव उसी माध्यम से होना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने एक साक्षात्कार में कहा, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा देश भी ईवीएम का इस्तेमाल करने के बाद मतपत्र की तरफ लौट गया। चुनाव आयोग एवं सरकार को मतपत्र की तरफ लौटना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भले ही यह राजग के पक्ष में जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संदेह तो दूर हो।' जब मैं कानून मंत्री था तब इस संदेह को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। यह पूछे जाने पर कि क्या 52 सांसदों के साथ कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी तो 79 वर्षीय मोइली ने कहा, हम 52 की संख्या में भी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। 1984 में भाजपा के दो सांसद थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। अकेले राहुल ही बहुत मजबूत आवाज उठा सकते हैं। एक सवाल पर कहा, धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की विचारधारा धारा के मूल में रहेगी।

वीरप्पा मोइली फाइल

जेपी नड्डा : जेपी आंदोलन से निकल भाजपा के शीर्ष पद तक

जेएनएन, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से संबंध रखने वाले जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1975 में जयप्रकाश नारायण (जेपी) के आंदोलन से हुई थी। आंदोलन में भाग लेने के बाद वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में शामिल हो गए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का सफरनामा यूं रहा :-

- 16 वर्ष की उम्र में राजनीतिक सफर शुरू। बिहार में स्टूडेंट मूवमेंट में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
- 1977 में छात्र संघ चुनाव में पटना विश्वविद्यालय के सचिव चुने गए।
- 1982 में हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाकर भेजा गया।
- 1983-1984 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला से वकालत की।
- 1983 में पहली बार हुए केंद्रीय छात्र संघ (एससीए) चुनाव में एचपीयू में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने।
- 1986 से 1989 तक विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रहे।
- 1989 में केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की वजह से 45 दिन तक जेल में रहे।
- 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया।
- 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने।
- 1993 में पहली बार विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष चुने गए।
- 1998 में दोबारा चुनाव जीते और राज्य भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने।
- 2007 में राज्य भाजपा सरकार में वन, पर्यावरण एवं संसदीय मामलों के मंत्री रहे।
- 2011 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। दिल्ली में कामकाज संभाला।
- 2014 में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने।
- 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला और पार्टी की बड़ी जीत के नायक बने।

जीवन परिचय

पिता : डॉ. नारायण लाल नड्डा, **माता :** स्व. कृष्णा नड्डा, **जन्म तिथि :** दो दिसंबर, 1960, **जन्म स्थान :** पटना (बिहार), **विवाह :** 11 दिसंबर 1991, **पत्नी :** डॉ. मल्लिका नड्डा, **पुत्र :** हरीश और गिरीश, **स्थायी निवासी :** बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), **शिक्षा :** बीए, एलएलबी, **प्रारंभिक शिक्षा :** सेंट जेवियर, स्कूल, पटना, **स्नातक :** पटना कॉलेज, **एलएलबी :** एचपीयू शिमला

कुशल संगठनकर्ता हैं नड्डा

जेपी नड्डा को नया अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तभी से लगने लगी थीं, जब उन्हें मंत्रिमंडल से दूर रखा गया था। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के विश्वस्त माने जाते हैं। उनकी सांगठनिक कुशलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्हें न सिर्फ संगठन के कामकाज दिए जाते थे, बल्कि संसदीय बोर्ड में सचिव का प्रभार भी उन्हें ही दिया गया था।

नई दिल्ली में सोमवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने जेपी नड्डा का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

कांग्रेस के डाटा विश्लेषण विभाग से जुड़ी खबर बकवास : चक्रवर्ती

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : कांग्रेस डाटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने मीडिया में आई उस खबर को बकवास एवं अपमानजनक करार दिया जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने चुनाव नतीजे के संदर्भ में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को 'गुमराह' किया।

चक्रवर्ती ने एक बयान में कहा, 'हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के डाटा विश्लेषण विभाग की गतिविधियों के बारे में गपशप से जुड़े एक स्तंभ की मुझे जानकारी मिली है। इस स्तंभ की हर पंक्ति में कोई तथ्य नहीं है और पूरी तरह बकवास है।'

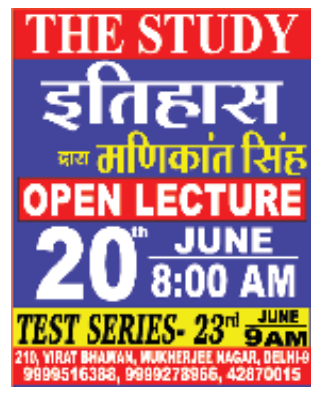

कह के रहेंगे माधव जोशी

नई योजना

केंद्र सरकार ने बेकार पड़ी जमीन पर हरियाली लाने के लिए पांच राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, अगले साढ़े तीन सालों में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य किया गया है तय

बेकार पड़ी वन भूमि पर फिर से उगेगा जंगल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर सरकार ने छेड़ी मुहिम
▸ देश की तकरीबन 30 फीसद भूमि है प्रभावित

देश की बेकार पड़ी लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर फिर से हरियाली रोपी जाएगी। सरकार ने इसे लेकर नए सिरे से पहल तेज की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इसे लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में बंजर भूमि पर फिर से जंगल लगाने का काम होगा। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब तीस फीसद हिस्सा बंजर या मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी समस्या से प्रभावित है, जिसमें बड़ा हिस्सा वन भूमि का है, जहां कभी पहले जंगल था।

विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस के मौके पर जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में जंगल तेजी से नष्ट हो रहा है। भारत सहित पूरी दुनिया इससे चिंतित है। यही वजह है कि भारत ने बगैर किसी दबाव के इससे निपटने के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ाया है। फिलहाल जिन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेकार पड़ी बंजर वन भूमि पर फिर से जंगल लगाने की तैयारी है, इनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, नगालैंड और कर्नाटक भी शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साढ़े तीन सालों में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल्द ही एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

जावड़ेकर ने कहा कि बंजर भूमि का क्षेत्रफल घटाने के उद्देश्य से ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। गौरतलब है कि जर्मनी के बोन में 2011 में हुए एक सम्मेलन में सबसे पहले मरुस्थलीकरण को लेकर दुनिया ने चिंता जाहिर की थी। साथ ही सभी देशों ने इस दिशा में मिलकर काम करने पर जोर दिया था। ज्ञात हो, देश के कई राज्यों में वन संपदा को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं क्योंकि जंगलों के कम होने के कारण आम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रकाश जावड़ेकर फाइल

मौसम के बदलाव पर विचार करने नोएडा में जुटेंगे दुनिया के 197 देश

मौसम में तेजी से आ रहे बदलावों पर चर्चा के लिए 2 से 14 सितंबर के बीच दुनिया के करीब 197 देशों का नोएडा में जमावड़ा होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि सीओपी-14 (कांफ्रेस आफ द पार्टीज) संगठन की यह 14 वीं बैठक होगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन होगा। इसमें दुनिया के 197 देशों के पांच हजार से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

193 करोड़ रुपये की 12 योजनाएं पूरी की गई हैं स्मार्ट सिटी में। इनमें भोपाल में 66 करोड़ की तीन, इंदौर में 34 करोड़ की पांच, जबलपुर में 68 करोड़ की दो और उज्जैन में 25 करोड़ रुपये की दो योजनाएं शामिल हैं। यह दावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने छह माह पूरे होने पर जारी उपलब्धियों की बुकलेट में किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 जून 2019

ममता को झटका, टीएमसी के 12 पार्षद और एक विधायक भाजपा में शामिल

पार्टी में टूट जारी ▶ उत्तर 24 परगना जिले में लगातार ढीली हो रही तृणमूल की पकड़

जिले की पांच नपा पर भाजपा का कब्जा, और बढ़ेगा दबदबा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट का सिलसिला जारी है। सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले के नोआपाड़ा से तृणमूल विधायक सुनिल सिंह गारुलिया नगरपालिका के 12 पार्षदों संग भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और बंगाल भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाजपा का झंडा थमाया। भाजपा में शामिल होने को लेकर सुनील सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास ध्येय का हिस्सा बनना चाहता था। लगे हाथ उन्होंने तृणमूल के सिंडीकेट राज और ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा।

मालूम हो कि सुनील सिंह बैरकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के रिश्तेदार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही अर्जुन सिंह तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। उनके सांसद निर्वाचित होने के बाद से ही सुनील सिंह के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके मद्देनजर तृणमूल ने सुनील को जिले में पार्टी की अहम जिम्मेदारी देते हुए उनका कद बढ़ाया था, लेकिन तृणमूल का यह पैतरा भी काम नहीं आया और वह सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। वहीं, सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई तृणमूल विधायक भाजपा में शामिल होंगे और आने वाले छह महीने में तृणमूल से सत्ता छिन जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अब तक जिले की पांच नगर पालिका पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, जबकि मंगलवार को बनगांव व आने वाले दिनों में टीटागढ़ समेत अन्य कई नपा पर भाजपा का कब्जा होगा। सुनील सिंह गारुलिया नगरपालिका के प्रधान भी हैं। इस नपा में कुल 21 पार्षद हैं, जिनमें एक कांग्रेस और एक फारवर्ड ब्लॉक से निर्वाचित हैं। अब जबकि 12 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं, गारुलिया नपा पर भी भाजपा का कब्जा होना लगभग तय है। कहा जा रहा है कि कुछ और पार्षद भाजपा में नाम लिखाने को तैयार हैं। इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के ही भाटपाड़ा, हालीशहर, नैहाटी नगरपालिका के पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से उक्त नपा पर भाजपा का कब्जा हो गया। हालांकि, नैहाटी नपा पर सत्तारूढ़ दल ने प्रशासक बैठा दिया है। खुद मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने जिले में सक्रियता बढ़ा दी है। वह लगातार जिले का दौरा कर रही हैं।

बीते महीने ही बैरकपुर संसदीय सीट के बीजपुर से तृणमूल विधायक व मुकुल रॉय के पुत्र शुभ्रांशु रॉय भाजपा में शामिल हुए थे। शुभ्रांशु के अलावा तृणमूल कांग्रेस के तुषारकांति भट्टाचार्य और माकपा के देवेंद्र नाथ रॉय समेत विभिन्न नपा से तृणमूल के करीब 50 पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए थे।

नई दिल्ली में सोमवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुनील सिंह सहित 12 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जागरण

सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा की मांग पर सुनवाई को हुआ तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोर्ट मंगलवार को करेगा जनहित याचिका पर सुनवाई
- याचिका में कोलकाता में डॉक्टर पर हमला करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की हड़ताल और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा दिलाए जाने की मांग पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। कोर्ट इस संबंध में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मी तैनात करने की मांग की। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तय करने की भी मांग की।

सोमवार को श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले को महत्वपूर्ण बताकर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की मंजूरी दे दी।

श्रीवास्तव की याचिका में हमले के विरोध में देशभर में हुई डॉक्टरों की हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए देश के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशभर के सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मी तैनात करे। साथ ही सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश और नियम तय किए जाएं।

याचिका में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में डॉक्टरों की हड़ताल से प्रभावित हुई स्वास्थ्य सेवाओं का भी मुद्दा उठाया गया है। यह याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई थी।

याचिका में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन का हवाला देते हुए डॉक्टरों पर होने वाले हमलों के आंकड़े दिए गए हैं, जिनमें यह भी बताया गया है कि ज्यादातर हमले अस्पताल के आपातकालीन विभाग में होते हैं और हमला करने वालों में ज्यादातर मरीजों के तीमारदार शामिल होते हैं।

जूनियर डॉक्टरों से बंगाल न छोड़ने की अपील

कोलकाता में सोमवार को जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक के दौरान सीएम ममता बनर्जी। एएनआइ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कोलकाता में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि आंदोलन करने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों से बंगाल छोड़कर नहीं जाने की भी अपील की। उन्होंने कहा, 'मैं जानती हूं कि आपको किस तरह से काम करना पड़ता है। राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों की आधारभूत संरचना को उन्नत करने के लिए तत्पर है। आप यहीं काम करें। बंगाल छोड़कर न जाएं। बंगाल में डॉक्टरों की कमी है। हमें डाक्टर नहीं मिल रहे। हमारी सरकार तो दूसरे राज्यों से भी यहां डॉक्टर लाने को तैयार है।'

पूरी बैठक के दौरान नर्म रवैया अख्तियार करने वाली ममता सिर्फ एक बार थोड़े तल्ख तेवर में दिखीं। उनसे जब एक जूनियर डॉक्टर ने ऐसी कोई भी घटना होने पर संबंधित अस्पताल जाने को कहा तो ममता ने दो-टूक कहा-'आपके कहने पर अस्पताल नहीं जाऊंगी। अपने समय के मुताबिक जाऊंगी।'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में स्वीकार किया कि घटना के दौरान पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा-'इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्पताल में दो ट्रक भरकर लोगों के घुसने के मामले की भी जांच चल रही है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई तो पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

दस लाख डॉक्टर रहे सांकेतिक हड़ताल पर : दूसरी तरफ जूनियर डाक्टरों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के बैनर तले देशभर में 10 लाख डॉक्टर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा। इस बीच पीपुल फॉर बेटर ट्रीटमेंट नामक संगठन ने डाक्टरों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर पुनर्विचार करेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशभर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य केंद्रों में मेडिकोज की सुरक्षा संबंधित केंद्रीय कानून तैयार करने के मुद्दे पर पुनर्विचार करेगी। अस्पतालों में हिंसा के खिलाफ डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए हैं।

हर्षवर्धन ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा से डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून लागू करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) द्वारा प्रस्तावित माडल कानून भी दिया है।

संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हम इस समस्या पर फिर से विचार करेंगे और देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। पूर्व में हमारे कानून के जानकारों ने विचार किया था।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा नहीं है और डॉक्टरों की सुरक्षा पर बहस की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा, 'अस्पताल में या उसके बाहर डॉक्टरों की कोई पिटाई नहीं करे। इससे कोई असहमत नहीं है।' संसद के वर्तमान सत्र में केंद्रीय कानून तैयार करने का कोई प्रस्ताव आ सकता है, के जवाब में हर्षवर्धन ने कहा, 'यह ऐसा नहीं जिसे रातों-रात तैयार कर लिया जाए। अध्ययन करने में समय लगेगा। मुझे पुराने रिकार्ड देखने होंगे। यह मुद्दा 2017 में भी उठा था और चर्चा हुई थी।'

कमलनाथ सरकार के छह माह पूरे होने पर प्रदेश कार्यालय में मना जश्न

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के छह महीने का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर सोमवार को जश्न मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता में कमलनाथ सरकार की छह महीने की उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की गई और नेताओं ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी।

प्रदेश कार्यालय में संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर, प्रशासन प्रभारी महामंत्री राजीव सिंह आदि की मौजूदगी में जश्न मनाया गया। वहीं, पत्रकारवार्ता में मीडिया विभाग की अध्यक्ष ओझा व उपाध्यक्ष अभय दुबे, पीसीसी अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने संबोधित करते हुए कमलनाथ सरकार की छह माह की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही प्रदेश सरकार के छह माह के कामों पर आधारित एक पुस्तिका 'बदलाव का पहला पड़ाव' का विमोचन किया। इसमें 22 सरकारी विभागों में छह माह की सरकार की कर्ज माफी योजना, वृद्धावस्था पेंशन व कन्या विवाह योजना राशि बढ़ोतरी जैसे कामों के बारे में बताया गया है।

शिअद ने हरियाणा में खेला भाजपा पर दबाव का कार्ड

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- पंजाब में 50 फीसद सीटें मांगने वाली भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब

हरियाणा में अब तक इनेलो का साथ देते आ रहे शिरोमणि अकाली दल ने अचानक भाजपा का हरियाणा में साथ देने का मन बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया। संसदीय चुनाव में भी उन्होंने भाजपा का साथ दिया था। हालांकि तब उनसे कोई सीट नहीं मांगी गई। सभी सीटें भाजपा ने ही लड़ीं, लेकिन संसदीय चुनाव के बाद अचानक पार्टी ने कोर कमेटी की मीटिंग में हरियाणा में चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार किया।

हरियाणा के प्रभारी व राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भूंदड़ ने हरियाणा के नेताओं के साथ मीटिंग करके भाजपा से 30 सीटें मांग लीं। इसके पीछे पार्टी ने दलील दी कि उनका कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा आदि में अच्छा आधार है। इस पंजाबी व सिख बाहुल इलाकों की सीटें उन्हें दी जानी चाहिए।

यह रणनीति क्यों अपनाई पार्टी ने : राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि अकाली दल ने यह रणनीति क्यों बनाई? 2019 के संसदीय चुनाव में अकाली-भाजपा गठबंधन ने 13 में से चार सीटें जीतीं, जिनमें दो पर अकाली दल ने और दो पर भाजपा ने कब्जा किया। अकाली दल दस सीटों पर लड़ीं और दो सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने तीन में से दो सीटें जीतीं। उसके बाद पूर्व प्रधान कमल शर्मा ने सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर दिया कि अब पार्टी विधानसभा चुनाव में पंजाब में 117 में सिर्फ 23 सीटों पर नहीं लड़ेगी, बल्कि 50 फीसदी सीटों की मांग करेगी। भाजपा का मुख्य फोकस कोर मालवा पर होगा, जिसमें लुधियाना जिला शामिल नहीं है।

कोर मीटिंग में भी उठा था मुद्दा : अकाली दल द्वारा सीटें ज्यादा लेने का मसला पिछले दिनों पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में भी उठा था। उसमें तय किया गया कि अब पार्टी 23 सीटें नहीं लेगी, बल्कि कम से कम 45 सीटों पर लड़ेगी। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने कह दिया कि वे अपना आधार मालवा में भी बढ़ाएं, ताकि अकाली दल के साथ नए सिरे से सीटों की हिस्सेदारी पर बात की जा सके। भाजपा के इस रुख को देखकर अकाली दल ने भी उसी तरह का दांव खेला है। पार्टी ने हरियाणा में 30 सीटें मांग ली हैं।

हरियाणा में इतनी सीटों पर अकाली दल ने कभी नहीं लड़ा है। इनेलो के साथ समझौता होने पर भी वे पार्टी को दो से तीन सीटें ही देते रहे हैं, लेकिन अब एक साथ 30 सीटें मांगना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गया। अकाली दल की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि पार्टी को इतनी सीटें मिलनी मुश्किल है, लेकिन भाजपा पंजाब में ज्यादा पांव न पसारे, ऐसा इसलिए किया गया है।

गुजरात राज्यसभा उपचुनाव पर कांग्रेस पहुंची कोर्ट

- दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए चुने जाने से ये दोनों सीटें खाली हुई हैं।

अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेशभाई धनानी द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर साथ-साथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

वकील वरुण चोपड़ा के जरिए दायर याचिका मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ के सामने रखी जा सकती है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा 15 जून को जारी प्रेस नोट में पांच जुलाई को दोनों सीटों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम बताया गया था। शाह के गांधीनगर और स्मृति के अमेठी लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं।

धनानी ने आयोग के आदेश को निरस्त करने तथा इसे असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि आयोग को गुजरात सहित सभी राज्यों की रिक्त सीटें भरने के लिए उपचुनाव और चुनाव साथ-साथ कराने का निर्देश दिया जाए।

कांग्रेस को क्या नुकसान ? : गुजरात की दोनों सीटों पर अगर एक साथ एक ही बैलट पेपर पर चुनाव हुए तो कांग्रेस को उसपर जीत मिल सकती है। वहीं विधायकों की संख्या के हिसाब से अगर चुनाव अलग-अलग बैलट पर होंगे तो जीत बीजेपी की होगी। संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए। एक ही बैलट पर चुनाव से उम्मीदवार एक ही वोट डाल पाएगा। इस स्थिति में कांग्रेस एक सीट आसानी से निकाल लेती क्योंकि उसके पास 75 विधायक हैं। हालांकि चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। इस तरह बीजेपी के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट करके दोनों उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में सांसद बने तीनों मंत्रियों के इस्तीफे हुए मंजूर, विभाग आवंटित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रहेगा महिला कल्याण एवं पर्यटन विभाग
- लक्ष्मीनारायण, सिद्धार्थनाथ, धर्मपाल और महाना के बीच बंटा विभाग

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सांसद बने तीनों मंत्रियों के इस्तीफे सोमवार को मंजूर कर लिए। योगी सरकार के पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य विभाग के मंत्री एसपी बघेल, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन विभाग की मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने सांसद बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं। महिला कल्याण एवं पर्यटन विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ही रखा है। लक्ष्मीनारायण चौधरी को पशुधन एवं मत्स्य विभाग, धर्मपाल सिंह को लघु सिंचाई विभाग और सिद्धार्थ नाथ सिंह को परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग, सतीश महाना को खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का कार्य प्रभार उनके वर्तमान कार्यप्रभार के साथ आवंटित किया है।

योगी आदित्यनाथ जागरण आर्काइव

उप चुनाव तक टल सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल : तीन मंत्रियों के सांसद चुने जाने और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर की बर्खास्तगी के बाद यह अटकलें तेज हो गई थीं कि मंत्रिमंडल में शीघ्र फेरबदल होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने वालों के विभाग दूसरे मंत्रियों को देकर यह संकेत दे दिया कि फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा। प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि अब उप चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होंगे।

विभागों के पुनर्गठन का इंतजार : केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी विभागों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नीति आयोग की गाइड लाइन के अनुरूप स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजय अग्रवाल की समिति ने पुनर्गठन के लिए अपनी रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही होनी है। इस संदर्भ में सिद्धार्थनाथ का कहना है कि मुख्यमंत्री जब चाहें इसे लागू कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री समेत अब 43 मंत्री : उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अब विभिन्न स्तर के कुल 43 मंत्री हैं। इनमें दो उपमुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री, नौ स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री और 13 राज्यमंत्री हैं। कोटे के मुताबिक सरकार में अभी 17 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं।

हरियाणा के श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों का हो गया कायाकल्प

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- कार्यकर्ता ने कहा-मेरे गांव का श्मशान घाट ठीक करा दो, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के करा दिए ठीक
- खर्च होने थे 750 करोड़, सरकारी खजाने से गए मात्र 150 करोड़ रुपये
- सीएसआर फंड और सामाजिक संगठनों से जुटाए 600 करोड़ रुपये

हरियाणा के गांव-देहात में बदहाल श्मशान घाट और कब्रिस्तानों के कायाकल्प की अलग ही कहानी है। यह कार्य कभी किसी सांसद या मंत्री-विधायक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के एजेंडे में नहीं रहा। यही वजह थी कि श्मशान घाट की ओर जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का बनाने की कभी कोई योजना नहीं बनी। दाह संस्कार के बाद हाथ-पैर धोने के लिए पानी, बारिश व धूप के बचाव के लिए शेड, बैठने के लिए बेंच, पेयजल और चहारदीवारी से अछूते इन श्मशान घाटों के कायाकल्प की पहल अगर किसी ने की तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इसका श्रेय जाता है।

दैनिक जागरण से बातचीत में मुख्यमंत्री बताते हैं कि एक बार एक कार्यकर्ता आया और बोला कि आज तक मैंने कोई काम नहीं कहा, लेकिन मेरे गांव की एक समस्या है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री से कहकर गांव का भला करा दो। मैंने पूछा कि काम क्या है तो बोला कि श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते कच्चे हैं। बरसात में वहां कीचड़ की स्थिति हो जाती है। शेड के अभाव में दाह संस्कार भी नहीं हो पाता। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। चहारदीवारी के अभाव में पशुओं का जमावड़ा रहता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता की बात समझते हुए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर को बुलाया। उनसे कहा कि प्रदेश में जितने भी श्मशान घाट और कब्रिस्तान हैं, उनकी सूची बनाकर पता कराओ कि उनके कायाकल्प पर कितनी राशि खर्च होगी। कार्यकर्ता अचंभित रह गया। सीएम से बोला, मैंने तो अपने गांव के श्मशान घाट व कब्रिस्तान के कायाकल्प का आग्रह किया था, लेकिन आप पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। बहरहाल, कुछ दिन बाद सीएम की टेबल पर रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, एक श्मशान घाट के कायाकल्प पर 25 से 30 लाख रुपये के खर्च का एस्टीमेट तैयार हुआ। पूरे प्रदेश के श्मशान घाट और कब्रिस्तानों के उद्धार के लिए 750 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव दिया गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की मीटिंग में इस रिपोर्ट को रखा और उनसे सुझाव लिए। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सामाजिक काम के लिए सामाजिक संगठनों तथा उद्योगपतियों की मदद ली जानी चाहिए। हर बड़ा उद्योगपति अपने शुद्ध लाभ का दो फीसद धन सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) फंड के लिए रखता है। अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों और उद्योगपतियों से संपर्क साधा। आप हैरान होंगे कि 600 करोड़ रुपये की मदद के प्रस्ताव आ गए।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार के खजाने से मात्र 150 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब पूरे प्रदेश में शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत श्मशान घाट और कब्रिस्तानों की हालत में सुधार का अभियान चल रहा है। कहीं स्थिति सुधर गई तो कहीं प्रक्रिया चल रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जागरण आर्काइव

> हमारी सरकार का जोर गांवों के विकास पर है। 10 हजार से अधिक आबादी वाले 126 गांव ऐसे चिन्हित किए गए, जहां सीवेज लाइन डलनी है। डेढ़ दर्जन गांवों में काम शुरू हो चुका। इस योजना के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये नाबार्ड से लिए हैं। श्मशान घाट और कब्रिस्तानों के कायाकल्प का प्रस्ताव हमारे सामने आया। एक गांव की बजाय हमने पूरे प्रदेश में इस योजना को अंजाम पर पहुंचाया। इस परियोजना पर साढ़े सात सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। कुछ इंतजाम सरकार ने किया और कुछ सामाजिक संगठनों व उद्यमियों ने किया। विकास का यह सिलसिला लगातार जारी है।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।**

रिपोर्ट कार्ड

छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा छह माह का रिपोर्ट कार्ड, रायपुर में कवासी व अनिला, अंबिकापुर में सिंहदेव ने गिनाई उपलब्धियां

खजाने से सबसे ज्यादा किसानों के लिए निकली राशि

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के छह माह पूरा होने पर मंत्रियों ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। छह जिला मुख्यालयों पर छह मंत्रियों और एक विधायक ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की बिंदुवार उपलब्धियां गिनाईं। सरकार के खजाने से सबसे ज्यादा 19 हजार 900 करोड़ रुपये किसानों के लिए निकले हैं। मंत्रियों ने कहा कि छह माह ज्यादा नहीं होते। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के 13 महीने तो योजनाएं बनाने में निकाल दिए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने छह महीने में ही अपने घोषणापत्र के ज्यादातर बड़े वादों को पूरा करके दिखाया है।

मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर, कवासी लखमा व अनिला भेंड़िया ने राजधानी, मोहम्मद अकबर ने कवर्धा, जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा, ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। वहीं, बस्तर में विधायक लखेश्वर बघेल ने पसरकार के कामकाज को बताया। मंत्रियों ने कहा कि किसानों की मदद से बनने वाली सरकार ने किसानों का पूरा ध्यान रखा है। व्यापक ऋण माफी योजना में 11 हजार करोड़, व्यवसायिक बैंकों का पांच हजार करोड़ कर्ज माफ, डिफाल्टर किसानों के ऋण माफी के लिए 600 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट और सिंचाई का 300 करोड़ कर्ज माफ किया गया। इस तरह सरकार का दावा है कि किसानों का कुल 16 हजार 900 करोड़ रुपये का कर्जमाफ किया गया है। इसके अलावा सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदकर किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपये डाले, वह अलग है। मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग की चिंता की है। प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, आदिवासियों, गरीबों, सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों, वृद्धजनों को पहली बार लग रहा है कि प्रदेश में अब उनकी सरकार है।

जकांछ ने कसा तंज : जनता कांग्रेस छतीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि सरकार ने किसानों का कर्जमाफ न करके, किसानों को ही साफ कर दिया है। बिजली बिल हाफ न करके, बिजली को हाफ कर दिया है। शराबबंदी न करके, छत्तीसगढ़ को शराब की मंडी बना दिया है। मृत्यु दर को 256 फीसद बढ़ाकर सरकारी अस्पतालों को मौत की फैक्ट्री बना दिया है। बंद कमरे में पांच खदानों का सौदा करके छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बना दिया है। पीड़ा बयां करने वालों पर राजद्रोह लगाकर छत्तीसगढ़ में गांधी की जगह गोडसे राज कायम कर दिया है।

सरकार ने ये गिनवाईं उपलब्धियां

- 19 लाख किसानों का 11 करोड़ व्यापक ऋण माफ
- व्यावसायिक बैंकों का किसानों का पांच हजार करोड़ कर्जमाफ
- किसानों के नॉनपरफार्मिंग खातों में 600 करोड़ का व्यय भार उठाया
- गरीबों को प्रति राशन कार्ड अब 35 किलो चावल दिया जा रहा
- पांच डिसमिल से छोटे भूखंडों की खरीदी-बिक्री से रोक हटी
- 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ
- रोजगार में मूल निवासियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट
- एनएमडीसी में ग्रुप सी व डी की भर्ती परीक्षा अब दंतेवाड़ा में होगी
- मुख्यमंत्री कन्या योजना की राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की
- दिव्यांगजनों के विवाह की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख की
- बस्तर में टाटा का उद्योग नहीं लगने पर आदिवासियों को 42 सौ एकड़ जमीन वापस
- तेंदूपत्ता मजदूरों को देश में सबसे ज्यादा 4000 रुपये मजदूरी दी जा रही।
- 15 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर
- कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर से चार गुना मुआवजे का प्रस्ताव पारित
- राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता पांच से बढ़ाकर नौ फीसद किया

2023 तक 9.4 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट डिजिटल रूप में किया जाएगा देश में। यह बात औद्योगिक संस्था एसोचैम और पीडब्ल्यूसी की एक अध्ययन रिपोर्ट में सामने आई है। अभी देश में 4.5 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट होता है।

हमारी सरकार नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री

20 फीसद राजनेता 80 फीसद समाजसेवी

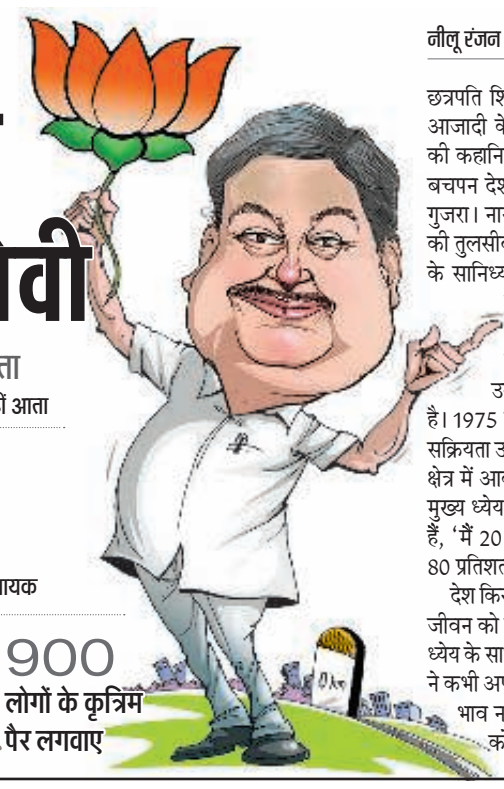

मां भानूताई गडकरी की व्यक्तित्व पर छाप

अंत्योदय प्रभावित करने वाली योजना

विफलता छुपाना नहीं आता

जीवन का ध्येय लोगों का जीवन कैसे बने सुगम

जिसकी कमी नहीं जोश और जज्बे की

उनका काम सबका दिल जीतने की कला

बेबाकी का विरोधी भी करते हैं तारीफ

मुकेश पसंदीदा गायक

1100 एकल विद्यालय चलाते हैं

8000 गरीबों के दिल का ऑपरेशन कराया

900 लोगों के कृत्रिम पैर लगवाए

नीलू रंजन • नई दिल्ली

छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और आजादी के आंदोलन में शहीद हुए लोगों की कहानियां सुनते हुए नितिन गडकरी का बचपन देश के लिए बड़े सपने संजोते हुए गुजरा। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलसीबाग शाखा में संघ के बड़े नेताओं के सानिध्य में इस सपने को दिशा मिली।

माता-पिता दोनों स्वयंसेवक थे, सो समाजसेवा का भाव घुट्टी में पिलाया गया, जिसका प्रभाव उनके हर काम में देखा जा सकता है। 1975 में लगे आपातकाल के खिलाफ सक्रियता उन्हें राजनीति की तरफ ले गई। इस क्षेत्र में आकर भी समाजसेवा को ही अपना मुख्य ध्येय बनाए रखा। खुद गडकरी कहते हैं, 'मैं 20 प्रतिशत राजनीति करता हूं और 80 प्रतिशत समाजसेवा करता हूं।'

देश किस तरह से आगे जाए और लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, इस एक ध्येय के साथ काम करने वाले नितिन गडकरी ने कभी अपने भीतर विफलता या निराशा का भाव नहीं आने दिया। वे कहते हैं, 'मुझे कोई निराशा आती नहीं और न ही मैं महत्वाकांक्षी हूं।' इसका उदाहरण साफतौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा का दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर उनके हाथ से फिसल गया। वह बहुत विचलित नहीं हुए। वे अपने काम के प्रति सजग रहते हैं और दी गई जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से निभाने का प्रयत्न करते हैं। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र में और फिर बाद में केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में उनके योगदान की प्रशंसा विरोधी भी करते नहीं थकते हैं।

नितिन गडकरी की मानें तो वे दीन दयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' से बहुत प्रभावित हैं। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण उनकी प्राथमिकता में है। हजारों किमी की हाईवे परियोजनाओं को लागू करने वाले नितिन गडकरी के अनुसार उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है, जब किसी को नौकरी मिल जाती है। किसी के दिल का ऑपरेशन हो जाता है। किसी गरीब आदमी को मकान मिल जाता है।

बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नितिन गडकरी गढ़चिरौली व अन्य जगहों पर 1100 एकल विद्यालय भी चलाते हैं। उन्होंने दिल की बीमारी से ग्रस्त 8000 गरीबों का मुफ्त ऑपरेशन कराया है। 850-900 लोगों को कृत्रिम पैर भी लगवाया। अन्नपूर्णा नाम से एक एयरकंडीशन रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जो 'नो प्रॉफिट नो लॉस' पर चलता है। किसानों की आत्महत्या से आहत गडकरी ने विदर्भ के इलाके में कई प्रकल्प शुरू किये। इनमें आज लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

नितिन गडकरी के जीवन व व्यक्तित्व पर उनकी मां भानूताई गडकरी का गहरा असर है। खुद गडकरी कहते हैं कि आज वे जो कुछ हैं अपनी मां की वजह से हैं। मां के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी होने के कारण गडकरी को अनुशासन और देशभक्ति की शिक्षा बचपन से ही मिली लेकिन इसको धार मिली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाकर। मैट्रिक पास करते ही वे आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। वे कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने उन्हें जीवन का दृष्टिकोण दिया। जिसमें यशवंत राव केलकर, बाल आप्टे, मदनदास देवी और सुधाकर भालेराव का अहम योगदान है।

नितिन गडकरी के पास अपने काम की वजह से सबका दिल जीतने की कला है। वे काम को काम के रूप में देखते हैं और जाति, धर्म, विचारधारा को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। यही कारण है कि विपक्षी भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वे अपनी बेबाकी के लिए भी उतने ही पसंद किये जाते हैं। अपनी विफलता को छुपाना उन्हें नहीं आता है। वे खुलेआम स्वीकार करते हैं कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम नहीं कर पाए और यह उनकी सबसे बड़ी विफलता है। पर उनकी एक खूबी यह भी यह भी वे कभी हार नहीं मानते हैं। जितनी बड़ी चुनौती होती है, उससे निपटने के लिए उनके पास जोश और जच्बा उससे भी बड़ा होता है। ऐसे वक्त में संगीत उन्हें बहुत भाता है और खासकर मुकेश।

राजनीति में शिखर तक पहुंचने, भाजपा का अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी राजनीति में उनका मन नहीं लगता है। 62 साल के हो चुके गडकरी कभी 60 साल की उम्र में राजनीति से सेवानिवृत्त होने का मन बना चुके थे। लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से ऐसा नहीं कर सके। उनके आदर्श पुरूष हैं नानाजी देशमुख। पर उनकी सार्वजनिक पहचान है एक बेबाक राजनीतिज्ञ की, जो बेहिचक कुछ भी कह सकते हैं, जिनके विचार क्रांतिकारी होते हैं और चौंकाते है।

झारखंड में एसपी के हत्यारों समेत छह बड़े नक्सलियों ने किया सरेंडर

बड़ी सफलता ▸ पुलिस से लूटे गए एके 47, इंसास, कार्बाइन, रायफल समेत कई हथियार जब्त

कुछ दिन सेंट्रल जेल में रखने के बाद उन्हें भेजा जाएगा हजारीबाग ओपेन जेल

जागरण संवाददाता, दुमका

झारखंड में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और जामा के थानेदार सदानंद सिंह की हत्या समेत कई बड़ी उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहे छह खूंखार नक्सलियों ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। झारखंड के संताल इलाके के इन इनामी और खूंखार नक्सलियों के सरेंडर को पुलिस बड़ी उपलब्धि और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। कुछ दिन सेंट्रल जेल में रखने के बाद उन्हें हजारीबाग ओपेन जेल भेजा जाएगा। सरेंडर करने के दौरान नक्सलियों ने एके 47, कार्बाइन, इंसास रायफल और पिस्टल दुमका एसपी को सौंपा। दो जुलाई 2013 को काठीकुंड में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या कर दी गई थी। 10 सितंबर 2010 को जामा के तत्कालीन थानेदार सदानंद सिंह की भी नक्सलियों ने हत्या की थी।

पीसी दी और किरण पर था पांच-पांच लाख का इनाम : सरेंडर करनेवाले नक्सलियों में संताल परगना का आतंक माने जाने वाले भाकपा माओवादी की जोनल कमांडर पीसी दी और खूंखार ताला दा की पत्नी सब जोनल कमांडर किरण उर्फ पक्कू टुडू के अलावा सुखलाल देहरी, सिद्धो, प्रेमशिला और भगत सिंह हेम्ब्रम शामिल हैं। इनमें पीसी दी और किरण पर सरकार ने पांच लाख का ईनाम घोषित कर रखा था, जबकि सुखलाल देहरी, सिद्धो और प्रेमशिला पर एक एक लाख का इनाम था।

माओवादियों ने पुलिस को जो हथियार सौंपे हैं, वो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों से छीने हुए हैं। एसपी ने कहा कि एके 47, इंसास, कार्बाइन, रायफल और पिस्टल की जांच के बाद पता चलेगा कि ये हथियार कब और किस वारदात में लूटे गए थे।

आतंक के एक अध्याय का हुआ अंत : डीआइजी : पीसी दी जैसी खूंखार माओवादी के सरेंडर करने पर डीआइजी राजकुमार लाकड़ा ने कहा कि दुमका के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। दुमका एसपी ने लंबे समय तक मशक्कत की। इसका नतीजा सामने है। माओवादियों के सरेंडर की पूरी प्रक्रिया में पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। माओवादियों तक संदेश गया है कि पुलिस सख्ती बरती है तो उतनी ही संवेदनशील भी है। वहीं एसपी वाई एस रमेश ने कहा कि एक दिन में माओवादी सरेंडर नहीं करते। 13 जनवरी को ताला दा की मौत के बाद से संताल परगना के माओवादियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू किया गया था। धीरे धीरे सभी लोग दस्ता से अलग होते गए। इनके परिवार के लोग पुलिस के संपर्क में थे।

झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सोमवार को दुमका में आत्मसमर्पण करते नक्सली। जागरण

नक्सलियों को दिए जाएंगे 80 लाख रुपये

समर्पण करने वाले सभी माओवादियों को झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति के तहत से कुल 80 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरेंडर करते वक्त माओवादियों को तत्काल एक-एक लाख रुपये दिए गए। अब बैंक खाते खुलवा कर उसमें बाकी राशि डाली जाएगी। एसपी वाइएस रमेश ने कहा कि जिन माओवादियों ने सरेंडर किया है, उनके परिवार की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उनकी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

हादसे में सीआइएसएफ उपनिरीक्षक समेत परिवार के छह लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून : सीआइएसएफ के उपनिरीक्षक समेत उनके परिवार के छह लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसमें उनकी पत्नी और बच्चे समेत अन्य लोग भी शामिल थे। देहरादून के सीमांत इलाके त्यूणी में उनका वाहन पांच सौ मीटर गहरी खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम काफी मशक्कत के बाद शवों को खाई से निकाल पाई। उप निरीक्षक हाल ही में छुट्टी पर आए थे। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे त्यूणी मार्ग पर यह दुर्घटना हुई। सीआइएसएफ में उप निरीक्षक पवन नेगी (32) पुत्र तेग सिंह बानपुर गांव स्थित अपने घर से पत्नी, बच्चों और कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ विकासनगर के लिए चले। सभी एक ही कार में सवार थे। अभी वह लगभग एक किलोमीटर सफर ही तय कर पाए थे कि उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई।

गांव वालों की सूचना पर राजस्व पुलिस का दल मौके पर पहुंचा, लेकिन खाई गहरी होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। आसपास के लोगों की मदद से शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार लोग खाई में छिटके मिले।

इनकी गई जान : हादसे में कार सवार दो बच्चों समेत सभी छह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में पवन नेगी के साथ ही उनकी पत्नी रश्मि नेगी (26), बेटी इशिका (4) विवाहित बहन सुमन तोमर (33) भांजा आरभ तोमर (5) (निवासी धर्मावाला विकासनगर) और बुआ मूर्ति देवी (52) (निवासी ग्राम सैंज तहसील जुब्बल जिला शिमला हिमाचल) शामिल हैं।

औली में शाही शादी पर हाई कोर्ट का पहरा, दो करोड़ जमा कराने का आदेश

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ बुग्याल क्षेत्र में हवाई उड़ानों पर फिलहाल रोक लगाई

▸ द. अफ्रीका में भारतीय मूल के कारोबारी गुप्ता बंधु के बच्चों की होनी है शादी

चमोली जिले में प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन औली में 200 करोड़ रुपये की शाही शादी की अनुमति देने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही इस शादी पर पहरा बैठा दिया है। हाई कोर्ट ने औली बुग्याल क्षेत्र में हवाई उड़ानों पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय नुकसान की आशंका को देखते हुए दो करोड़ जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार और बचाव पक्ष से स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर साफ-सफाई के एवज में धनराशि जमा नहीं की गई तो शादी पर विचार करना पड़ेगा। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को शादी की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं के परिवार के दो सदस्यों का रिश्ता दुबई निवासी कारोबारी परिवार के साथ हुआ है। कारोबारी अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बच्चों की यह शाही शादी औली में 18 से 22 जून तक होनी है। इधर, काशीपुर के अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शादी के लिए औली में दी गई अनुमति को चुनौती दी है। याचिका में शादी को पर्यावरण मानकों के साथ ही हाई कोर्ट के ही उस आदेश का उल्लंघन करार दिया गया, जिसमें बुग्यालों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार सुबह मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए दोपहर दो बजे तक सरकार से यह बताने को कहा कि क्या औली में पहले भी शादियां हुई हैं। दोपहर बाद कोर्ट ने मामले में फिर से सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शादी की मॉनिटरिंग करने और पर्यावरण को हुए नुकसान की रिपोर्ट मंगलवार को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

नगरपालिका से ली जा चुकी है अनुमति : इस इवेंट को करा रही कंपनी के वकील ने अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोजन के लिए नगरपालिका से अनुमति मिली हुई है। इसकी एवज में सरकार के खाते में 30 लाख भी जमा किए जा चुके हैं। याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

कोर्ट ने इन सवालों के मांगे हैं जवाब

- जिस क्षेत्र में शादी हो रही है वह बुग्याल है या नहीं?
- क्या इस क्षेत्र में पहले से हेलीपैड बना है?
- शादी के आयोजन की अनुमति किसने दी?

सरकारी पक्ष की दलील

- सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई विधि विरुद्ध नहीं की गई।
- आयोजन से किसी तरह का पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा है।
- इससे राज्य की लोक संस्कृति के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- शादी की अनुमति नगरपालिका जोशीमठ ने दी है।
- शादी के लिए सरकार ने कोई नया हेलीपैड नहीं बनाया है।

आतंकी हमले पर फैसले को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट

जागरण संवाददाता, अयोध्या

▸ आरएएफ-पीएसी की अतिरिक्त कंपनी अयोध्या पहुंची, सघन तलाशी

अधिगृहीत परिसर में पांच जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले पर मंगलवार को विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। इसे लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आरएएफ व पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मातहतों के साथ बैठक कर मंगलवार को प्रस्तावित फैसले के मद्देनजर सतर्क रहने की हिदायत दी।

अयोध्या व फैजाबाद में होटल, ढाबों, धर्मशाला, सराय व गेस्ट हाउस के संचालकों से भी निगरानी और सुरक्षा में सहयोग मांगा गया है। अधिगृहीत परिसर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। अधिगृहीत परिसर के भीतर सुरक्षा व निगरानी हर वक्त सख्त रहती है, फिर भी इसे और सतर्क रखने की हिदायत दी गई है।

पांच जुलाई 2005 अयोध्या की काली तारीख है। इसी दिन हथियारों से लैस आतंकियों ने अधिगृहीत परिसर पर हमला किया था। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर मुठभेड़ हुई। अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बलों ने पांच आंतकवादी ढेर कर दिए थे। इस आतंकी हमले में दो निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस हमले की जांच में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई और मददगारों में आसिफ इकबाल, मो. नसीम, मो. अजीज, शकील अहमद और डॉ. इरफान का नाम सामने आया। सभी को गिरफ्तार कर पहले अयोध्या जेल में रखा गया। इसके बाद 2006 में हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय कारागार नैनी में दाखिल कर दिया गया। मंगलवार को इस मुकदमे में फैसला आना है। एसपी सिटी अनिल सिंह व सीओ अयोध्या अमर सिंह को निगरानी की कमान सौंपी गई है।

एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि मंगलवार को फैसला आने की संभावना के मद्देनजर अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा व निगरानी बरती जा रही है। सुरक्षा प्वाइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। संवेदनशील इलाकों में आरएएफ व पीएसपी को लगातार गश्त का निर्देश दिया गया है।

चोकसी ने बांबे हाई कोर्ट से कहा, इलाज के लिए छोड़ा देश

मुंबई, प्रेट्र : करोड़ों के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के प्रमुख आरोपित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि उसने स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए देश छोड़ा है, न कि मुकदमे से बचने के लिए।

कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहे चोकसी ने कोर्ट में अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिये सोमवार को हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा है कि जनवरी 2018 में विदेश में अपने इलाज के लिए उसने भारत छोड़ा था। उसने कहा, 'मैंने संदिग्ध परिस्थितियों में देश नहीं छोड़ा।' चोकसी ने कहा है कि वह स्वास्थ्य की समस्या बनी रहने के कारण भारत नहीं लौट पा रहा है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की है। चोकसी ने इसे रद कराने के लिए हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगा रखी हैं। इन्हीं याचिकाओं के संबंध में उसने सोमवार को हलफनामा दाखिल किया। ईडी और सीबीआइ को पीएनबी के 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चोकसी और उसके रिश्तेदार नीरव मोदी की तलाश है। यह मामला वर्ष 2018 की शुरुआत में प्रकाश में आया था।

भगवान का दुग्ध स्नान...

पश्चिम बंगाल के हुगली के महेश में सोमवार को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दुग्ध और जल से स्नान अनुष्ठान के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यह दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन रथयात्रा है। एक सप्ताह तक चलने वाले रथयात्रा महोत्सव में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। एएनआइ

महिला को पीटने के आरोप में भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार

पंबा, प्रेट्र : गत वर्ष छह नवंबर को महोत्सव के दौरान सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए आई एक महिला पर हमले के मामले में पुलिस ने सोमवार को भाजपा केरल इकाई के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। वीवी राजेश इस मामले में 15वां आरोपित है।

भगवान अयप्पा मंदिर जब विशेष पूजा के लिए खुला था, तब अपने नाती के चूरुनु (भात भोज महोत्सव) के लिए जा रही 52 वर्षीय ललिता को एक समूह ने रोक दिया था। लोगों को लगा था कि ललिता रजस्वला आयुवर्ग की हैं। कुछ ने उन्हें पीटने की भी कोशिश की।

पुलिस ने बताया, 'कोर्ट ने राजेश को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया था। जब वह पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी दर्ज करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई।' इस मामले में राजेश के अलावा चार अन्य भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता नामजद हुए थे।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता का हवाला देते हुए सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे दी थी।

बढ़ेगी ताकत

30 देशों की सेनाएं करती हैं इस आधुनिक हथियार का इस्तेमाल, नक्सलियों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद

अमेरिकन रायफल से लैस होगी झारखंड पुलिस

दिलीप कुमार, रांची

अब झारखंड पुलिस के पास अमेरिकन आर्मी समेत 30 देशों की सेनाओं के इस्तेमाल में आने वाली बारेट स्निपर रायफल होगी। इस हथियार को अमेरिकन आर्मी ने कुवैत व इराक के अलावा अफगानिस्तान में उपयोग किया था। ऐसी 30 बारेट स्निपर रायफल खरीदने की स्वीकृति मिल गई है। इससे नक्सलियों पर नकेल कसने में झारखंड पुलिस को मदद मिलेगी। इसकी पहल शुरू कर दी गई है। सरकार ने हथियार खरीद के नाम पर पांच करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दे दी है।

खरीदे जाने वाले हथियारों में 500 एके-47 रायफल, 30 बारेट स्निपर रायफल, 110 अंडर बैरेल ग्रेनेड लांचर व 5000 ग्रेनेड शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड व पुलिस के कम्यूनिकेशन सेक्शन को भी अपडेट करने के लिए अलग से राशि आवंटित की गई है।

पुलिस को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में काम: पुलिस को हर मोर्चे पर अत्याधुनिक बनाने की पहल की जा रही है, ताकि झारखंड पुलिस हर मोर्चे पर बेखौफ होकर लड़ सके। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 23 करोड़ 34 लाख रुपये के प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है। इसमें केंद्र से 14 करोड़ रुपये केंद्र व नौ करोड़ 34 लाख रुपये राज्य सरकार के अंश हैं। केंद्र प्रायोजित स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआइएस) में 64 फोर्टिफायड पुलिस स्टेशन के लिए 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 188. 88 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इस राशि में केंद्र से 60 फीसद व राज्य से 40 फीसद राशि खर्च होती है। इस राशि से राज्य के एसटीएफ को सुदृढ़ करने, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच योजना व फोर्टिफायड पुलिस स्टेशन का निर्माण होना है। इसी राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति मिली है।

पुलिस आधुनिकीकरण के किस मद में कितनी राशि होगी खर्च

पांच करोड़ रुपये : 500 एके-47 रायफल, 30 बारेट स्निपर रायफल, 110 अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर व 5000 ग्रेनेड।

14 करोड़ रुपये : निर्माण पर खर्च होंगे। इनमें 12 जी प्लस थ्री यूएस क्वार्टर, 12 जी प्लस थ्री एलएस क्वार्टर व दो ब्लॉक असाल्ट ग्रुप हॉस्टल बनेंगे।

एक करोड़ 34 लाख 19 हजार रुपये : बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड पर खर्च होंगे। इसमें दो इंस्पेक्शन मिरर, तीन नन लाइनर जंक्शन डिटेक्टर, आठ एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, पांच पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, 10 सर्च किट, तीन इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, दो टूल किट, दस नन मैग्नेटिक टूल, तीन थर्मल कटर, सात रियल टाइम व्यूविंग सिस्टम, दस वाटर कैनन डिस्टूप्टर।

दो करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपये : सूचना उपकरण पर खर्च होंगे। 15 आइसैट फोन, 16 ट्रूप्स ट्रेकर, 55 जीपीएस, दो वायरलेस सेट, दो इंटरसेप्टर, पांच बैकपैक रीपीटर, पांच डायरेक्टर फाइंडर।

500 एके-47 व 30 बारेट स्निपर रायफल की होगी खरीद

5 करोड़ रुपये खर्च होंगे हथियारों की खरीद पर

बारेट स्निपर रायफल की खासियत

यह सेमी ऑटोमेटिक मशीनगन है। अमेरिकन आर्मी इसका उपयोग इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध में कर चुकी है। यह रायफल करीब 14 किलोग्राम की होती है। इसकी लंबाई 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें दस राउंड मैगजीन लगती है। इसकी मारक क्षमता 1800 मीटर तक है। यह टाइटेनियम धातु की बनी होती है।

नौवीं व 12वीं के छात्रों ने बैंक कैशियर से लूटे 24 लाख

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

▸ एक लुटेरे को भीड़ ने पकड़ा, दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ा

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सहकारी बैंक के कैशियर से नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार को दिनदहाड़े 24 लाख रुपये लूट लिए। वारदात के बाद भाग रहे लुटेरों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उससे कैश का बैग भी बरामद हो गया। दूसरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि तीसरा फरार है। पकड़े गए लुटेरों में एक 12वीं, जबकि दूसरा नौवीं कक्षा का छात्र है। तीनों की उम्र 18 साल से कम है।

गंगोह कस्बे में जिला सहकारी बैंक, तीतरों की शाखा नारायण सिंह बिल्डिंग में ऊपरी तल पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण बैंक बंद होने से पहले यहां का सारा कैश करीब 500 मीटर दूर स्थित जिला कोऑपरेटिव बैंक, गंगोह की शाखा में जमा कर दिया जाता है। सोमवार सुबह बैंक खुलने के बाद सहकारी बैंक कैशियर अमित वर्मा व अजय कुमार जिला कोऑपरेटिव बैंक, गंगोह की शाखा से 24 लाख रुपये लेकर अपनी शाखा की ओर चले। कैश का बैग अमित के हाथ में था। वह जैसे ही नारायण सिंह बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पहुंचे, पहले से मौजूद दो हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर बैग छीन लिया। बदमाशों का तीसरा साथी सड़क पर बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। अमित ने संघर्ष किया, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ पड़े। बदमाशों ने तमंचे से फायर करना चाहा, लेकिन गोली नहीं चली। करीब 500 मीटर दौड़ने के बाद भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। बाइक स्टार्ट कर खड़ा लुटेरा कुछ देर बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तीसरा लुटेरा फरार हो गया। लुटेरों से 24 लाख रुपये से भरा बैग बरामद हुआ। एसपी देहात विद्या सागर मिश्र ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे 12वीं व नौवीं के छात्र हैं। तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है।

3 भालुओं की मौत हो गई छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आंधी से गिरे बिजली के तार से करंट लगने पर। घटना के बाद किसी ने मादा भालू के नाखून और दांत निकाल लिए। वन विभाग की टीम ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 जून 2019

बिहार में लू का कहर जारी, 64 और ने दम तोड़ा

प्रकोप ▸ अब तक 242 की गई जान, मचा हड़कंप

गया में आठ, नवादा में 10, सासाराम में 17, औरंगाबाद में पांच लोग लू के शिकार

जागरण टीम, गया

बिहार में लू से होने वाली मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। सोमवार को भी सूबे में 64 की मौत हो गई। गया में आठ, नवादा में 10, सासाराम में 17, औरंगाबाद में पांच, समस्तीपुर में तीन, मुंगेर में पांच और नालंदा, हाजीपुर, छपरा, बेगूसराय, बक्सर व अरवल में 16 की जान गई। शनिवार से बिहार में 242 की मौत हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मची हुई है। मौत के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई मौतें हुई हैं, जिनका अस्पताल में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन स्थानीय मुखिया आदि उसकी पुष्टि कर रहे हैं।

जांच कर दिया जाएगा मुआवजा : बिहार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मंगल पांडेय ने सोमवार को औरंगाबाद के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीजों की देखरेख में कोई कसर बाकी नहीं रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मरीजों की मौत प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं है, उसके लिए गठित कमिटी जांच कर रिपोर्ट देगी। इसके बाद उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक लू से 34 लोगों की मौत में सभी के परिजनों को चार-चार लाख की मुआवजा राशि दे दी गई है। जो इस सूची से छूटे हुए हैं, उसके लिए गठित टीम जांच के बाद मुआवजा की अनुशंसा करेगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी।

11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे बाजार : बिहार में अगले तीन दिन लू का कहर जारी रहने की आशंका है। गर्मी के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 22 जून तक सूबे के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद रखने का निर्देश दिया है। निजी स्कूल भी इसमें शामिल हैं। एहतियात के तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि दक्षिण बिहार के प्रभावित जिलों में सभी बाजार सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेंगे। पटना के बाजार को फिलहाल इस आदेश से अलग रखा गया है। संपूर्ण सूबे में निर्माण कार्य सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेंगे। दिन के समय में चल रही गर्म हवाओं से लोग अचानक हीटस्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। इसके चलते सरकार ने यह कदम उठाए हैं।

झारखंड में पांच की मौत स्कूल में बच्चे बेहोश

जेएनएन, रांची : झारखंड में लू लगने से सोमवार को पलामू में तीन व कोडरमा में एक और दुमका में एक की मौत हो गई। भीषण गर्मी और लू से पाकुड़ में तीन तथा हरिणडांगा में दो बच्चे क्लास में ही बेहोश होकर गिर पड़े।

बिहार में एईएस से पांच और बच्चों की मौत, 48 भर्ती

जासं, मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) बेकाबू हो रहा है। मरनेवालों और पीड़ितों के अस्पताल आने का सिलसिला थम नहीं रहा। डॉक्टरों की टीम बीमारी के आगे असहाय नजर आ रही। सोमवार को पांच और बच्चों की मौत हो गई। इनमें तीन का एसकेएमसीएच और दो का केजरीवाल अस्पताल में इलाज चल रहा था। भीषण गर्मी और उमस के बीच 48 नए मरीजों को इलाज के लिए लाया गया। एसकेएमसीएच में 42 और केजरीवाल में छह मरीजों को भर्ती कराया गया है। इनमें आधा दर्जन से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही। एसकेएमसीएच और केजरीवाल मिलाकर अब तक 116 बच्चों की मौत हो चुकी है। जबकि 395 बच्चों को पीएचसी से लेकर एसकेएमसीएच तक में भर्ती कराया जा चुका है। वहीं अस्पताल प्रशासन की मानें तो अब तक 309 बच्चों को ही भर्ती किया गया है। इसमें सौ से अधिक बच्चों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मंगलवार को भी 40 बच्चों को स्वास्थ्य जांच के बाद छुट्टी देने की उम्मीद है।

केंद्रीय व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद : एईएस से हो रही बच्चों की मौत मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को आरोपित किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख मुकर्रर की है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

मानवाधिकार आयोग का बिहार व केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एईएस से बच्चों की मौत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से मरने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या का स्वतः संज्ञान लिया है।' आयोग ने बयान जारी कर बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती एईएस से पीड़ित बच्चे। बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल भी फुल हो गए हैं। मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेट्र

डॉ. गीता की गिरफ्तारी के आश्वासन पर रोहतक पीजीआइ में हड़ताल खत्म

जागरण संवाददाता, रोहतक : पीजीआइएमएस में पीजी डॉ. ओमकार की आत्महत्या के बाद से चल रही पीजी डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार देर रात डॉ. गीता गठवाला की गिरफ्तारी समेत अन्य मांगों को मानने के आश्वासन के बाद खत्म हो गई। कुलपति डा. ओपी कालरा के साथ करीब तीन घंटे चली वार्ता में मांगों पर सहमति बनी।

पिछले सप्ताह पीजी डॉ. ओमकार ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से गुस्साए पीजी डाक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। उन्होंने पीडियाट्रिक विभाग की अध्यक्ष डॉ. गीता गठवाला पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। साथ ही बहन की शादी के लिए भी डॉ. ओमकार को छुट्टी नहीं देने की बात कही थी। डॉ. गीता के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किए जाने के बाद पीजीआइएमएस प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया था। मगर हड़ताली डॉक्टर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। उधर, डा. गठवाला ने भी घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 21 डाक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

इन प्रमुख मांगों का दिया आश्वासन

- डॉक्टरों की सुविधा के लिए सात सदस्यीय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का गठन होगा
- तनाव में रहने वाले डॉक्टरों के लिए काउंसिलिंग सेल बनाई जाएगी, जो हर माह छात्रों की समस्याएं जानेगी
- डाक्टरों से 24 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाएगी। अगले दिन हर हाल में उसे ऑफ दिया जाएगा।
- डाक्टरों पर दर्ज हुए केस को खत्म कराने के लिए भी प्रशासन पूरा सहयोग करेगा।

न्यूज गैलरी

पाक गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल का जवान घायल

पुंछ : पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाक गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। विश्वकप में गत रविवार को एक तरफ भारत-पाक के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था और दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पुंछ के किरनी सेक्टर में गोलाबारी की रही थी। इस गोलाबारी में तीन लोग घायल हो गए। इसके बाद रात को पाकिस्तान टीम के मैच हारने के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने सोमवार तड़के तीन बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में मोर्टार दागने के साथ भारी गोलीबारी शुरू कर दिया। इस गोलाबारी में अग्रिम चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल का जवान संदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। (जासं)

हत्या आरोपित दो माकपा नेताओं को केरल हाई कोर्ट से झटका

कोच्चि : केरल हाई कोर्ट के एक फैसले से राज्य में सत्तारूढ़ माकपा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस हत्याकांड की सुनवाई कन्नूर से कोच्चि स्थित सीबीआइ कोर्ट को स्थानांतरित कर दी है, जिसमें माकपा के दो बड़े नेता नामजद हैं। फरवरी 2012 में हुए अब्दुल शुकूर हत्याकांड में माकपा के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन व युवा विधायक टीवी राजेश नामजद हैं। सीबीआइ ने फरवरी में ही दोनों नेताओं के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया है। हाई कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को तेल्लिचेरी कोर्ट से कोच्चि स्थित सीबीआइ कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जयराजन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दोनों नेताओं को अगस्त 2012 में गिरफ्तार किया गया था। (आइएएनएस)

उप्र के बागपत में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, गिरफ्तार

बागपत : नेशनल शूटर से छेड़छाड़ करने और विरोध पर उसके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उप्र के बागपत स्थित बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वह निशानेबाजी का अभ्यास करने रेंज पर जाती थी। एक मनचला उसके साथ छेड़छाड़ करता था। परेशान होकर उसने गांव छोड़ दिया और मेरठ में अभ्यास करने लगी। वह तीन दिन पहले मेरठ से गांव में आई, तो आरोपित ने उसके साथ फिर छेड़छाड़ कर दी। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने आरोपित से ऐसा न करने के लिए कहा तो उसने पीड़िता के पिता की पिटाई कर दी। आरोपित ने उसके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। (जासं)

भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल 11 पुलिसकर्मी बर्खास्त

पटियाला : भ्रष्टाचार व नशे के खिलाफ शुरू की गई पंजाब सरकार की विशेष मुहिम के तहत पटियाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे व भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में संलिप्त पटियाला पुलिस के 11 मुलाजिमों की सेवाएं खत्म कर दी गईं हैं। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पांच सहायक थानेदार, एक महिला थानेदार, तीन हेड कांस्टेबल व दो कांस्टेबल शामिल हैं। एसएसपी मंदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि विभिन्न मामलों में इन पुलिस मुलाजिमों की शमूलियत सामने आने के कारण इनको गिरफ्तार कर विभागीय जांच की गई। जांच में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उनकी सेवाएं खत्म कर दी गईं। सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। (जासं)

अनंतनाग में मुठभेड़, आतंकी ढेर, मेजर शहीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- दो कैप्टन रैंक के अधिकारियों सहित चार सैन्यकर्मी घायल
- मेरठ निवासी केतन शर्मा के रूप में हुई शहीद की पहचान
- करीब 12 घंटे चली भीषण मुठभेड़, आतंकी ठिकाना तबाह
- भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद

मेजर केतन। फाइल फोटो

दक्षिण कश्मीर के बड़ूरा (अनंतनाग) में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच करीब 12 घंटे चली मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकी मारा गया। इस दौरान एक मेजर भी शहीद हो गए। जबकि चार अन्य सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में दो कैप्टन रैंक के अधिकारी हैं। मुठभेड़ में आतंकी ठिकाना बना मकान पूरी तरह तबाह हो गया है। शहीद की पहचान (29) मेजर केतन शर्मा पुत्र रविंद्र शर्मा, निवासी श्रद्धापुरी सेक्टर चार, कंकरखेड़ा, मेरठ के रूप में हुई है। मुठभेड़स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है।

जानकारी के अनुसार, सुबह पुलिस को सूचना मिली कि अनंतनाग के अच्छाबल के बड़ूरा में तीन से चार आतंकी अपने किसी संपर्क सूत्र के पास रुके हुए हैं। इसका पता चलते ही सेना की 19 आरआर, राज्य पुलिस विशेष अभियान दल (एसओजी) और सीआरपीएफ के एक संयुक्त कार्यदल ने अभियान चलाया। सुबह करीब सात बजे जब जवान एक मकान के पास पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में करीब सवा आठ बजे 15 मिनट के लिए आतंकियों की तरफ से गोलीबारी बंद हुई। इस दौरान जवानों ने जैसे ही मकान में दाखिल होने का प्रयास किया, आतंकियों ने दोबारा गोली चला दी। इसमें एक मेजर समेत तीन सैन्यकर्मी जख्मी हो गए। सुबह दस बजे एक बार फिर फायरिंग कुछ देर के लिए थमी, तो सुरक्षाबलों ने एक से दो आतंकियों को एक जगह जमीन पर गिरे देखा। लेकिन जैसे ही जवानों ने फायरिंग रोकी आतंकी तुरंत उठे और फायरिंग शुरू कर दी। दोपहर करीब दो बजे के करीब आतंकी ठिकाना बने मकान में एक जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इस दौरान कुछ जवान भी जख्मी हो गए। हालांकि शाम छह बजे तक सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया और करीब साढ़े छह बजे मुठभेड़ समाप्ति का एलान कर दिया। इस बीच, अस्पताल में उपचाराधीन एक मेजर शहीद हो गए। वहीं, अन्य चार की हालत भी गंभीर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अपना ठिकाना 14 साल पहले मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के तत्कालीन डिवीजनल कमांडर शब्बीर बदूड़ी के मकान में बनाया था। दावा किया जाता है कि बदूड़ी का बेटा आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर है। हालांकि पुलिस ने अन्य आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने का दावा किया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों की मानें तो वहां छिपे अन्य आतंकी भाग निकले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मकान के मलबे के नीचे किसी आतंकी के शव होने की बात से अभी इन्कार नहीं किया जा सकता।

शहीद के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुठभेड़ में शहीद मेरठ निवासी मेजर केतन शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। योगी ने शहीद के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। योगी ने कहा कि शहीद के परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा मेजर केतन शर्मा की स्मृति में मेरठ की एक सड़क का नामकरण किया जाएगा।

निकाह कर प्रोटेक्शन लेने पहुंची युवती को उठा ले गए कार सवार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

यमुनानगर के हमीदा निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की बेटी से निकाह कर सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे युवक से मारपीट कर कार सवार लोग युवती को जबरन साथ ले गए। सूत्रों के अनुसार सड़क पर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक नबील को अपने साथ थाने ले गई। उसने बताया कि वह युवती के साथ चंडीगढ़ आया था जिसे उसके परिजन जबरन गाड़ी में लेकर चले गए।

बता दें कि युवक-युवती निकाह के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन मांगने सोमवार को चंडीगढ़ आए थे। सूत्रों के अनुसार सुबह 7.40 बजे एक राहगीर ने सेक्टर-21-22 की सड़क पर मारपीट होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां युवक नबील मिला। पुलिस उसे सेक्टर-19 थाने ले गई। नबील ने पुलिस को बताया कि वह यमुनानगर के वार्ड नंबर 13 खुड्डा कालोनी का रहने वाला है। वह एक युवती के साथ चंडीगढ़ घूमने आया था। सुबह करीब 7.30 बजे जब वे सेक्टर-21 स्थित एक पार्क के पास पहुंचे तो हरियाणा नंबर की एक कार सामने आकर रुकी। कार से युवती के दो परिजन उतरे और उसे जबरन साथ ले जाने लगे। उसने विरोध किया तो परिजन उसे धक्का देकर युवती को लेकर चले गए। नबील ने पुलिस को लिखकर दिया कि वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता। सूत्रों के अनुसार उसके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं बरामद हुआ है। संघ कार्यकर्ता की बेटी 10 जून को लापता हो गई थी। इस पर नबील के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया था। इसी बीच हाई कोर्ट में युवती की तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन के लिए याचिका लगाई गई। उसने कोर्ट को बताया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और नबील के साथ उसका निकाह 10 जून को पिंजौर में मौलाना शकील अहमद ने कराया है।

> एक वेंडर का फोन आया था। उसने बताया कि एक बुर्का पहने हुए लड़की किसी लड़के संग पैदल जा रही थी। लड़की को कार सवार 4 या 5 लोग जबरन गाड़ी में बैठा ले गए। वेंडर के बयान पर केस दर्ज किया गया है।
> **चरणजीत सिंह विर्क, डीएसपी एंड पीआरओ।**

पहले कुबूला हत्या का जुर्म, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान

जागरण संवाददाता, बिजनौर

हत्या के बाद आमतौर पर रंजिश का सिलसिला आगे बढ़ता है लेकिन यह मामला उससे अलग है। हत्यारोपित ने भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। लेकिन इससे पहले प्रायश्चित करते हुए न सिर्फ हत्या के जुर्म को कुबूल किया, बल्कि अपना मकान भी मृतक के बच्चों को देने की बात कही। उसने सुसाइड नोट में खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हुए लिखा है कि-मैं सबकी नजरों में गिर चुका हूं, इसलिए अब जीना नहीं चाहता। मौत मेरे गुनाहों की सजा है।

सोमवार सुबह एक युवक उप्र के बिजनौर स्थित चंदक रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कट गया। उसकी शिनाख्त एजाज (38) निवासी ग्राम बुडगरा थाना किरतपुर के रूप में हुई। उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला। दरअसल, नौ जून की रात ग्राम बुडगरा निवासी अनीस की हत्या हो गई थी, जिसमें एजाज मुख्य आरोपित था। पुलिस ने 13 जून को हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए अनीस के साढ़ू शबनूर उर्फ शब्बू निवासी ग्राम कनकपुर थाना नजीबाबाद व उसके एक दोस्त रईस को जेल भेजा था। एजाज वांछित था। बताया जाता है कि एजाज सऊदी अरब में काम करता था।

ये है सुसाइड नोट : सुसाइड नोट में एजाज ने अनीस की हत्या की बात कुबूलते हुए लिखा है कि उसने ही किसी बात को लेकर अनीस को कांच की बोतल मारी थी। इसमें अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। इस गुनाह की सजा मौत है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इस केस में जो भी फंसे हैं, वे सब बेगुनाह हैं। मैं हर किसी की नजरों से गिर गया हूं। इसलिए अब जीना नहीं चाहता। लिखा है कि उसकी मौत के बाद उसका घर अनीस के बच्चों को दे दिया जाए।

> मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग का परीक्षण कराया जाएगा। जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों को हत्या के केस में शामिल किया जाएगा।
> **- लक्ष्मी निवास मिश्र, एसपी सिटी।**

अभिनेता करण ओबेरॉय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार

मुंबई, आइएएनएस : टीवी अभिनेता व गायक करण ओबेरॉय के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। पुलिस ने ओबेरॉय पर दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद छह मई को ओबेरॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, बांबे हाई कोर्ट ने उन्हें सात जून को जमानत दे दी थी। डीसीपी मंजूनाथ ने महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ओबेरॉय के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और 25 मई को खुद पर नियोजित तरीके से हमला कराने के मामले में महिला को ओशिवारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने दावा किया था कि 25 मई को बाइक सवार लोगों ने उस पर हमला किया था। हमलावरों ने ओबेरॉय के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट वापस लेने अथवा तेजाब हमला करने की चेतावनी दी थी। दो दिन बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें एक महिला के वकील का रिश्तेदार था। दोनों ने स्वीकार किया था कि हमला पूर्व नियोजित था।

....और यूं 'शांत' हो गया जादूगर 'चंचल'

जागरण संवाददाता, हावड़ा

- रविवार को गंगा में खतरनाक करतब दिखाने के दौरान हुए थेलापता
- 30 घंटे से भी ज्यादा चले तलाशी अभियान के बाद मिला शव

खतरनाक करतब दिखाने की एक दुस्साहसिक कोशिश का आखिरकार बेहद दुखःद अंत हुआ। करतब दिखाने के दौरान गंगा नदी के जल में गायब हुए जादूगर चंचल लाहिरी की पानी में डूबकर मौत हो गई है। 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक चले तलाशी अभियान के बाद सोमवार शाम को हावड़ा के रामकृष्णपुर गंगा घाट से उनका शव बरामद किया गया। आपदा प्रबंधन टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद उनके शव को नदी से ढूंढ निकाला।

बचपन से ही जादू के प्रति था लगाव : चंचल लाहिरी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर स्थित सुभाषग्राम इलाके में रहते थे। परिवार में मां, पत्नी और एक बेटा है। जादू के प्रति उनका यह लगाव ही था कि कभी आंखों पर पट्टी बांधकर बस चलाना तो कभी नदी से बंधे हाथ-पैर खोल कर सकुशल बाहर निकल आना, इस प्रकार के कई खतरनाक कारनामे वह पहले भी कर चुके हैं। 1998 में बक्से में खुद को बंद कर नदी के जल से वह सकुशल बाहर निकल आए थे। इस कारनामे ने उन्हें ना केवल राज्य बल्कि पूरे देश में ख्याति दिलाई थी। उन्हें मिली देशव्यापी पहचान के बूते वह देश के विभिन्न हिस्सों में जादू का शो करने लगे थे।

यह है मामला : जादू को लेकर लोगों में कम होती रुचि को फिर से जगाने की एक कोशिश के तहत जादूगर चंचल ने नदी के जल में फिर से एक बार उस खतरनाक करतब को दुहराने की ठानी थी, जिसे वह पहले भी दिखा चुके थे। रविवार को हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे व गंगा नदी के बीच, इस करतब को दिखाने की योजना बनी। एक जलयान (वाटर वेसेल) पर जादूगर चंचल और उनके सहयोगी सवार थे। वहीं दूसरे जलयान में एक अन्य टीम थी, जो इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद करने में जुटी थी। करतब के अनुसार हाथ-पैर बंधे हालत में जल के अंदर उतरने के बाद उन्हें सकुशल बाहर आना था।

चंचल के सहयोगियों ने लोहे की जंजीर व मोटी रस्सी से उनके हाथ-पैर बांध दिए। लंबी जंजीर से उनके पूरे शरीर को बांधने के बाद दो तालें जड़ दिए गए। फिर क्रेन की मदद से रस्सी के सहारे उन्हें गंगा नदी के जल में उतारा गया।

नदी के जल में अंदर जाने के बाद लगा कि वह थोड़ी ही देर में जल से बाहर दिखाई देंगे। हालांकि 10 मिनट बीत जाने पर वहां मौजूद लोगों की चिंता बढ़ने लगी। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पहले रिवर पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी। फिर आपदा प्रबंधन टीम चंचल को जल में तलाश करने लगी। रविवार देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिला था। अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान को बीच में ही रोक देना पड़ा था। सोमवार को फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया।

छत्तीसगढ़ में आरएसएस के कार्यक्रम से एक दिन पहले सभाकक्ष देने से इन्कार

नईदुनिया, रायपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के व्याख्यान के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जलसंसाधन विभाग ने सभाकक्ष देने से इन्कार कर दिया है। कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले विभाग के अधिकारियों ने आवंटन रद होने की जानकारी संघ पदाधिकारियों को दी। तब तक संघ की ओर से कार्ड बांट दिए गए थे। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इशारे पर आवंटन रद करने का आरोप लगाया है।

संघ के सुदर्शन प्रेरणा मंच की ओर से बिलासपुर में 18 जून और रायपुर में 19 जून को विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के व्याख्यान का आयोजन किया जाना है। बिलासपुर में जलसंसाधन विभाग के सभागार और रायपुर में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में आयोजन तय किया गया था। कलेक्टर बिलासपुर संजय अलंग ने जलसंसाधन विभाग की ओर से आवंटन रद करने की जानकारी से अनिभिज्ञता जाहिर की। अलंग ने कहा कि जलसंसाधन विभाग के अधिकारी ने सभाकक्ष आवंटित करने के बाद अचानक क्यों रद किया, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। अफसर से बात करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

वहीं, सुरदर्शन प्रेरणा मंच के संयोजक डॉ.प्रफुल्ल शर्मा ने कहा कि आवंटन रद करके विभाग क्या संदेश देना चाहता है, यह सब समझ में आ रहा है। यह सीधा-सीधा विचारों की स्वतंत्रता पर हमला है। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही। राष्ट्रीय विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ को पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है। यहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति निर्मित करने की कोशिश हो रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, रायपुर में कार्यक्रम संयोजक शशांक शर्मा ने कहा कि बिलासपुर का कार्यक्रम अचानक आला अधिकारियों के निर्देश पर रद कर दिया गया। यह पूरी तरह से गलत है। अब कार्यक्रम बिलासपुर के सरस्वती शिशु मंदिर तिलक नगर में होगा।

कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार आवंटन रद : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहली बार संघ के कार्यक्रम के लिए आवंटित सरकारी सभागार को रद किया गया है। जलसंसाधन विभाग के ईई ने पत्र जारी कर आयोजन समिति को आवंटन रद करने के संबंध में जानकारी दी। मंच के पदाधिकारियों ने 29 मई को जलसंसाधन विभाग खारंग डिवीजन के ईई को पत्र लिखकर प्रार्थना सभा को कार्यक्रम के लिए आवंटित करने की मांग की थी। विभाग ने प्रेरणा मंच को सभाकक्ष आवंटित करने के साथ में स्वीकृति भी जारी कर दी थी।

इस विषय पर होने वाली थी व्याख्यानमाला

18 जून को मंच के बैनर तले भारतीय संविधान एवं हिंदुत्व विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाना था। प्रमुख वक्ता के रूप में प्रबुद्ध राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुमार को आमंत्रित किया गया है।

पुलिस के सामने सास ससुर व देवर ने कर दी महिला की हत्या

जागरण संवाददाता, मनीमाजरा (चंडीगढ़) : इंदिरा कॉलोनी में सोमवार शाम ससुर, सास और देवर ने बहू को पहले कैंची से लहूलुहान किया और फिर बचाने पहुंची पुलिस टीम के सामने शर्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। तीनों आरोपितों को मौके पर ही दबोच लिया गया।

सोमवार शाम करीब 5.28 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी के मकान नंबर-1315 के दूसरी मंजिल के कमरे में 35 वर्षीय ललिता के साथ परिवार के तीन लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस पहुंची तो देखा कि तीनों आरोपित शर्ट से महिला का गला घोंट रहे थे। ललिता का पति से तलाक का मामला चल रहा है। आयेदिन झगड़े के कारण वह पहली मंजिल से हटकर दूसरी मंजिल पर रहने लगी थी। सिलाई का काम कर गुजारा करती थी। छह साल पहले उसने देवर मुकेश पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद मुकेश परिवार से अलग होकर पिंजौर में रहने चला गया था। मुकेश पेशे से फोटोग्राफर है जबकि मृतका का पति मोहिंदर केबल इंजीनियर का काम करता है। उसके दो बेटे हैं, जो दादा-दादी के साथ रहते हैं।

सिख रेफरेंस लाइब्रेरी मामले की जांच करेगी उच्च स्तरीय कमेटी

जागरण संवाददाता, अमृतसर

- एसजीपीसी के दो पूर्व अध्यक्ष भी जांच कमेटी में शामिल
- 1984 से अब तक का रिकॉर्ड चेक कर जल्द रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी
- अगर आरोप साबित न हुए तो एसजीपीसी मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई भी करेगी

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसपीजीसी) ने सिख रेफरेंस लाइब्रेरी के मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। एसजीपीसी अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल की ओर से गठित कमेटी में पांच सदस्य होंगे। इनमें एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्षों प्रो. किरपाल सिंह बडूंगर व बीबी जागीर कौर के अलावा एसजीपीसी के पूर्व सचिव दिलमेघ सिंह, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से डॉ. अमर सिंह और एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह शामिल हैं। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

उल्लेखनीय है कि जून 1984 में श्री हरिमंदिर साहिब पर समय की सरकार की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान सिख कौम का साहित्यिक खजाना सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। मीडिया में सामने आया था कि सेना ने अपनी सात किस्तों में सारा सामान एसजीपीसी को वापस कर दिया था। एसजीपीसी की पूर्व व मौजूदा अधिकारियों की एक बैठक 13 जून को हुई, जिसमें जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि सारा सामान नहीं लौटाया गया था। इसके बाद इसकी जांच के लिए कमेटी के गठन का फैसला लिया गया था। लोंगोवाल ने कहा कि जांच कमेटी सारे मामले की पारदर्शी ढंग से जांच करेगी।

जांच कमेटी वर्ष 1984 से लेकर आज तक का सारा रिकार्ड चेक करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी का मामला सिख कौम की भावनाओं के साथ जुड़ा है। एसजीपीसी सारा सच संगत के सामने लेकर आएगी। अगर लगाए गए आरोप साबित न हुए तो एस

2575 गांव कर्नाटक में इन दिनों गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं, तेलंगाना के 310 मंडल ऐसे हैं जहां भीषण जल संकट है। वर्तमान में दक्षिण भारत के राज्यों में जलसंकट बढ़ता जा रहा है।

मानसून हुआ बहुत लेट
जलाशयों के भी खाली पेट

भयावह गर्मी और जल संकट से पूरा देश त्राहि माम कर रहा है। देश के कई हिस्सों में लोगों को पीने का पानी नहीं मयस्सर हो रहा है। इस अनिवार्य जरूरत को पूरा करने के लिए कई किमी दूर से उन्हें पानी लाना पड़ रहा है। लू की लपटें असमय लोगों को काल-कवलित कर रही हैं। सिर्फ बिहार में लू से मरने वालों की संख्या सौ के पार हो रही है। इन सब इंसानी दुश्वारियों का एकमात्र इलाज मानसून है। इसी पर लोगों की टकटकी लगी है। लेकिन इस बार सात दिन देरी से केरल तट छूने वाले मानसून की रफ्तार सुस्त है। पूरे देश में अब तक मानसूनी बारिश में 43 फीसद की कमी दिखी है। कायदे से अब तक मानसून की बारिश को आधे देश को सराबोर कर देना चाहिए था, लेकिन अभी मानसून उत्तरी बंगाल और सिक्किम को ही छू सका है। देश में कुल 91 बड़े जलाशय हैं। इनकी भी स्थिति कमोबेश चिंता पैदा करने वाली है। ऐसे में मानसून की ताजा स्थिति और देश के जलाशयों में भंडारण के स्तर पर पेश है एक नजर:

बारिश में कमी
(एक जून 2019 से 17 जून 2019)

76.2 मिमी अब तक देश में होने वाली कुल सामान्य बारिश की मात्रा

43.2 मिमी अब तक हुई वास्तविक बारिश

43% कमी

राज्यों की हालत

बहुत अधिक बारिश	2 राज्य
अधिक	1
सामान्य	2
कमी	18
बहुत कमी	13

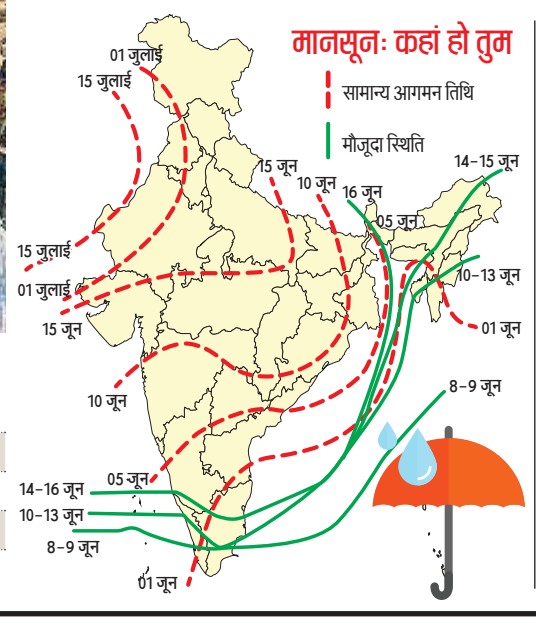

29.189 अरब घन मी
देश के जलाशयों में मौजूद जल

28.013 अरब घन मी
2018 में इस समय तक मौजूद पानी

28.972 अरब घन मी
इस समय तक का सामान्य औसत

जलाशयों का भंडारण

देश में कुल 91 बड़े जलाशय हैं जिनके जलस्तर और भंडारण की जानकारी हर गुरुवार को केंद्रीय जल आयोग जारी करता है। ये जलाशय सिंचाई, पेयजल और पनबिजली उत्पादन करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अहम हिस्सा होते हैं। हालिया 13 जून की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी जलाशयों में इस समय 29 .18 अरब घन मी पानी है जो उनकी कुल भंडारण क्षमता का सिर्फ 18 फीसद है। हालांकि पिछले साल के इसी सप्ताह के मुकाबले भंडारण की समग्र स्थिति अच्छी है लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति काफी दयनीय है।

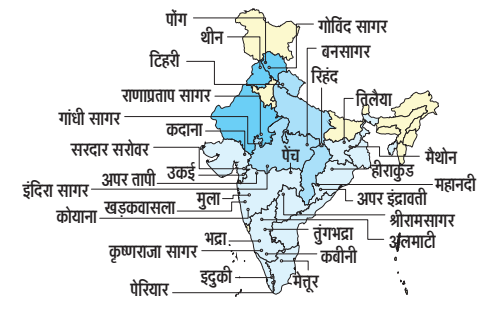

शेष हिस्सों में सामान्य स्थिति

देश के उत्तरी क्षेत्रों (हिमाचल, पंजाब), पूर्वी क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा) और मध्य प्रदेश के जलाशयों की स्थिति ठीक है। यहां के जलाशयों में पानी औसत के अनुरूप है।

पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में बुरा हाल

देश के पश्चिमी हिस्से में 27 बड़े जलाशय हैं। जो गुजरात और महाराष्ट्र की जल जरूरतें पूरी करते हैं। इनकी कुल क्षमता का 10 फीसद पानी इनमें शेष है। जबकि इस समय तक सामान्य भंडारण का औसत 17 फीसद है। महाराष्ट्र के 68 फीसद जलाशयों में सामान्य के कम भंडारण है। दक्षिण के पांच राज्यों में कुल 31 जलाशय हैं जो अपनी क्षमता का महज 11 फीसद भरे हैं। इनकी अब तक की सामान्य भंडारण स्थिति 15 फीसद होती है।

गन्ने और धान की खेती में हो रही भूजल की बर्बादी

जलसंकट ▸ नीति आयोग के सीईओ ने किया आगाह

कहा, पानी है देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

आसन्न जल संकट के प्रति आगाह करते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पानी की है। कांत ने महाराष्ट्र व पंजाब जैसे राज्यों में गन्ने व धान की खेती में भूजल की बर्बादी के प्रति आगाह किया है। साथ ही उन्होंने भूजल का समझदारीपूर्वक उपयोग की जरूरत पर भी बल दिया है।

नीति आयोग के सीईओ ने यह टिप्पणी ऐसे सयम की है जब अगले कुछ दिनों में आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 जारी करने जा रहा है। इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि कौन सा राज्य कितने बेहतर तरीके से अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल और प्रबंधन कर रहा है। आयोग ने पिछले साल पहली बार यह इंडेक्स जारी किया था जिसके शीर्ष पर गुजरात जबकि सबसे निचले पायदान पर झारखंड था।

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। सरकार ने 2024 तक हर घर को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।

कांत ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ''भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें जल सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत आबादी है लेकिन जल संसाधन मात्र चार प्रतिशत हैं। हमारे देश में सिंचाई की 63 प्रतिशत जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं। ऐसे में भारत को भूजल का समझदारीपूर्वक उपयोग, जल स्रोतों को रिचार्ज करने, जलाशयों का जीर्णोद्धार करने और वेस्ट वाटर को पुनः इस्तेमाल करने की जरूरत है।' कांत ने कहा, पंजाब और महाराष्ट्र में धान और गन्ने जैसी फसलें उगायी जा रही हैं जो प्रति हेक्टेयर लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल करती हैं। महाराष्ट्र में गन्ने की पूरी फसल सिंचाई के पानी से ही होती है। बिहार में एक किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है, उतना ही चावल पैदा करने में पंजाब में 3.5 गुना जल खर्च हो जाता है। कांत ने चावल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले जल के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हर साल बासमती चावल के निर्यात के साथ 10 लाख लीटर पानी भी निर्यात कर देता है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। प्रेट्र

स्टील घोटाला में रेलवे के तीन बड़े अफसरों पर गिरी गाज, शक्तियां छीनीं

जागरण प्रभाव

दीपक बहल, अंबाला

▸ जम्मू-ऊधमपुर रेल सेक्शन में करोड़ों का सामान इधर-उधर करना पड़ा भारी

▸ कंपनी पर की मेहरबानी, 7.58 करोड़ के टेंडर को 10 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया

रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के दौरान उपयोग में लाए जा रहे कम वजन वाले स्ट्रक्चर (ट्रैक के साथ साथ लगाए जाने वाले खंभे व ढांचे जो बिजली के तारों को सपोर्ट देते हैं) लगाने के घोटाले में रेलवे के तीन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है।

तीनों की अब किसी भी टेंडर के आवंटन में कोई भूमिका नहीं रहेगी। इनसे वित्त संबंधी कार्य भी छीन लिए गए हैं। यह कार्रवाई प्रयागराज स्थित केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) ने की है। इनमें दो अधिकारी अंबाला चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर (सीपीडी) कार्यालय में तैनात हैं। तीसरा अधिकारी फिरोजपुर मंडल में कार्यरत है।

गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने अफसरों ने 'दांव पर लगा दी यात्रियों की सुरक्षा, खंभों से घटाया स्टील' शीर्षक से इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस घोटाले के कारण जम्मू से ऊधमपुर, ऊधमपुर से कटरा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मुरादाबाद, केरल के कोजीकोड से कोंकण रेलवे सेक्शन में हुआ विद्युतीकरण का कार्य प्रभावित था। इन सेक्शन में लगाए गए स्टील के स्ट्रक्चर का वजन 13 से 19 फीसद तक कम था।

सूत्रों के अनुसार जम्मू-ऊधमपुर सेक्शन में विद्युतीकरण का कार्य करने वाली कंपनी क्वालिटी इंजीनियर्स एंड कांट्रेक्टर्स को अधिकारियों ने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। जिस टेंडर का मूल्य 7.58 करोड़ रुपये तय था, तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए उसका मूल्य बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया, जबकि काम कम में हुआ। इससे कंपनी को फायदा मिला। इसके अलावा स्टील के खंभे, तांबे के तार, ट्रांसफार्मर आदि रेलवे ने प्रोजेक्ट को पूरा कर रही कंपनी को दिए थे, जिसमें से बाकी बचा सामान उसे काम पूरा होने के बाद लौटाना था, लेकिन काम पूरा होने के बाद तांबा व अन्य सामान गायब कर दिया गया।

इस सामान का मूल्य करोड़ों रुपये है। इसके बावजूद कंपनी को लाखों रुपये की राशि जारी कर दी गई। इसी प्रकरण में रेलवे ने विभागीय कार्रवाई की है।

दैनिक जागरण की तरफ से जीएम (कोर) रतनलाल से संपर्क करने का बार-बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) के सीपीआरओ ने अनभिज्ञता जताई।

गायब रेल संपत्ति का पता लगाने में आरपीएफ भी नाकाम

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने सहायक आयुक्त जम्मू के नेतृत्व में चार अफसरों की टीम गठित की थी। टीम ने प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली क्वालिटी इंजीनियर्स एंड कांटेक्टर्स कंपनी के संचालक सतीश मांडवकर और रेलवे अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सामान कहां गया। जांच कमेटी ने कंपनी द्वारा लौटाए गए सामान के चालान और रेलवे लेजर तथा ईश्यू नोट तक चेक किए थे। कुछ चालान पर रेलवे ने सामान को रिसीव भी कर रखा है लेकिन उसकी रजिस्टर में एंट्री नहीं पाई गई।

पीजी मेडिकल सीट पर रुख स्पष्ट करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

▸ याचिका में काउंसिलिंग की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करे कि डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में 400- 500 सीटों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों) में नामांकन की काउंसिलिंग की तारीख बढ़ा सकती है अथवा नहीं। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसे कोई आसान हल नहीं मिल पाया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से पूछा कि वह हलफनामा दायर कर रुख स्पष्ट करें। बनर्जी स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय (डीजीएचएस)की तरफ से पेश हुए थे।

पीठ देश के 1300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के पंजीकृत समूह एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सोसायटी ने काउंसिलिंग की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है ताकि 500 से अधिक सीटों पर नामांकन हो सके। याचिकाकर्ता सोसायटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि कुछ तकनीकी एवं अन्य मुद्दों पर डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मेडिकल सीट खाली रह गई थीं और इससे शिक्षण संस्थानों को काफी नुकसान हो रहा है जिन्हें गुणवत्तापूर्ण ढांचागत निर्माण पर काफी निवेश करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जो सीट व्यर्थ चली जाती है उससे छात्र और शैक्षणिक संस्थान दोनों प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को केंद्र सरकार से कहा था कि समस्या का आसान हल ढूंढने का प्रयास करें। अदालत ने कहा था, ''जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग को एक हफ्ते या संक्षिप्त समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।'' सोसायटी ने याचिका में कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं डीम्ड विश्वविद्यालय न तो सीटों की संख्या बढ़ाने या न ही छात्रों को समायोजित करने के लिए किसी मानदंड को कम करने का आग्रह कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने साझा किया योग का एक और वीडियो

नई दिल्ली, एएनआइ : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर योग का एक और वीडियो साझा किया। इसमें शलभासन का प्रदर्शन किया गया है, जिसे टिड्डी आसन भी कहा जाता है।

3डी वीडियो में एनिमेटेड पात्र नीली रंग की टीशर्ट और काली ट्रैक पैंट पहने है। वह आसन का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि वाइस ओवर के जरिये इसके फायदे बताए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि शलभासन मोटापे को कम करता है, शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को आकार देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। यह साइटिका व मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक है। गर्भवती, पेप्टिक अल्सर, हार्निया, उच्च तनाव और दिल के मरीज इसे न करें। मोदी ने ट्विटर पर वीडियो को साझा करते हुए लिखा, 'मजबूत कलाई और पीठ की मांसपेशियां तथा स्पॉन्डलाइटिस से बचाव... शलभासन का अभ्यास फायदेमंद साबित होता है।'

आइएएस-आइपीएस कैडर आवंटन मामले में केंद्र से मांगा जवाब

▸ 2018 बैच के दो दर्जन से अधिक प्रशिक्षु आइएएस एवं आइपीएस अधिकारियों ने दायर की है याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 बैच के दो दर्जन से अधिक प्रशिक्षु आइएएस एवं आइपीएस अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं के जरिए उन्होंने सरकार की कैडर आवंटन योजना के तहत अपने 20 सहयोगियों को मिली राहत में समानता मांगी है। कोर्ट ने 17 मई को 20 प्रशिक्षु आइएएस एवं आइपीएस अधिकारियों को राहत दी थी जिन्होंने 2018 बैच के लिए सरकार की कैडर आवंटन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। न्यायालय ने केंद्र से इन प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी प्राथमिकता के राज्य कैडरों में एक-एक पद बढ़ाकर उन्हें समायोजित करने का निर्देश दिया था।

गत 17 मई के आदेश के बाद अब 2018 बैच के प्रशिक्षु आइएएस एवं आइपीएस अधिकारियों के दो ग्रुप में 20 अभ्यर्थियों के एक ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें कैडर आवंटन की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था और दूसरा पांच अधिकारियों का अन्य ग्रुप है जिसने अपने 20 सहयोगियों के साथ बराबरी की मांग करते हुए एक नई याचिका दायर की है। कई अन्य प्रशिक्षु आइएएस एवं आइपीएस अधिकारियों ने भी इन दो याचिकाओं में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने कहा कि वह पहली नजर में हाई कोर्ट के नजरिए से सहमत नहीं है। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से इस मामले में केंद्र का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, यह हमारा अस्थायी नजरिया है कि पहली नजर में हम हाई कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं और सरकार को इस तरीके से नहीं झुक जाना चाहिए था। पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद नियमित पीठ के समक्ष तय की है।

धरने पर बैठे गुर्जरों ने सरकार को दिया 20 जून तक का अल्टीमेटम

जासं, जयपुर : विधानसभा में पारित कानून के अनुसार सरकारी भर्तियों में गुर्जरों सहित पांच पिछड़ी जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर दौसा में धरना दे रहे गुर्जरों ने राजस्थान सरकार को 20 जून तक का समय दिया है। इस बीच मंगलवार को अशोक गहलोत सरकार के मंत्रियों और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के गुट के बीच जयपुर में बैठक होगी। इसमें भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर दौसा जिले के सिकंदरा में गुर्जर समाज के बेरोजगार युवक गुर्जर नेता हिम्मतसिंह गुर्जर की अगुआई में एक सप्ताह से धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार विधानसभा में पारित कानून के अनुसार गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे और गुर्जर नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस ले। इसके अलावा कुछ अन्य मांगें भी हैं। धरना दे रहे गुर्जर बेरोजगार युवकों ने सोमवार को धरना स्थल पर महापंचायत कर सरकार को 20 जून तक मांगें मानने का अल्टीमेटम दिया है। बैंसला गुट से अलग होकर नई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति बनाने वाले हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि हमने सरकार को 20 जून तक का समय दिया है।

एएन-32 का ब्लैकबॉक्स क्षतिग्रस्त हादसे की वजह देर से पता चलेगी

▸ तीन जून को हुआ हादसा, 13 वायु सैनिकों में से कोई जिंदा नहीं बचा

▸ अरुणाचल प्रदेश में गहरी खाई में नौ जून को मिला था मलबा

नई दिल्ली, एएनआइ : वायु सेना के विमान एएन-32 का ब्लैकबॉक्स मिल गया है। लेकिन हादसे की वजह से ब्लैकबॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में देरी हो सकती है। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। अभी ब्लैक बॉक्स का परीक्षण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की जानकारी तलाशने की संभावना देखी जा रही है।

यह विमान तीन जून को अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हादसे का शिकार हो गया था। विमान में वायु सेना के तेरह जवान सवार थे, जिनमें से कोई भी नहीं बच पाया। भारी खोजबीन के बाद करीब हफ्ते भर बाद 9 जून को इस विमान का मलबा और जवानों के शव मिले थे। तीन दिन पहले ही ब्लैकबॉक्स मिला था।

सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता भटकने से विमान पहाड़ी से टकराकर गिर गया होगा। लेकिन असली कारणों का पता ब्लैकबॉक्स के परीक्षण से ही लग पाएगा। यह देखा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ब्लैकबॉक्स से डाटा निकाल पाती है या किसी और एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है।

वायु सेना की तरफ से कारणों की जांच जारी है। साथ ही शवों को बाहर निकालने की भी कोशिश हो रही है। पूर्वी वायु कमान के एयर मार्शल आरके माथुर खुद इस ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। इसके चलते उन्होंने अपनी बांग्लादेश यात्रा भी रद कर दी है। असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद दोपहर करीब एक बजे इससे संपर्क टूट गया था।

इसे अरुणाचल प्रदेश के मेचुका स्थित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) पर उतरना था। अरुणाचल प्रदेश में लिपो के पास इसका मलबा मिला था। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी।

उप्र के मीरजापुर में बेटी के शव संग रह रहे थे रिटायर्ड दारोगा

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : उप्र के मीरजापुर स्थित कटरा कोतवाली के हयात नगर निवासी रिटायर्ड दारोगा व उनकी पत्नी अपनी ही बेटी के सड़े-गले शव संग घर में रह रहे थे। दुर्गंध फैलने पर आसपास के लोगों ने बेटे को जानकारी दी। घर पहुंचे बेटे की सूचना पर पुलिस ने कमरे से निर्वस्त्र अवस्था में शव बरामद किया। शव दो माह पुराना बताया जा रहा है।

पुलिस से सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दिलावर खान हयात नगर मोहल्ले में कई साल से मकान बनवाकर रह रहे हैं। उनको दो बेटे अनवार हुसैन व आफताब हुसैन हैं। एक बेटी जीनत थी। बेटे प्रयागराज व दिल्ली में अध्ययनरत हैं। बेटी जीनत (32) माता-पिता के साथ ही रहती थी। करीब दो माह पूर्व उसकी मौत हो गई। दिलावर खान ने इस बारे में किसी को नहीं बताया और शव को कमरे में रख दिया। दफनाया भी नहीं। एक सप्ताह बाद शव सड़ने लगा तो दुर्गंध उठने लगी। इससे आसपास के लोगों का जीना हराम हो गया तो उन्होंने दारोगा के बेटों को बताया। रविवार रात पहुंचे दोनों बेटों ने कमरे में बहन के शव को देखा तो दंग रह गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिता और बहन मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे।

जल यात्रा...

गुजरात के अहमदाबाद में वार्षिक रथयात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जल यात्रा निकाली। श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान साबरमती का पवित्र जल घड़ों में भरकर चलते हैं। यात्रा में सजे-धजे हाथी भी शामिल होते हैं। यह अनुष्ठान रथयात्रा का एक हिस्सा है। एएनआइ

सख्त रुख

पंजाब सरकार को नोटिस, मुख्य सचिव से स्टेटस रिपोर्ट तलब, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर केंद्र से भी मांगा जवाब

बोरवेल मामले में हाई कोर्ट ने जिम्मेदारों के नाम मांगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब के संगरूर जिले में बोरवेल में गिरने से दो वर्षीय मासूम फतेहवीर की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जिम्मेदार अफसरों के नाम बताने को कहा है। कोर्ट ने घटना के कारण और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट तलब कर तीन जुलाई तक जवाब मांगा है।

पंजाब में धान की बुआई के मौसम में किसानों की ओर से एक बार फिर बोरवेल की खुदाई की संभावना पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार समेत प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बोरवेलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर भी जवाब मांगा है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने एनडीआरएफ के ऑपरेशन का बचाव करते हुए कहा कि एनडीआरएफ ने अपने काम को अंजाम देने का सही प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में खुले बोरवेल की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जैन ने कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपट कर रही ऐसे मामलों से बचा जा सकता है। इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि क्या इस बोरवेल को बनाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ था।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट फाइल

याचिका में नीति बनाने की मांग: संगरूर के निवासी एडवोकेट परमिंदर सिंह सेखों ने हाई कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में बोरवेल खोदने के लिए निश्चित नीति बनाए जाने की मांग करते हुए कहा था कि इस नीति में बोरवेल को खोदने और इसके प्रयोग में सावधानियों संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि फतहवीर की मौत जैसी घटनाएं दोबारा न हों। याचिकाकर्ता ने बोरवेल खोदने वाली कंपनियों को बोरवेल खोदते समय ही इन्हें बंद करने के प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी बनाए जाने की भी मांग की है।

ऑपरेशन की देरी पर उठाया सवाल: याचिकाकर्ता ने फतहवीर को बचाने के ऑपरेशन में की गई देरी को जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा है कि इस बचाव ऑपरेशन करने में देरी की वजह से फतहवीर को बचाया नहीं जा सका। याचिका में फतहवीर को बचाने के लिए पांच दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी मांगते हुए कहा गया है कि जिला प्रशासन इस बात की भी जानकारी दे कि सोशल मीडिया पर फतहवीर के बोरवेल में गिरने की सूचना प्रसारित होने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में 10 से अधिक घंटे की देरी पर भी सवाल उठाया था।

और यह भी : सुनवाई के दौरान पंजाब में फसलों के विविधिकरण को अपनाने की हिमायत करते हुए हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पंजाब अगर अपने फसल चक्र से नहीं निकला, तो यहां हालात राजस्थान जैसे हो सकते हैं।

सलमान खान के झूठे शपथ-पत्र मामले में सरकार की अर्जी खारिज

जासं, जोधपुर: फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ झूठा शपथ-पत्र पेश करने की राज्य सरकार की अर्जी को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण जज ने खारिज कर दिया। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2006 में कोर्ट में झूठा शपथ-पत्र पेश किया था कि उनके हथियार का लाइसेंस गायब हो गया है। पिछले सप्ताह इस मामले में सलमान की तरफ से कहा गया था कि उनका किसी भी तरह का यह मंतव्य नहीं था कि वह झूठा शपथ-पत्र दें। ऐसे में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। सीजेएम ग्रामीण अंकित रमन ने फैसले में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई अपील को खारिज कर दिया। 1998 में सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के तीन और आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सलमान को अपना लाइसेंस कोर्ट में जमा करवाना था, लेकिन सलमान की तरफ से झूठा शपथ-पत्र देकर बताया गया कि उनका लाइसेंस गायब हो गया है।

दरवेश हत्याकांड में आरोपित के पिता बोले, बेटे को साजिशन फंसाया गया

▸ कहा, घर से ले गए थे साथी अधिवक्ता, चार लोगों की मौजूदगी में लगी गोली

जागरण संवाददाता, आगरा

उप्र बार कौंसिल अध्यक्ष दरवेश सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को मनीष के पिता सामने आ गए। उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा है कि उनके बेटे को साजिश के तहत दीवानी बुलाया गया था। चार लोगों की मौजूदगी में गोली लगी। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ मुकदमे की मांग की है।

बार कौंसिल अध्यक्ष दरवेश सिंह की दीवानी में बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली मारने का आरोप मनीष बाबू शर्मा पर है। दरवेश को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। अभी तक पुलिस की जांच में भी यही सामने आया है। मनीष बाबू शर्मा गंभीर हालत में गुरुग्राम स्थित मेदांता मेडिसिटी में भर्ती हैं। सोमवार को मनीष के पिता रमेश बाबू शर्मा एसएसपी जोगेंद्र सिंह से मिले।

एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा है कि घटना वाले दिन उनका बेटा मनीष घर में था। दीवानी से अधिवक्ता विनीत गुलेच्छा उन्हें बुलाने पहुंचे थे। मनीष की पत्नी वंदना ने काफी मना किया, लेकिन विनीत ने अपने बच्चों की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि जैसा ले जा रहा हूं, वैसा ही छोड़कर जाऊंगा। जिस पर मनीष बेमन से विनीत के साथ चला गया। मनीष जब दीवानी में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मिश्रा के चैंबर में पहुंचा तो दरवेश, इंस्पेक्टर सतीश यादव, मनोज यादव और कंचन मौजूद थे। गहमागहमी के बाद मनीष को गोली लग गई। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

इंस्पेक्टर सतीश को भेजा बयान के लिए नोटिस : एसएसपी को पत्र भेजने के बाद भी मैनपुरी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश यादव न्यू आगरा थाने में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। इंस्पेक्टर न्यू आगरा अजय कौशल ने बताया कि अब उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भेजकर मंगलवार को बयान के लिए बुलाया गया है। इंस्पेक्टर सतीश दरवेश की हत्या के समय मौके पर मौजूद थे।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 18 जून 2019

दैनिक जागरण

मन की पवित्रता से ही तन की पवित्रता संभव है

गहराता जल संकट

बारिश के पहले देश के विभिन्न हिस्सों में पानी की किल्लत के जैसे समाचार आ रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में पेयजल के साथ सिंचाई के पानी का संकट और गहराने वाला है। इसकी पुष्टि नीति आयोग के सीईओ के इस आकलन से भी होती है कि पानी का संकट सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में धान एवं गन्ने की खेती के जरिये पानी की बर्बादी हो रही है। यह पहली बार नहीं जब गहराते जल संकट के साथ उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो। यह काम एक अर्से से हो रहा है। खुद नीति आयोग ने पिछले साल कहा था कि देश इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। यह अच्छा है कि इस बात को फिर से कहा गया कि धान और गन्ने की खेती के जरिये पानी की बर्बादी की जा रही है, लेकिन केवल समस्या के कारणों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं। इन कारणों का निवारण भी करना होगा। यह आसान काम नहीं, क्योंकि आम तौर पर किसान मनचाही फसलें उगाना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि किसानों को यह बताया-समझाया जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाना उचित है? ऐसा केवल बताया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि जल संकट वाले इलाकों में वे फसलें न उगाई जाएं जो कहीं अधिक पानी की मांग करती हैं। यह कितना कठिन काम है, इसे इससे समझा जा सकता है कि कुछ समय पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के समक्ष यह सवाल उछाला था कि आखिर वे इतना अधिक गन्ना क्यों उगाते हैं तो उस पर आपत्ति जताई गई थी।

इसका कोई मतलब नहीं कि देश के जिन इलाकों में पानी की कमी बढ़ती जा रही है वहां भूमिगत जल का दोहन करके वे फसलें उगाई जाएं जिनमें कहीं अधिक पानी की खपत होती है। आज महाराष्ट्र गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन गन्ना उगाने वाला रकबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह उस पंजाब में धान की खेती बड़ी मात्रा में की जा रही है जहां भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति देश के अन्य अनेक क्षेत्रों में है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि किसानों को कोई यह सीख देने वाला नहीं कि वे क्या करें और क्या न करें? इसके लिए जरूरी हो तो आवश्यक नियम-कानून बनाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। निःसंदेह किसानों को सिंचाई के वे तरीके भी उपलब्ध कराने होंगे जिनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ पानी की बचत करने और उसे दूषित होने से बचाने के तौर-तरीके भी विकसित करने होंगे। हालांकि इस मामले में इजरायल से कुछ सीख ली जा रही है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यह भी एक तथ्य ही है कि वर्षा जल संरक्षण के उपाय अभी कागजों पर ही अधिक हैं।

संकट की घड़ी

पहले से एईएस से जूझ रहे बिहार पर तपिश की मार से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एईएस जहां सौ से अधिक बच्चों को लील चुका है, वहीं दो दिनों में लू से डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखते ही देखते लोग काल के गाल में समाते चले गए। राज्य सरकार इस आपदा का सामना करने में जुटी है। लू और एईएस के शिकार लोगों के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री ने चार-चार लाख के मुआवजे की घोषणा की है। तत्काल इस राशि के भुगतान का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव से बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाने एवं प्रभावित लोगों को हरसंभव चिकित्सा उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश भी दिया है, लेकिन इस मौके पर दूसरी तरफ अस्पतालों में संसाधनों के अभाव एवं चिकित्सकों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। यह स्थिति दुखद है। आइएसओ का दर्जा प्राप्त औरंगाबाद के सदर अस्पताल में लू से आक्रांत लोगों के परिजनों ने जब मरीजों को एसी वार्ड में भर्ती करने की मांग की तो बताया गया कि यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। आइसीयू के बंद रहने से मरीजों को इसकी सुविधा भी नहीं मिल सकी। अगर आइसीयू चालू होता तो कुछ मरीजों की जान बच सकती थी। अस्पताल में एसी भी नहीं था तो परिजनों को बाहर से बर्फ खरीदकर लाना पड़ा। डॉक्टरों की कमी के कारण इलाज में देरी की बात भी सामने आई। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ खड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुजफ्फरपुर का दौरा कर एईएस से मौत के कारणों की जांच के लिए मुजफ्फरपुर में उच्चस्तरीय रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा बीमार बच्चों के बेहतर इलाज के लिए अगले साल तब एसकेएमसीएच परिसर में सौ बेड की पीआइसीयू बनाने का निर्णय लिया गया है। अब व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को इस ओर देखने की जरूरत है। इस संकट से जूझने के लिए विभागों के बीच समन्वय की भी जरूरत है। यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी सूरत में प्रभावितों के इलाज में किसी तरह की कोताही न हो। लू एवं एईएस से बचाव के लिए आमजन में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यह निश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को बेड, स्लाइन और आवश्यक दवाओं के लिए भटकना न पड़े।

कारगर उपाय नहीं सस्ता कर्ज

डॉ. भरत झुनझुनवाला

हमारी अर्थव्यवस्था की हालत उस हृदय रोगी के समान है जिसका इलाज हड्डी के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा हो

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले छह महीनों में तीन बार ब्याज दरों में कटौती की है। इसके पीछे दलील है कि इससे उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेकर उपभोग की वस्तुएं खरीदना एवं उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। परिणामस्वरूप मांग जोर पकड़ेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ब्याज दर में कटौती का यह वांछित परिणाम इस बात पर टिका हुआ है कि उपभोक्ता कर्ज लेकर उपभोग को बढ़ाएंगे या नहीं? इसका कारण है कि उपभोक्ता कर्ज तभी लेगा जब उसे भविष्य में आय की संभावना दिखेगी। जैसे यदि किसी का मासिक वेतन एक लाख रुपये है तो वह निश्चित रूप से कर्ज लेकर कार खरीद सकता है, लेकिन यदि किसी की नौकरी छूट गई है तो भले ही कर्ज कितना सस्ता हो वह कार खरीदने का इच्छुक नहीं होगा। ऐसे में देखना चाहिए कि क्या आम आदमी की आय इस अनुपात में बढ़ रही है जिससे वह कार आदि खरीदने में रुचि दिखाएगा? इस समय उपभोक्ता की आय पर पहला संकट मुक्त व्यापार का है। हमारे आयात निरंतर बढ़ रहे हैं जबकि निर्यात दबाव में हैं। भारत में माल के उत्पादन की लागत अधिक आती है। इसके तीन कारण दिखते हैं। पहला कारण भ्रष्टाचार है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। दूसरा कारण न्यायपालिका है। यदि खरीदार पैसा अदा न करे और न्यायपालिका में मामला दायर करना पड़े तो उद्यमी के पसीने छूट जाते हैं। पांच साल के बाद निर्णय होता है और तब तक पानी उद्यमी के सिर के ऊपर से गुजर चुका होता है। तीसरा कारण है कि भारत में चीन की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण के कानून ज्यादा प्रभावी हैं। प्रदूषण नियंत्रण का बोझ भी हमारे उद्यमियों पर पड़ता है। इन कारणों से भारत में उत्पादन लागत अधिक आती है और हमारे निर्यात दबाव में हैं।

निर्यात उद्योगों जैसे गलीचा अथवा खिलौने में रोजगार कम हो रहे हैं और आम आदमी को भविष्य में आय बढ़ने पर संदेह बना हुआ है। इसलिए ब्याज में कटौती के बावजूद उसके कर्ज लेकर उपभोग बढ़ाने में संदेह है। दूसरा कारण सरकार का आधुनिकता के प्रति मोह दिखता है। सरकार ने मेक इन इंडिया, नोटबंदी एवं जीएसटी के माध्यम से बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्योगों का संकुचन हुआ है। यही कारण है कि सेंसेक्स उछल रहा है जो कि बड़े उद्योगों की सुधरती स्थिति को दर्शाता है, लेकिन देश की आर्थिक विकास दर नरम पड़ी हुई है जो समग्र अर्थव्यवस्था के ठहराव को दिखाती है। छोटे उद्योगों के संकुचन से रोजगार कम हो रहे हैं। उपभोक्ता को भविष्य में आय पर भरोसा नहीं है। वह कर्ज लेकर कार खरीदने को तत्पर नहीं दिखता। तीसरा कारण सरकारी खर्च की दिशा का है। सरकार अपनी आय से अधिक खर्च को पोषित करने के लिए बाजार से उधार लेती है। इस उधारी को वित्तीय घाटा कहा जाता है। सरकार का वित्तीय घाटा वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 7.6 प्रतिशत था। इस वर्ष फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में चालू वर्ष वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का अनुमान 3.5 प्रतिशत बताया गया है। सरकार का वित्तीय घाटा 7.6 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत हो गया है। इसमें 4.1 प्रतिशत की भारी कटौती हुई है। देखना है कि यह कमी किस प्रकार के सरकारी खर्चों में कटौती करके हासिल की गई है। सरकार के खर्च दो प्रकार के होते हैं- राजस्व खर्च यानी खपत और दूसरा पूंजीगत खर्च यानी निवेश। खपत में सरकारी कर्मियों के वेतन, पुलिस, राजस्व आदि आते हैं जबकि पूंजीगत निवेश में हाईवे बनाना आदि आते हैं। सरकार की प्राप्तियों और राजस्व खर्चों अथवा खपत का जो अंतर होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। सरकार का राजस्व घाटा 1990-91 में जीडीपी का 3.2 प्रतिशत था जो चालू वर्ष 2019-20 में 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। यानी सरकार की खपत में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। सरकार के कुल खर्चों में 4.1 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है जबकि राजस्व खर्चों में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट। शेष 3.5 प्रतिशत की कटौती सरकार के पूंजीगत खर्च में हुई है।

अवधेश राजपूत

वर्तमान सरकार की खपत मूल रूप से पूर्ववर्ती स्तर पर कायम है जबकि निवेश में भारी कटौती हुई है। सरकार के राजस्व खर्चों अथवा खपत का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मियों के वेतन अथवा ठेकेदारों को जाता है। इनके द्वारा अपनी आय का एक हिस्सा सोना खरीदने में अथवा विदेश में जमा कराने में किया जाता है। इस प्रकार राजस्व खर्चों अथवा खपत का एक हिस्सा रिसकर बाहर चला जाता है। राजस्व खर्चों अथवा खपत के पूर्ववत बने रहने से रिसाव बना हुआ है और अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। सरकार ने अपने कुल खर्च अथवा वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने में सफलता पाई है। इसके लिए वह प्रशंसा की पात्र है, लेकिन यह नियंत्रण गलत तरीके से हासिल किया गया है। सरकार को चाहिए था कि अपने राजस्व खर्चों अथवा खपत में कटौती करती और पूंजीगत व्यय को पूर्ववत बनाए रखती। पूंजीगत व्यय बढ़ने से हाईवे इत्यादि बनाने से बाजार में सीमेंट और लोहे की मांग बढ़ती और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसकी तुलना में राजस्व खर्चों अथवा खपत से देश की पूंजी का रिसाव होता है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। सरकार ने गलती यह की है कि राजस्व व्यय में कटौती न करके पूंजीगत व्यय में कटौती की है जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी हुई है। इन कारणों से उपभोक्ता को आने वाले समय में आय में वृद्धि का भरोसा नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की हालत उस हृदय रोगी के समान है जिसका इलाज हड्डी के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा हो। अर्थव्यवस्था का रोग आर्थिक नीतियों का है, लेकिन उसका उपचार रिजर्व बैंक के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। जब अर्थव्यवस्था में आम आदमी को भविष्य में अपनी आय बढ़ने का भरोसा ही नहीं है तो वह कर्ज लेकर कार क्यों खरीदेगा?

सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी तीन नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। पहला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सबक लेते हुए संरक्षणवाद को अपनाना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका और प्रदूषण नियंत्रण के खर्च के करण हमारे उद्योगों पर लागत का जितना बोझ बढ़ता है उसी अनुपात में चीन से होने वाले आयात पर आयात कर बढ़ा देने चाहिए जिससे हमारे उद्यमी उनसे प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। दूसरे, सरकार को मेक इन इंडिया के अंतर्गत बड़ी स्वदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मोह छोड़कर अपने छोटे उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। जीएसटी आदि में उन्हें छूट देनी चाहिए जिससे वे बड़ी कंपनियों के सामने टिक सकें और रोजगार सृजन कर सकें। तीसरे, सरकार को वित्तीय घाटे के नियंत्रण को लक्ष्य बनाने के स्थान पर राजस्व घाटे को घटाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। समस्या सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की नहीं है। समस्या खपत की है। सरकार अपनी खपत को कम करे और निवेश बढ़ाए तो अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार की जरूरत

एनके सिंह

समय आ गया है कि संविधान में व्यक्त किए गए केंद्र-राज्य संबंधों को एक बार फिर से परिभाषित किया जाए

हाल की दो घटनाएं केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के संकेत दे रही हैं। पहली घटना पश्चिम बंगाल की है। वहां लोकसभा चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस संबंध में सूबे के राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं। इस अफवाह के साथ कि शायद राज्य में बिगड़ते हालात के बाद राष्ट्रपति शासन का विकल्प केंद्र सरकार सोच सकती है। इसके बाद कोलकाता में दिल के मरीज के अस्पताल में मरने के बाद एक डॉक्टर को एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा घातक रूप से पीटने पर पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल डॉक्टरों को धमकी दी, बल्कि हालात बिगाड़ने का आरोप केंद्र में शासन कर रही भाजपा पर थोप दिया। सोशल मीडिया पर घायल डॉक्टर की लहूलुहान फोटो देखकर बाकी डॉक्टर भड़क गए। इसका देशव्यापी असर हुआ और स्वास्थ्य सेवाएं एम्स से लेकर निजी अस्पतालों तक में बंद हो गईं। दूसरी घटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से चलाई जाने वाली योजनाओं का विरोध ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि राज्यों को अपनी योजना चलाने की आजादी होनी चाहिए। उनका आरोप है कि केंद्रीय योजनाओं में औसतन 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को व्यय करना पड़ता है, लेकिन श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। नीतीश ने अभी चंद दिनों पहले ही भाजपा के साथ चुनाव लड़कर अपनी पार्टी को लोकसभा में 16 सीटें दिलाई हैं। ममता भी केंद्र में भाजपा की सरकार में मंत्री रही थीं और नीतीश भी, लेकिन इन दोनों ने कभी भी केंद्र की किसी योजना पर आक्षेप नहीं लगाया था। यह 'ज्ञान' उन्हें इस चुनाव में भाजपा को मिली जबरदस्त देशव्यापी जीत के बाद आया है।

यह भी ध्यान रहे कि केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे समय में जब देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया के साथ समेकित हो चुकी हो, जब किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कृषि-बाजार को देशव्यापी बनाने की कवायद चल रही हो, जब केंद्र की नीतियों का राज्यों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा हो तब यह तनाव विकास और जनकल्याण को बुरी तरह अवरुद्ध कर सकता है। ध्यान रहे केंद्र की अधिकांश योजनाओं पर अमल राज्य सरकारें करती हैं। देखा जाए तो इस बढ़ते तनाव के पीछे दो कारण हैं। पहला, राज्यों में भाजपा का स्थानीय दलों के मुकाबले बढ़ता जनाधार और दूसरा, केंद्र में भाजपा की ताकत बढ़ने से गैर भाजपा राज्यों में (कांग्रेस या उनके द्वारा समर्थित सरकार में भी) पार्टी के टूटने का खतरा। ये दोनों पहलू क्षेत्रीय दलों को ही नहीं, कांग्रेस को भी हाशिये पर ला सकते हैं। यह डर भी राज्य सरकारों को केंद्र के साथ दो-दो हाथ करने के भाव में ला रहा है।

इतिहास गवाह है कि जब कभी केंद्र ने राज्य की शक्तियों का प्रभुत्व के आधार पर एक सीमा से अधिक दमन किया तो केंद्र ही कमजोर हुआ, क्योंकि राज्य की शक्तियां बगावत पर आ गईं। अतीत में अंग्रेज मजबूत केंद्र की नीति के तहत चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया, 1833 बना कर सारी शक्तियां केंद्र में निहित करने लगे। लॉर्ड डलहौजी ने सुधार के नाम पर इस केंद्रीकरण के शिकंजे को और मजबूत किया। नतीजा था 1857 का विद्रोह। अंग्रेज सकते में थे और अगले ही साल पूरा शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों आ गया। अगले तीन सालों में अंग्रेज हुकूमत को समझ में आ गया कि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश में स्थानीय शक्तियों को दबाकर पूर्ण केंद्रीकरण करके शासन करना असंभव है। इसके लिए उन्होंने राजाओं की सहायता ली, जो कहने को तो संप्रभु थे, लेकिन शक्तिहीन थे। अंग्रेजों ने अगले 90 साल इसी तरह सफलतापूर्वक शासन किया। इसके बाद आजाद भारत का संविधान बनाने के समय तीन जून, 1947 को संघ शक्ति समिति की दूसरी रिपोर्ट में भी कहा गया 'अब जबकि विभाजन एक निर्विवाद सत्य है तब हम सर्वसम्मति से इस राय के साथ हैं कि देश के हित के लिए यह घातक होगा कि ऐसा एक कमजोर केंद्रीय शासन हो जो जरूरी मुद्दों पर समन्वय बनाने में अक्षम हो। पुख्ता संवैधानिक ढांचा वह है जिसमें परिसंघ के साथ ही एक मजबूत केंद्र हो।' शायद इसी भावना से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान रखे जो आज राज्यों के मुकाबले केंद्र को मजबूत पायदान पर रखते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा को जो जन स्वीकार्यता मिल रही है वह पुराने जमाने का 'नृप-प्रजा' भाव नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में लालू यादव, जयललिता, मायावती भी समय-समय पर यह जन स्वीकार्यता हासिल कर चुकी हैं। यह उनकी गलती थी कि वे झूठे सशक्तीकरण के जरिये सता पर काबिज रहना चाहते थे।

दरअसल क्षेत्रीय ताकतों के उभार का मुख्य कारण समाजशास्त्रीय न होकर राजनीतिक रहा है। ये वहीं उभरती हैं जहां अल्पसंख्यक अपने राष्ट्रीय औसत 14.2 प्रतिशत से ज्यादा हैं जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और केरल। अल्पसंख्यकों का वोट जब उस पार्टी के आधार वोट जो नेता की जाति से तय होता है, से मिल जाता है तो यह मेल सीटों पर जीत में तब्दील हो जाता है। इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर आधारित जातिवादी पार्टियां देखने को नहीं मिलतीं। ममता बनर्जी का संकट यह है कि वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की अपनी नीति रातों-रात बदल नहीं सकतीं और नाराज बहुसंख्यक भाजपा के रूप में अपना 'रक्षक' देखने लगा है। सामाजिक तनाव का राजनीति में लाभ का यह दोनों तरफ से अद्भुत नमूना है और भाजपा इस खेल में भारी पड़ रही है, लेकिन क्या मोदी इस 'हम-बनाम-वे' से राज्यों में काबिज होकर समाज को अपेक्षित समरसता दे सकेंगे? क्या उन्हें सामाजिक तनाव जनित बिगड़ते केंद्र-राज्य संबंधों के काल में तब तक इंतजार करना होगा जब तक भाजपा पूरे राज्यों में 'अपना' शासन नहीं कर लेती? भाजपा के विस्तार के इस उद्दात भाव के ही कारण ममता-चंद्रबाबू तो छोड़िए, शिवसेना और नीतीश भी हमेशा उससे सशंकित रहते हैं, भले ही चुनाव के कारण उन्हें साथ आना पड़ता हो। ऐसे में क्या अब समय नहीं आ गया है जब संविधान में व्यक्त किए गए केंद्र-राज्य संबंधों को एक बार फिर से परिभाषित किया जाए, ताकि सार्थक क्षेत्रीय भावनाएं प्रतिक्रियात्मक बहुसंख्यकवाद की बाढ़ में बह न जाएं?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चिंता

वेदों और तमाम अन्य ग्रंथों में चिता और चिंता में समानता का वर्णन किया गया है। आशय यह है कि चिंता मानव जीवन में चिता के समान ही जीवन के अंत का कारण बनती है। यहां पर एक विचारोत्तेजक प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि यदि चिंता व्यक्ति के जीवन को लील सकती है तो इससे मुक्ति पाने का यथोचित मार्ग क्या है? इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न भी तार्किक हो उठता है कि आखिर हम चिंता का शमन कैसे करें, ताकि इसके प्राणघातक प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख पाएं?

चिंता पर जब हम शिद्दत से मनन करें तो इस सत्य को समझने में देर नहीं लगती है कि जिन तमाम चिंताओं से एक इंसान हलकान और बेजार होता है, वे सभी महज दो प्रकार की होती हैं। चिंताओं का पहला प्रकार मानव-निर्मित है तो दूसरा प्रकृति प्रदत्त। यहां पर हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मानव-निर्मित चिंताओं के कर्णधार हम खुद ही होते हैं और इसीलिए उनके समाधान का रास्ता भी हम तक ही आकर सिमट कर रह जाता है। इसके लिए खुद के जीवन की सोच, कर्म और दर्शन पर गंभीरता से सोचने की दरकार है। यदि हमें कोई चिंता सता रही हो तो पहला काम यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारी जीवनशैली, सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों और मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रही है? यदि खुद को आप इस प्रकार के चक्रव्यूह में पाते हैं तो फिर यह समय चेतने का है, यह समय खुद को रोकने का है और यह समय खुद को नियंत्रित करके मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों के रास्ते पर लौट कर आ जाने का है।

कुछ चिंताएं प्रकृति और प्रारब्ध से प्राप्त होती हैं, जिन पर एक व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। समय तेजी से बदलता जा रहा है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज धन है, कल नहीं है, आज सुख है तो कल नहीं है, आज आनंद है तो कल नहीं है, आज स्वस्थ हैं तो कल नही हैं, आज प्रसन्न हैं तो कल नहीं हैं। इन्हें हम नियंत्रित नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में इन सभी अपरिहार्य घटनाओं पर चिंता व्यर्थ है। समय के चक्र को सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही चिंता से मुक्ति का सांसारिक दस्तूर है तो फिर चिंता क्यों? जीवन की वास्तविकताओं को मूल स्वरूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी चिंताओं से मुक्त करती है।

श्रीप्रकाश शर्मा

कितना उचित है मुफ्त सफर का वादा

आशीष सूद

दिल्ली मेट्रो को 378 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है। इस पर और आर्थिक बोझ डालना अनुचित होगा

मेट्रोमैन ई. श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली मेट्रो को कंगाल होने से बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार को सालाना एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना होगा। इससे दिल्ली मेट्रो स्वाबलंबी न रह कर, सरकारी सब्सिडी का मोहताज हो जाएगी। (डीएमआरसी ने यह राशि सालाना 1560 करोड़ रुपये बताई है।) श्रीधरन की इस राय से शायद ही कोई असहमत होगा कि महिलाओं को छूट मिलते ही कई अन्य जरूरतमंद वर्गों जैसे छात्र, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को भी छूट देने की मांग उठेगी। यह बीमारी कहां जाकर रुकेगी, यह कहना मुश्किल है। श्रीधरन ने दोटूक कहा है कि जब मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की भागीदारी हैं तो दिल्ली सरकार अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती।

लेकिन मेट्रोमैन के अनुभव और नजरिये का सम्मान करने के बजाय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें जो जवाब लिखा है, वह इस बात का सनद है कि 'आप' का सरोकार न व्यवस्था से है न ही जनता से। केंद्र से सलाह के बिना मनमाने ढंग से घोषणा क्यों की गई, इसका कोई जवाब सिसोसिदा के पत्र में नहीं है?

दिल्ली मेट्रो पहले से ही आर्थिक दबाव से गुजर रही है। 2009 से इसके इनपुट खर्च में 105 प्रतिशत, कर्मचारियों पर 139 प्रतिशत, जबकि रखरखाव पर खर्च में 213 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। एक बेहतर मैनेजमेंट के बावजूद मेट्रो को करीब 378 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है। इस पर और आर्थिक बोझ डालने पर इसकी व्यवस्था का चरमरा जाना तय है। सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली सरकार टोकन खरीद कर महिलाओं को बांटेगी। प्रश्न यह है कि क्या सरकार टोकन बांटने के लिए शहर भर के मेट्रो स्टेशनों पर अपना टोकन काउंटर खोलेगी? इन काउंटरों पर किन लोगों को नियुक्त करेगी? इनका खर्च कौन वहन करेगा?

'आप' ने 'यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट कमांड' के साथ लोक परिवहन को सस्ता, सुलभ और सुगम बनाने का जो वादा किया था, उसे दिल्ली सरकार भूल गई। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट कमांड में ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, कैब सर्विस और मेट्रो समेत पूरी परिवहन व्यवस्था को एकीकृत कर उसे चाक-चौबंद बनाया जाना था। दिल्ली में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 4000 नई बसें उतारने के वादे के उलट, 400 नई बसें भी नहीं आईं। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 100 करोड़ रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। इससे दिल्लीवासी हर दिन मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर हैं।

दिल्ली सरकार 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' का वादा भी पूरा नहीं कर पाई! दिल्ली में अमूमन आवास से मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से कार्य स्थल तक पहुंचना ज्यादा दुष्कर है। महिलाएं इसमें और भी ज्यादा परेशानी महसूस करती हैं। मेट्रो स्टेशन को सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो फीडर सर्विस और ई-रिक्शा आदि से जोड़ने में दिल्ली सरकार विफल रही है। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सुविधा इस बात की गारंटी नहीं है कि महिलाएं इसका उपयोग करेंगी ही।

(लेखक दिल्ली भाजपा के नेता हैं)

मेलबाक्स

प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने की जरूरत

भारत के भविष्य का आधार बने नई शिक्षा नीति शीर्षक से अपने लेख में सृजन पाल सिंह ने मोदी सरकार की बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं, वे विशाल आबादी वाले विकासशील भारत के लिए तब तक अनुपयोगी हैं जब तक भारत की शिक्षा को गुणवत्तापरक नहीं बनाया जाता। प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापरक शिक्षा की नींव है, यह नींव जितनी सुदृढ़ होगी आगे की शिक्षा उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि यह एक तथ्य है कि इस देश की कमजोर प्राथमिक शिक्षा आगे की माध्यमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। भारत की उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की बात करने वाली नई शिक्षा नीति में इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। शायद इसीलिए आज कथित रूप से शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उप्र जैसे बड़े राज्य में हाईस्कूल-इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में नकल का बोलबाला रहता है। इस स्तर पर नकलविहीन परीक्षा कराना लगभग असंभव सा हो गया है। नकल का यह रोग उच्च शिक्षा में भी व्याप्त है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पहले शिक्षा की नींव मानी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को पहले की मॉडल स्कूल पद्धति के अनुरूप कड़े मानकों के आधार पर त्रिवर्षीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उसी जिले के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाए जहां के वे मूल निवासी हैं, ताकि वे अपने अध्यापकीय दायित्व को ठीक से निर्वाहित कर सकें। शिक्षा की नींव मानी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ किए बिना माध्यमिक और उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने की बात करना बेमानी है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

एक देश एक चुनाव

देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के संदर्भ में कई सालों से बहस चल रही है। इस संदर्भ में समय-समय पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग एक देश एक चुनाव के समर्थन में पहल कर चुके हैं। 2018 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों तथा सरकारी अधिकारियों की राय जानने के लिए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था, परंतु अधिकतर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। दरअसल आजादी के बाद चार चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 एक देश एक चुनाव के आधार पर कराए गए। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों को क्या समस्याएं हैं? वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर चर्चा के लिए संसद भवन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। समस्त देशवासियों को उम्मीद है कि यदि एक देश एक जीएसटी लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं? इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों को सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि चुनाव में होने वाली पैसे एवं समय की बर्बादी को रोका जा सके। चुनाव पर होने वाले खर्च में हो रही वृद्धि से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में एक राष्ट्र में एक चुनाव होना ठीक है।

vermakashish66@gmail.com

डॉक्टरों का फर्ज

अपवाद स्वरूप सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों को छोड़ दें तो अधिकांश डॉक्टर अपना फर

100 वर्ग मीटर आकार की छत पर लगभग 65 हजार लीटर तक वर्षा जल को एकत्रित किया जा सकता है, बारिश के मौसम में होने वाली बारिश की बूंदों को बेकार में बहने से बचाते हुए।

आजकल

शिक्षा व्यवस्था को भारतीय बनाने की पहल

प्रो. सतीश कुमार
शिक्षाविद

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने जैसी सिफारिशों को लागू करने का ड्राफ्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया है। अनेक प्रकार की व्यावहारिक बातों के अलावा इसमें शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर भी पूरा जोर दिया गया है। साथ ही इसमें देश की भाषाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव को भी रेखांकित किया गया है। कहा गया है कि आजीविका के साथ मूल्यों की शिक्षा देने और बच्चों को जीवन के लिए भी तैयार करने की आवश्यकता है। इसे समग्रता से लागू करने से पूर्व सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ा बदलाव हो सकता है

देश की आजादी के लगभग 72 वर्षों बाद शिक्षा व्यवस्था को भारतीय ढांचे में डालने की कोशिश 2019 की प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है जिसे तैयार करने वाली समिति के चेयरमैन प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन हैं। समिति ने अपनी सिफारिशों को मानव संसाधन मंत्रालय के पोर्टल पर डाल दिया है। साथ ही इस संबंध में आम जनता से सुझाव को आमंत्रित किया गया है। लोगों से प्राप्त सुझाव के उपरांत ही सरकार इस बारे में नीतिगत निर्णय लेगी। वर्ष 2019 का शिक्षा अधिनियम 1988 के बाद पहला नियम होगा। वर्ष 1992 में आंशिक बदलाव किए गए थे, लेकिन वह महज कॉस्मेटिक बदलाव था। इस ड्राफ्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि कट्टर वैचारिक आलोचक इस बात को तूल नहीं दे पाए कि सरकार ने शिक्षा का भगवाकरण कर दिया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है। सभी ने इसकी प्रशंसा की है। आलोचना केवल त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर दक्षिण के राज्यों में राजनीति को हवा देकर की गई। हालांकि यह कोई आज की बात नहीं है, इसकी बुनियाद 1988 की शिक्षा नीति के तहत लागू की गई थी। सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों को आश्वासन दिया है कि पहले की तरह उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। दरअसल हिंदी आज विवाद के दायरे में भी नहीं है। जिस तरीके से सांस्कृतिक आयामों से हिंदी का प्रसार दक्षिण के राज्यों में हुआ है उससे राजनीति की रोटी सेकने का अवसर किसी के पास बच नहीं जाता।

लचर प्रणाली से दयनीय दशा

दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। भारत की गिनती एक नामचीन देश के रूप में होने लगी है, लेकिन शिक्षा की लचर प्रणाली के कारण हमारी दशा दयनीय होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर हमारे कोई भी शिक्षण संस्थान अपनी जगह बनाने में सफल नहीं रहे हैं। इस बात का रोना हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कई बार रो चुके हैं। आज भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था के तहत गुणों की तलाश की जाती है, वह व्यवस्था और प्रारूप ही बेढंगा है। देश की सोच की जगह विदेशी सोच, अपने इतिहास की जगह अन्य देशों का इतिहास और संस्कृति की उधेड़ बुन में देश की व्यवस्था अटकी रही। स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच में कोई तारतम्य नहीं रहा। भूमंडलीकरण ने इस दशा को और पेचीदा बना दिया। पुस्तकों से खिसक कर ज्ञान मोबाइल और कंप्यूटर में समाहित होते जा रहे हैं। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच पहले से ही तल्खी थी, भूमंडलीकरण ने बची-खुची रचनात्मकता को खत्म कर दिया। लाखों लोग ऐसी डिग्री लेकर बाजार में हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा की जानकारी भी समुचित रूप से नहीं होती, बाजार जनित रोजगार ऐसे लोगों को लेने से परहेज करता है। फिर सवालिया निशान खड़ा होता है कि भारत में बेरोजगारी की तादाद बढ़ती जा रही है, सरकार ने पांच वर्षों में कुछ भी नहीं किया। समस्या की जड़ हमारी व्यवस्था में है। जब तक उसे दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, भारत की पहचान एक समृद्ध देश के रूप में नहीं बन पाएगी। यह नई शिक्षा व्यवस्था उसी को दुरुस्त करने का सफल प्रयास है।

स्कूली शिक्षा और भारतीय धारणा को समझने के लिए दो सच्ची कहानियां महत्वपूर्ण होंगी। कक्षा छह से आठ के कुछ बच्चों को शहर से गांव ले जाया जाता है। गांव में दिसंबर के महीने में लहलहाते खेत में गेहूं और आलू के पौधे लगे हुए थे। जब बच्चों से पूछा गया कि यह किस चीज के पौधे हैं, तो कोई भी बच्चा उन पौधों की सही पहचान नहीं कर पाया। दरअसल इसमें दोष उन बच्चों का नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का है। दूसरी कहानी और दर्दनाक है। राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे छात्रों से जब पूछा गया कि शीत युद्ध की व्याख्या करें, तो अधिकतर छात्रों ने लिखा कि ठंड की रात में शीत की बूंदों में लड़ी गई लड़ाई को शीत युद्ध कहते हैं। यह हमारी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा की स्थिति है।

शिक्षा मंत्रालय में केवल शिक्षा

ऐसे हालात में जब बात गुणपरक आर्थिक व्यवस्था की हो तो कैसे हम अन्य देशों से मुकाबला कर पाएंगे। जिनकी जानकारी इतनी कमजोर और लचर हो, 2019 की शिक्षा व्यवस्था में इन अवगुणों को दूर करने की कोशिश की गई है। इसकी कई विशेषताएं हैं जिन्हें रेखांकित करना जरूरी है। साथ में इस बात की भी विवेचना की गई है कि इससे परिवर्तन कैसे होगा। पहला, इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाना तय किया गया है। अभी इसे मानव संसाधन मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। यह शब्द ज्यादा व्यापक है, कई चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। शिक्षा मंत्रालय के तहत बात केवल शिक्षा की होगी। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन शिक्षा आयोग बनाने की है। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखने के कारण कई विसंगतियां प्रांत स्तर पर दिखाई देती हैं। नियमों का पालन राष्ट्र स्तर पर नहीं हो पाता और न ही एकरूपता बनी रहती है। बच्चों के स्थान परिवर्तन की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। नई व्यवस्था में इन कमियों को दूर करने की कोशिश होगी।

विदेशी ढांचे का अनुपालन

भारतीय शिक्षा कभी भी भारत की नहीं रही। स्कूल में बच्चों को ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप में जो काम दिए जाते हैं, वह अपने देश को जानने को छोड़कर सबकुछ होता है। इटली की वास्तुकला, चीन की चित्रकला और यूरोप के इतिहास की जानकारी। वहां अपना देश कहीं नहीं है। ब्रिटिश नीतिकार मैकाले ने सही कहा था कि भारत आनेवाली कई शताब्दियों तक ब्रिटेन का गुलाम शिक्षा पद्धति की वजह से बना रहेगा। इतने वर्षों में भारत को कोई भी सामाजिक वैज्ञानिक एक नए सिद्धांत को देने में सफल नहीं रहा है। केवल विदेशी ढांचे का अनुपालन हम तन्मयता से करते गए। उच्च शिक्षा में बनाए गए विषय भी पश्चिमी नक्शे-कदम पर थे। वर्ष 1948 की राधाकृष्णन समिति और 1964 की कोठारी समिति में भी शिक्षा को उपनिवेशिक मानसिकता से हटाने की बात की थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिससे स्थिति कॉपी कैट की बनी रही। विदेशों में पढ़ने की होड़ और शिक्षा व्यवस्था में उसकी जबरदस्त पकड़ हमारे देश की पहचान बनी रही। शिक्षा के उच्च पदों पर उसी को बैठाया जाता, जिसकी डिग्री विदेशों से अर्जित की गई हो। यानी यह मान लिया गया कि हमारी व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है।

रचनात्मक परिवेश ही है शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रो. डीपी सिंह ने उच्च शिक्षा को सुनियोजित और सुयज्ञ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम दिया है। उनका मानना है कि विश्वविद्यालय छात्रोन्मुख होना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता विद्यार्थियों की होनी चाहिए। प्रो. डीपी सिंह ने कहा कि ऐसे और प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे छात्रों की शोध गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। शिक्षा महज पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, पढ़ाई केवल क्लासरूम तक नहीं होती, एक रचनात्मक परिवेश बनता है, जहां पर जीवन के हर पहलू की जानकारी शिक्षा के जरिये दी जाती है। यूजीसी इस पहल को मुकाम तक ले जाना चाहती है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जगदीश कुमार ने कई ऐसे विषयों की पढ़ाई और शोध पर बल दिया जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। ज्ञान का एक ऐसा पुंज जिसे गैर प्रगतिशील समझकर दरकिनार कर दिया गया और हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। प्रो. जगदीश कुमार ने उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। ट्राइबल मेडिसिन और इकोलॉजी पर विशेष बल देने की बात की गयी है। जेएनयू की एक टीम इस विषय की गंभीरता के साथ उच्च शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश में है। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सुनील अम्बेकर भी ड्राफ्ट पॉलिसी की प्रशंसा इस अर्थ में करते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में एक भारतीयता की झलक है। देश को मजबूत और संयोजित करने की एक परिकल्पना है। अगर यह देश मजबूत होना है तो हुनर की पहचान भी शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर मदरसा की व्यवस्था को भी एक ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई है। अर्थात धर्म की शिक्षा में विज्ञान और ज्ञान का समावेश भी यथोचित होना चाहिए। इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2019 की ड्राफ्ट, शिक्षा नीति में बदलती है तो देश का स्वरूप भी बदलेगा। भारत अगर धर्म के कारण विश्व गुरु बनने की कल्पना करता है तो शिक्षा ही तुरूप का पत्ता साबित होगा।

मातृभाषा में हो ज्ञान का विकास

आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां देश के सामने आईं। उसमें एक बेहद गंभीर समस्या भाषा की समस्या थी। भाषाई विषमता ने देश को खंडों में बांट दिया। एक वर्ग अंग्रेजी स्कूलों से निकलने वाला इलीट वर्ग बनता गया, और शेष सरकारी स्कूलों में पढ़कर बेतरतीब व्यवस्था के शिकार बनते गए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्च कोटि की नौकरियां भी अंग्रेजी में पढ़ने वालों की मिलती गई। बीते सात दशकों में मातृभाषा की स्थिति अछूत जैसी हो गई। गांधीजी की दिव्य दृष्टि ने भविष्य का लेखा जोखा कर लिया था। उनके विचार में बच्चों को उनके घर से दूर करना असली शिक्षा से दूर करना है, क्योंकि घर से बड़ा विद्यालय और कोई नहीं होता है। नैतिकता पर बल देते हुए शिक्षा द्वारा सहयोग की भावना और धार्मिक- जातिगत भेदभावों तथा द्वेष से दूर रहने की भावना को विकसित करना एक अहम विषय है। उनके अनुसार शिक्षा अनुभवों के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए जिससे बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और उसे हर काम को बराबर सम्मान देना सिखाया जाए या ऐसा माहौल दिया जाए कि वो ये सारी बातें अमल में लाते हुए शिक्षित हों। गांधीजी ने अपनी शिक्षा योजना में सबसे पहले माध्यम के सवाल को महत्वपूर्ण मानते हुए इस बात पर बल दिया कि भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा देने का काम प्रांतीय भाषाओं में किया जाना चाहिए। गांधीजी ने 1908- 1910 में इंडियन ओपिनियन में लिखा था- 'हमलोगों में बच्चों को अंग्रेज बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति अपनेआप में घातक है।' फरवरी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी उन्होंने यह बात सभी के बीच में रखी- 'इस विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बोलना पड़े, यह अत्यंत ही अप्रतिष्ठा और लज्जा की बात है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में सफल होगा।' इसके बाद 1917 में भागलपुर में छात्रों के एक सम्मलेन में भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा- 'मातृभाषा का अनादर मां के अनादर के बराबर है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमारी भाषा में वह शब्द नहीं है कि ऊंचे विचार प्रकट किए जाएं, जबकि यह दोष भाषा का नहीं है, उसे बढ़ाना हमारा ही कर्तव्य है।' गांधीजी ने यह भी कहा कि जब तक हमारी मातृभाषा में हमारे सारे विचार प्रकट करने की क्षमता विकसित नहीं हो जाती और वैज्ञानिक विषय मातृभाषा में नहीं समझे जा सकते, तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकेगा।

खरी-खरी

कानून का 'का' और 'नून'!

डॉ. अनिता यादव

हम तोड़ने में बेहद माहिर हैं, फिर वह कानून हो या खुद के मामले में अड़ी दूसरे की टांग। नियम तोड़कर दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करना हमारा वैधानिक अधिकार है। यह अधिकार जन्मजात नहीं, सुसभ्य समाज में रहकर अनुकरण द्वारा अर्जित करना पड़ता है। जिसके पास जितनी तीव्र अर्जन क्षमता, उसका प्रतिभा निखार उतना प्रखर। यातायात नियम तोड़ने के मामले में यह कला और प्रतिभा हमारे यहां इफरात में है। वह जीवन ही निरर्थक है, जो इस कला को अर्जित न कर पाया। जीवन की सार्थकता का रास्ता इसी नियम-तोड़क सड़क से गुजरता है। इस मामले में दोपहिया चालक सबसे 'तेज' हैं।

ठेले और ई-रिक्शा थोड़े और आगे की सोचते हैं। उनके लिए लाल बत्ती भी हरी बत्ती है। कलर ब्लाइंड होकर निकल जाना उनके लिए मदारी के खेल से ज्यादा नहीं। जीवन में शॉर्टकट सफलता का सूत्र भले न हो, पर सड़क पर वही सफल है जो शॉर्टकट काट ले। भले चित्र पर हार चढ़ जाए, मगर सड़क पर हार बर्दाश्त नहीं।

असल में हमें अलगाव पसंद नहीं। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग लेन बनाना हमारी संस्कृति का ध्रुवीकरण है। मिली-जुली संस्कृति का परिचय हम स्कूटर की लेन में गाड़ी, गाड़ी की लेन में ट्रक और ट्रक को हवाई जहाज के रनवे पर पहुंचा कर देते रहते हैं। मेलजोल बचपन से सीखा है। तभी नियम और कायदों में झोल की क्षमता भी आसानी से अर्जित कर पाते हैं। जितनी जल्दी हमें घर जाने की होती है, उससे कई गुना जल्दी दूसरे की लेन में घुसने की होती है। इससे चालक को आत्मतुष्टि सहित अन्य की 'टॉलरेंस पावर परीक्षा' भी हो जाती है। 40 की स्पीड लिखा साइन बोर्ड देखकर भी रफ्तार 100 नहीं की तो आप नुगरे माणस नहीं, बल्कि उत्तम चालक हैं! फिर हादसे हों तो हों। आखिर मनमर्जी भी किसी चीज का नाम है।

रोड जाम पर जाम से जाम टकराने में भी हम पीछे नहीं हैं। समय कीमती है, इसलिए उसकी इज्जत जरूरी है। एसी गाड़ी में बैठकर कानून का 'नून' और 'का' अलग-अलग तोड़ने तथा जाम की बोरियत को चियर्स कह खल्लास न किया तो किस बात का नागरिक! सीटी मारते हवलदार का क्या, वह तो आएगा और मुंह खोल, फूंक मार बोलेगा ही। अब आपका कर्तव्य बनता है कि वह बोले, उससे पहले 'करारे गांधी' से उसकी मुट्ठी गरम कर दी जाए।

ट्वीट-ट्वीट

डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं, बच्चों को इलाज नहीं, एम्स में हार्ट सर्जरी के लिए पांच साल की डेट, गजब है। पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाकर क्या करेंगे जब मूलभूत सुविधाओं का यह हाल है।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

भुवी की चोट पर विराट ने कहा कि विकल्प के तौर पर हमारे पास शमी उपलब्ध हैं। भारतीय क्रिकेट विशेषकर गेंदबाजी विभाग पहले कभी इतना समृद्ध नहीं रहा।
संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर भारत की जीत को 'एक और स्ट्राइक' बताया है। यकीनन यह बड़ी जीत है, पर यह क्रिकेट का खेल है कोई युद्ध का मैदान नहीं।
राजदीप सरदेसाई@sardesairajdeep

क्वाड सदस्यों में केवल भारत ही चीन से सीमा साझा करता है, लेकिन वही उसके खिलाफ सबसे मुखर है और बीआरआइ जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाता है। भारत के उलट अन्य सदस्यों ने बीआरआइ सम्मेलनों का बहिष्कार नहीं किया। एससीओ सम्मेलन में भी मोदी ने बीआरआइ पर झुकने से इन्कार कर दिया। ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

हिमालय की ओर खिंचे चले आ रहे विदेशी पर्यटक

रेणु जैन
स्वतंत्र टिप्पणीकार

तेजी से बदलती और भागदौड़ भरी जीवनशैली के कारण अधिकांश लोगों में स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ता जा रहा है। आज ज्यादातर लोग अक्सर स्वयं के तनाव में होने की शिकायत करते हैं। लोगों में मानसिक तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। भारत में इस तनाव को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते रहते हैं। इन उपायों में ध्यान, योग, प्राणायाम, घूमना-फिरना, रिश्तेदारों से मिलना, विभिन्न कार्यक्रमों में जाना एवं दोस्तों से गपशप करना शामिल है ही, लेकिन अब एक तथ्य यह भी उजागर हुआ है कि लोग पहाड़ों पर कुछ समय बिताकर तथा हरियाली के बीच रहकर तनाव को दूर करते हैं। वे वहां जाकर थोड़े दिनों में सारी चिंताओं से बेखबर होकर अपने मन को आगे के लिए शांत तथा स्थिर करने की कोशिश करते हैं।

हिमालय पर्वत आजकल विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, बल्कि कई पर्यटक तो वहां महीनों बिताते हैं। वैसे भारतीय ऋषि-मुनि सदियों से हिमालय की कंदराओं में आसन जमाकर योग एवं प्राणायाम करते रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमालय में बड़े-बड़े आश्रम हैं जहां आज भी सैकड़ों साधक साधना में लीन हैं। हम हिमालय के जितने अंदर जाएंगे, उतनी नई जानकारियां मिलती जाएंगी। हिमालय के मठों में अनेक महात्मा अपनी योग-साधना के बल पर कई दिनों तक निराहार रहते हैं। धर्मग्रंथों के अनुसार यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य था इसलिए इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है।

अध्यात्म की तलाश में हजारों विदेशी यहां आकर भारत के वातावरण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अध्यात्म विद्या सीखने के लिए अन्य देशों की अपेक्षा यहां उचित वातावरण है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के पिपली गांव के रहने वाले तेग सिंह नेगी ने वर्ष 2013 में योग में मास्टर डिग्री हासिल की तथा अब वे हिमालय योग आश्रम में लोगों को योग सीखा रहे हैं। कई विदेशी भी यहां योग सीख रहे हैं। कुछ समय पूर्व अफ्रीका के लाइबोस शहर में 50 देशों के करीब 10 हजार लोगों को उन्होंने

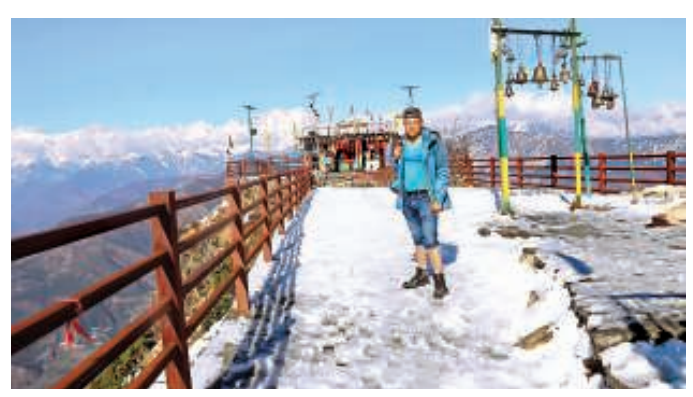

योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के गुर सिखाए। कहा जाता है कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्मरोग, अस्थिरोग तथा नेत्ररोग जैसी बीमारियां नहीं होतीं। गौर से देखें तो जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की तुलना में बेहतर होता है। एक बात और ध्यान तथा योग के माध्यम से औसत आयु बढ़ाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग तथा अध्यात्म की इस जमीन पर हिमालय की कंदराओं में 33 साल पहले साधना की थी। बीते माह लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी उन्होंने यहां की गुफा में साधना की थी। इस गुफा में योग, ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शांति के लिए माकूल माहौल है।

जिंदगी को तनावमुक्त, सेहतमंद तथा खुशनुमा बनाने के लिए जापानियों ने भी 'फॉरेस्ट बाथिंग' थैरेपी का प्रचलन शुरू किया। सीधे शब्दों में कहें तो यह जंगल या घने पड़ों के बीच कुछ देर शांति से घूमना-फिरना होता है। जापानी वैज्ञानिकों की मानें तो फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब पेड़ों की शुद्ध हवा लेना भर नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच रहने से तमाम तरह के तेल और उनकी महक हमारे शरीर तक पहुंचती हैं, इससे हमारा शरीर कई तरह के कीटाणुओं तथा वायरस से सुरक्षित रहता है। टेक्नोलॉजी से घिरे हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए जंगलों की सैर कारगर सिद्ध हो रही है। फॉरेस्ट थैरेपी अब जापान के साथ-साथ यूरोपीय देशों से लेकर कनाडा तक लोकप्रिय होती जा रही है। जंगल की खुबसूरती, गंध तथा ध्वनियां हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से लाभ पहुंचाती हैं और सकारात्मक विचार लाती हैं। यह थैरेपी डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, मोटापे तथा डायबिटीज जैसे रोगों के लिए अधिक लाभकारी हैं। वन थैरेपी कॉर्टिसोल नामक एक तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को भी कम कर देती हैं।

हिमशिखरों के बीच बसे उत्तरकाशी की पहचान हिमालय योग नगरी के रूप में भी बढ़ रही है। हिमालय की गोद में गंगा किनारे बसा उत्तरकाशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही साधकों का भी ठौर बनता जा रहा है। ये साधक होटलों की आलीशान जिंदगी के बजाय होम स्टे में ठहरना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जिन ग्रामीणों के पास पारंपरिक शैली के पुराने घर हैं वे उन्हें कुछ सजा-संवार कर होम स्टे शुरू कर रहे हैं। यहां ठहरने वाले विदेशियों का कहना है कि गंगा किनारे हिमालय की गोद में सबकुछ भूल जाने और खुद में खो जाने का एहसास हुआ है। कुछ विदेशियों का कहना है कि उन्होंने कई राष्ट्रों की धर्म-संस्कृति का इतिहास पढ़ा है, पर हिंदुस्तान को जब से जानने का अवसर मिला, तय किया कि वहां जाकर वहां की संस्कृति को जानेंगे।

इस पूरे इलाके में कई ऐसे योग केंद्र हैं जो विदेशी मेहमानों को पहाड़ी संस्कृति से भी परिचित कराते हैं। इस लिहाज से होम स्टे भी पसंद किए जा रहे हैं। इससे राज्य में पर्यटकों के जरिये आमदनी का एक बड़ा माध्यम शुरू हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह की मुहिम को सरकार भी अपनी ओर से सहूलियत प्रदान करे ताकि यहां अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक आ सकें।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की बन सकती है?

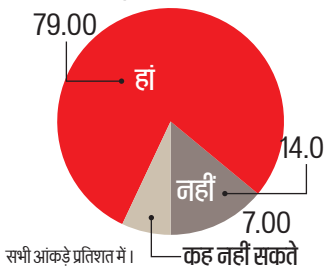

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या एक राष्ट्र-एक चुनाव पर सभी दलों की सहमति बनने की संभावना है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गुंडागर्दी 'लू' करे रवि बरसाए आग,
नदियां सूखी हो गईं सूखे कूप-तड़ाग।
सूखे कूप-तड़ाग जीव पर बरसे आफत,
सूर्यदेव का आज देखते बनता है हठ।
कर लो प्रकृति विनाश कभी मारेगी सर्दी,
कभी झेलना आप ताप की गुंडागर्दी।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

वर्षा जल संचयन से ही संकट का समाधान

रोहित कौशिक
स्वतंत्र टिप्पणीकार

बारिश के पानी को जितना हम जमीन के अंदर जाने देंगे उतना ही हम जल संकट को दूर रखेंगे। इस प्रणाली को प्रभावी बनाने से हमारे देश को सूखे के संकट से बचाया जा सकता है। इस बारे में लोगों को जागरूक होना ही होगा

देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अनेक राज्यों में जल संकट गहराता जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया था कि देश के 91 जलाशयों में उनकी क्षमता का 25 फीसद औसत जल ही उपलब्ध है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जल रिपोर्ट में जल संकट को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि में जल की बढ़ती जरूरतों, ऊर्जा उपभोग, प्रदूषण और जल प्रबंधन की कमजोरियों की वजह से स्वच्छ जल पर दबाव बढ़ रहा है। इन कारणों से दुनिया के कई देश गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है।

हमारे देश में भी वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि भूजल स्तर घटने के कारण जल्द ही देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु समेत देश के अनेक इलाकों में भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आज जल संकट को लेकर चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन इससे निपटने हेतु गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि आज जल संकट से देश का आम आदमी ही अधिक जूझ रहा है, लेकिन उसमें इस संकट से उबरने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है। जल संकट जब तक आम आदमी की चिंता नहीं बनेगा तब तक इससे उबरने के बारे में सोचना शायद दिवास्वप्न ही होगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जल संकट की चिंता बुद्धिजीवियों की गोष्ठियों से निकलकर आम आदमी तक भी पहुंचे। यह तभी संभव होगा जब आम जनता के बीच इस विषय को लेकर युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए।

बुद्धिजीवियों द्वारा जब भी जल संकट की चर्चा की जाती है तो वर्षा जल के संग्रहण की सलाह दी जाती है। सरकार जन-जागरण अभियान के तहत सरकारी औपचारिकताओं को निभाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं में भी वर्षा जल संग्रहण के विज्ञापन प्रकाशित कराती है। लेकिन इस मामले में अभी तक नतीजा ढाक

के तीन पात ही है। भारत में मात्र 10 से 15 प्रतिशत वर्षा जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष नालियों-नदियों के रास्ते समुद्र में चला जाता है। इस मामले में इजराइल जैसे देश ने (जहां वर्षा का औसत 25 सेमी से भी कम है) एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। वहां जल की एक बूंद भी बेकार नहीं जाती है। प्रभावी जल प्रबंधन तकनीक के कारण वहां जल की कमी नहीं होती है। जल संकट से निपटने के लिए हमें भी अपने देश में ऐसा ही उदाहरण पेश करना होगा। एक आंकड़े के अनुसार यदि हम देश के कुल जमीनी क्षेत्रफल में से महज पांच फीसद क्षेत्र में होने वाली वर्षा के जल का संग्रह कर सके तो एक करोड़ लोगों को 100 लीटर पानी प्रतिदिन मिल सकता है।

वर्षा का करीब 85 फीसद जल बरसाती नदियों के माध्यम से समुद्र में बेकार बह जाता है। यदि इस जल को जमीन के भीतर पहुंचा दिया जाए तो इससे एक ओर बाढ़ की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर भी बढ़ेगा। जनसंख्या में हुई तीव्र वद्धि से हमारे देश में पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सतही एवं भूमिगत दोनों ही स्रोतों से जल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता कुछ अधिक ही है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 70 फीसद भाग जल से भरा हुआ है, लेकिन पीने लायक मीठा जल केवल तीन फीसद ही है। शेष खारा जल है। इसमें से भी हम सिर्फ एक फीसद मीठे जल का ही उपयोग करते हैं। धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल, जल चक्र में चक्कर लगाता रहता है। औद्योगीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट के कारण जहां एक ओर जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जल चक्र भी बिगड़ता जा रहा है।

विश्व में उपलब्ध कुल जल की मात्रा आज भी उतनी ही है जितनी दो हजार वर्ष पहले थी। अंतर है तो बस इतना कि उस समय पृथ्वी की जनसंख्या आज की तुलना में महज तीन फीसद ही थी। वर्ष 1947 में प्रतिव्यक्ति मीठा जल 6,000 घन मीटर उपलब्ध था जो वर्ष 2000 आते-आते केवल 2,300 घन मीटर रह गया। जल की बढ़ती खपत को देखते हुए यह आंकड़ा वर्ष 2025 तक सिर्फ 1,600 घन मीटर हो जाने की आशंका है।

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के एक अनुमान के अनुसार अगले 20 वर्षों में ही भारत में जल की मांग 50 फीसद बढ़ जाएगी। देश में समस्त उपलब्ध जल के 90 प्रतिशत का उपयोग कृषि उत्पादन में किया जाता है। यदि कृषि उत्पादन में समुचित जल निकासी एवं जल उपयोग के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो 20 प्रतिशत तक जल की बचत की जा सकती है। इसी प्रकार दुनिया का लगभग 22 फीसद जल विभिन्न उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। यदि औद्योगिक क्षेत्र पानी की बचत करना शुरू करें और पानी का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करें तो इस संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। आज हमने भले ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन मौजूदा जल संकट से निपटने हेतु हमें अपनी पुरानी तकनीक को ही अपनाना होगा। हम अपने मकान की छत पर वर्षा जल को एकत्रित कर भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर टैंक में जमा कर सकते हैं। बारिश के मौसम में 100 वर्ग मीटर आकार की छत पर 65,000 लीटर वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां पानी का प्रमुख स्रोत बरसात ही है, वहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जल संकट का बेहतर समाधान है।

फिच ने फिर देश का विकास अनुमान घटाया

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी फिच ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए देश का विकास अनुमान घटाकर 6.6 फीसद कर दिया। एजेंसी ने लगातार दूसरी बार चालू वित्त वर्ष के लिए देश का विकास अनुमान घटाया है। इस बार मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र में सुस्ती का संकेत मिलने से विकास का अनुमान घटाया गया है। रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान सबसे पहले सात फीसद पर रखा था। (प्रेट्र)

वित्तीय स्थिरता अब मौद्रिक नीति समीक्षा का प्रमुख आधार बन चुकी है। हम एनबीएफसी सेक्टर की स्थिरता के लिए भी कदम उठा रहे हैं।
— शक्तिकांत दास
चेयरमैन, आरबीआइ

सेंसेक्स 38,960.79	निफ्टी 11,672.15	सोना (प्रति दस ग्राम) ₹33,620	चांदी (प्रति किलोग्राम) ₹38,090	डॉलर ₹69.91	क्रूड (ब्रेंट) $ 61.91 (प्रति बैरल)
▼ 491.28	▼ 151.15	▼ ₹100	▼ ₹10	▲ ₹0.11	

जेट एयरवेज के फिर उड़ान भरने की उम्मीदें खत्म

कर्जदाता बैंक देंगे एनसीएलटी में आवेदन

जेट पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये का बकाया, बहुत कम रिकवरी की उम्मीद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कभी देश की नंबर-वन एयरलाइन कही जाने वाली निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के फिर से उड़ान भरने की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों ने सोमवार को यह फैसला किया कि इसके लिए नए शेयरधारक खोजने की जगह इसकी दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत अब जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों की बिक्री की जाएगी और उससे वसूली हुई राशि को कर्ज देने वाले बैंकों और शेयरधारकों में बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जेट एयरवेज का मामला ज्यादा दिनों तक लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बैंकों ने यह फैसला है। पीएमओ के उच्च अधिकारियों की पिछले शुक्रवार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ बैठक हुई थी। इसमें कहा गया था कि अब जेट एयरवेज के मामले को आइबीसी के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएएलटी) के तहत ले जाना चाहिए।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने बताया है कि जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों की बैठक में यह फैसला किया गया है कि इस मामले का निपटारा दिवालिया कानून के तहत करने का फैसला किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के एसबीआइ और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने जेट एयरवेज को सबसे ज्यादा कर्ज दिया हुआ है। जब से जेट एयरवेज ने उड़ान भरनी बंद की है, तभी से बैंक किसी न किसी नए निवेशक की खोज में लगे हैं। लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला है। सिर्फ एक कंपनी ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव किया था। लेकिन वह कई नियमों से छुटकारा चाहता था। सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों के इस फैसले के बाद अब सही तरीके से एनसीएलटी इस पर फैसला कर सकेगी। वैसे, जेट एयरवेज को दो अन्य कर्जदाता पहले ही एनसीएलटी में ले जा चुके हैं। उनकी मांग है कि कंपनी को आइबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया में लाया जाए। उन कंपनियों की याचिका पर एनसीएलटी गुरुवार को सुनवाई करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बैंकों की तरफ से भी मंगलवार को ही एनसीएलटी में मामला भेज दिया जाएगा।

बुरी तरह टूट चुकी है कंपनी : जेट एयरवेज का परिचालन 18 अप्रैल से बंद है। इस पर वित्तीय संस्थानों का 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज बकाया है। कंपनी पर वेंडरों का 10,000 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के मद में भी 3000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसके अलावा बंद होने से पहले कंपनी 13,000 करोड़ रुपये का घाटा भी उठा चुकी है। बैंकों ने जेट एयरवेज का परिचालन दोबारा शुरू करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया के तहत वसूली की रकम बहुत कम हो जाएगी। ऐसे में बैंकों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा।

निवेशक खोजने की कोशिशें नाकाम। फाइल

शेयरों में गिरावट जारी

एक समय शेयर बाजार में निवेशकों की खास पंसद बने रहने वाले जेट शेयरों की कीमत सोमवार को 18 फीसद और गिर गई। बीएसई में इसकी एक शेयर की कीमत 68.30 रुपये पर बंद हुई। जून के महीने में इसके शेयरों के भाव में 54 फीसद से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

हवाई क्षमता में आई कमी तीन माह में दूर होने की संभावना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्पाइसजेट, विस्तारा और इंडिगो के विमान बेड़ों में होगा विस्तार

निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के बंद होने से भारतीय कंपनियों की सीट क्षमता में जो कमी आई थी, वह अगले तीन महीनों में दूर होने की उम्मीद है। इसकी भरपाई निजी विमानन कंपनियां स्पाइसजेट, विस्तारा तथा इंडिगो करेंगी। हालांकि क्षमता की पूरी भरपाई होने में कम से कम तीन महीने का वक्त लग सकता है।

स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह के मुताबिक अगले चार-पांच महीनो में डोमेस्टिक रूटों पर क्षमता की समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सीटों की उपलब्धता बढ़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वर्ष अप्रैल-मई के दौरान स्पाइसजेट ने अपने बेड़े में 25 नए विमान शामिल किए हैं। कंपनी के बेड़े में अगले छह महीनों में 35 और विमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से कई विमान जेट एयरवेज के बेड़े वाले होंगे। इससे स्पाइसजेट की सीट क्षमता 80 फीसद बढ़ जाएगी। छह महीनों में विस्तारा और इंडिगो भी अपना बेड़ा बढ़ाएंगी। जुलाई के बाद से डोमेस्टिक रूटों में क्षमता की दिक्कत कम होने लगेगी। जेट एयरवेज के बंद होने से भारतीय एयरलाइन उद्योग की सीटिंग क्षमता में 4.5 अरब अवेलेबल सीट किलोमीटर (एएसके) की कमी पैदा हुई थी। इसमें से लगभग 2.9 अरब एएसके की भरपाई अप्रैल में ही स्पाइसजेट, विस्तारा और इंडिगो की ओर से कर दी गई थी। अगले तीन महीनों में जेट के बाकी ज्यादातर विमानों का भी स्पाइसजेट और विस्तारा द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

जहां तक अंतरराष्ट्रीय मार्गों का सवाल है, तो जेट के वाइड बॉडी विमानों की भरपाई भारतीय एयरलाइनों में केवल एयर इंडिया कर सकती है, जो जेट की तरह यूरोप और अमेरिका के लिए उड़ाने संचालित करती है। इंडिगो के पास वाइड बॉडी विमान नहीं हैं। इसलिए अपने यात्रियों को इंटरनेशनल उड़ानों की सुविधा देने के लिए उसने टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग समझौता किया हुआ है। अगले चार माह में केएलएम तथा एयर फ्रांस की योजना भारत के विमानों और उड़ानों में 25 फीसद बढ़ोतरी की है। अक्टूबर में वर्जिन अटलांटिक मुंबई से लंदन के बीच उड़ानें शुरू करने वाली है, जबकि डेल्टा एयरलाइन का मुंबई से न्यूयॉर्क के बीच दिसंबर से उड़ानें शुरू करन की योजना है।

आमदनी दोगुनी करने को सरकार ने बढ़ाई रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कृषि मंत्री तोमर ने योजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
- मांग आधारित खेती के साथ लागत घटाने और उपज के उचित मूल्य पर जोर

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुट गई है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस दिशा में किए प्रयासों की गहन समीक्षा की और संबंधित परियोजनाओं की रफ्तार को तेज करने का निर्देश दिया। किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों ने तोमर के समक्ष योजनाओं की सही तस्वीर रखी।

नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अशोक दलवई ने समीक्षा बैठक में वर्ष 2022 तक आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए कार्यों का ब्योरा पेश किया। दलवई ने परंपरागत फसलों की खेती के साथ अन्य संबंधित उद्यमों के विकास का विवरण पेश किया। उन्होंने बैठक में बताया खेती में उपज से लाभ को बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों का उचित प्रयोग कर लागत में कटौती जैसे उपाय किए जा रहे हैं। फसल चक्र को अपनाने के साथ खेती में विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत ऊंचे दाम वाले फसलों की खेती की जा रही है।

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए गैर-कृषि कार्यों से किसानों को जोड़ने के बारे में तोमर ने विस्तार से जानकारी मांगी। समीक्षा बैठक में उन्हें बताया गया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। खेती को जोखिम से बचाने के लिए फसल बीमा योजना, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाना और किसानों तक खेती की उन्नत जानकारी पहुंचाने को प्रमुखता दी गई है।

बैठक में अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि कृषि कार्यों से 60 और गैर-कृषि कार्यों से 40 फीसद तक आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी रणनीति तैयार कर किसानों तक पहुंचा दी गई है। उसके अमल के लिए राज्य सरकारों पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। दूसरी योजना के तहत मांग आधारित खेती पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से बचाने के उपायों पर जोर दिया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। फाइल

भारत-अमेरिका तनाव बढ़ने की आशंका से बाजार में गिरावट

- सेंसेक्स में 491.28 अंकों की और निफ्टी में 151.15 अंकों की गिरावट
- पिछले चार सत्रों में कुल 796.02 अंक लुढ़क चुका है सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : देश में अमेरिकी आयात पर जवाबी शुल्क लगने के बाद निवेशकों में घबराहट बढ़ने से सोमवार को देश के शेयर बाजारों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट देखी गई। मानसून की प्रगति को लेकर चिंता बढ़ने से भी बाजार में गिरावट को बल मिला। बीएसई का सेंसेक्स 491.28 अंकों की गिरावट के साथ 38,960.79 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 151.15 अंकों की गिरावट के साथ 11,672.15 पर बंद हुआ। पिछले चार सत्रों में सेंसेक्स कुल 796.02 अंक लुढ़क चुका है।

सेंसेक्स में टाटा स्टील में सर्वाधिक 5.66 फीसद गिरावट रही। वेदांता व टाटा मोटर्स तीन फीसद से अधिक और एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल व रिलायंस इंडस्ट्रीज दो फीसद से अधिक लुढ़के। सेंसेक्स में सिर्फ दो शेयरों में तेजी रही। यस बैंक 0.74 फीसद और कोल इंडिया 0.10 फीसद उछले। बीएसई के सभी सेक्टरों में गिरावट रही। धातु सेक्टर में सर्वाधिक 3.05 फीसद और ऊर्जा सेक्टर में 2.49 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 1.29 फीसद और स्मॉलकैप में 1.35 फीसद गिरावट रही। बीएसई पर जेट एयरवेज में 16.76 फीसद गिरावट रही। अपोलो टायर्स 7.87 फीसद उछला।

भारतीय स्टील और अल्यूमिनियम पर अमेरिका के शुल्क के जवाब में भारत ने भी अमेरिका के 29 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जो रविवार से लागू हुआ। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि ट्रेड वार का दायरा बढ़ने से निवेशक सहम गए हैं। केंद्रीय बैंकों और जीएसटी काउंसिल की इस सप्ताह होने वाली बैठक तक बाजार में गिरावट जारी रहने की संभावना है।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के पीसीजी एंड कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी प्रमुख वीके शर्मा ने कहा कि निवेशक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की इस सप्ताह आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में दक्षिण कोरिया के बाजार में गिरावट और शंघाई, हांगकांग व टोक्यो के बाजारों में तेजी दर्ज की गई। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुझान रहा।

रुपया लगातार तीसरे सत्र में हुआ कमजोर : रुपये में भी लगातार तीसरे सत्र में गिरावट रही। यह 11 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 69.91 पर बंद हुआ। गत तीन कारोबारी सत्रों में रुपया 57 पैसे कमजोर हो चुका है।

निवेशकों के दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूबे : शेयर बाजारों में हुई चौतरफा बिकवाली से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के निवेशकों को दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 2,00,258.81 करोड़ रुपये घटकर 1,50,09,329.19 करोड़ रुपये पर आ गया।

सोना 100 रुपये फिसला, चांदी लगभग सपाट

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों में सुस्ती और घरेलू निवेशकों की बेरुखी के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने के भाव में गिरावट आई। चांदी भी नकारात्मक रुझान के साथ पिछले कारोबारी सत्र के आसपास ही बंद हुई। सोमवार को सोने का भाव 100 रुपये टूटकर 33,620 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। कारोबार के आखिर में चांदी का भाव 10 रुपये गिरावट के साथ 38,090 रुपये प्रति किलोग्राम था।

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को विदेशी बाजारों में पीली धातु के प्रति निवेशकों में उत्साह नहीं देखा गया। इसलिए घरेलू बाजार में भी निवेशक सोने में निवेश से दूर रहे। दूसरी तरफ, चांदी को औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का समुचित साथ नहीं मिला। न्यूयॉर्क में सोने का हाजिर भाव गिरावट के साथ 1,333.90 डॉलर और चांदी का भाव 14.85 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 100 रुपये गिरकर 33,620 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना 33,450 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। सोने की आठ ग्राम की गिन्नी 26,800 रुपये प्रत्येक के भाव पर बनी रही। चांदी हाजिर 10 रुपये फिसलकर 38,090 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई।

पीरामल ने बेचा हिस्सा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर लुढ़के

- 2,305 करोड़ रुपये में बेचा हिस्सा, छह साल में 653 करोड़ का मुनाफा
- छह फीसद से ज्यादा टूट गए श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर

मुंबई, प्रेट्र : दिग्गज कारोबारी अजय पीरामल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में अपने ग्रुप की करीब 10 फीसद हिस्सेदारी बेच दी है। हालांकि फिलहाल सौदे की सही कीमत उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह हिस्सेदारी 1,000-1,015 रुपये प्रति शेयर के भाव से लगभग 2,305 करोड़ रुपये में बेची गई है।

पीरामल इंटरप्राइजेज ने वर्ष 2013 में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 9.96 फीसद हिस्सेदारी 1,652 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इस सौदे से उन्हें सिर्फ छह साल में 653 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पीरामल एंटरप्राइजेज ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा 'कंपनी ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अपनी पूरी 9.96 फीसद हिस्सेदारी शेयर बाजार में तीसरे पक्ष के निवेशकों को बेच दी है।' पीरामल इससे पहले भी श्रीराम ग्रुप से बाहर निकलने पर विचार कर रहे थे और 2017 में उन्होंने आइडीएफसी ग्रुप से विलय की कोशिश भी की थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अलावा पीरामल के पास श्रीराम सिटी यूनियन (10 फीसद) और श्रीराम कैपिटल में 20 फीसद हिस्सेदारी है। उन्होंने इन दो कंपनियों में उन्होंने 2014 में हिस्सेदारी बढ़ाई और 2015 में ग्रुप के चेयरमैन बन गए। श्रीराम ग्रुप में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य 9,000 करोड़ रुपये अधिक है। गौरलतब है कि अजय पीरामल अपने निवेश पर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए मशहूर हैं। इससे पहले उन्होंने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन में निवेश से भारी मुनाफा कमाया था।

दोनों के शेयरों पर दबाव

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के शेयरों पर सोमवार को शेयर बाजारों में बड़ा दबाव देखा गया। बीएसई में कंपनी के शेयर 6.15 फीसद गिरकर 1,015 रुपये के भाव पर बंद हुए। एनएसई में भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर 6.53 फीसद टूट गए। सोमवार को कारोबार के आखिर में एनएसई में श्रीराम ट्रांसपोर्ट का शेयर भाव 1,014 रुपये रह गया। दूसरी तरफ, पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयर भी बीएसई में 3.07 फीसद गिरकर 2,004.85 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

जिस बैंक को परदादा ने खड़ा किया, उसी के विलफुल डिफॉल्टर हुए यश बिड़ला

- यूको बैंक ने 67.55 करोड़ रुपये कर्ज नहीं चुकाने पर बिड़ला को घोषित किया विलफुल डिफॉल्टर
- बैंक ने 'नेम एंड शेम' अभियान के तहत जाहिर किए 665 ऐसे कर्जदारों के नाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता यूको बैंक ने अपने संस्थापक घनश्यामदास बिड़ला के भाई के परपोते यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। यश बिड़ला नियंत्रित कंपनी बिड़ला सूर्या लिमिटेड ने 67.55 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया। बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम जाहिर कर उन्हें शर्मिंदा करने के अपने 'नेम एंड शेम' अभियान के तहत 665 ऐसे कर्जदारों की सूची जारी की है, जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया है। बिड़ला सूर्या लिमिटेड को यह कर्ज एक कंसोर्टियम ने दिया था, जिसमें सरकारी क्षेत्र के तीन अन्य कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल थे।

यूको बैंक ने बिड़ला सूर्या लिमिटेड को मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित अपनी कॉरपोरेट शाखा से 100 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा मुहैया कराई थी। यह सुविधा कंपनी द्वारा मल्टी-क्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक सेल की उत्पादन गतिविधियों के लिए दी गई थी। बैंक के मुताबिक इसका 67 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया था। इस लोन को वर्ष 2013 में एक फंसे कर्ज (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत किया गया था।

अपनी वेबसाइट पर जारी एक सूचना में यूको बैंक ने कहा कि कर्जदार (बिड़ला सूर्या लिमिटेड) को कई बार नोटिस भेजे गए। कर्जदार कंपनी, उसके निदेशकों, प्रमोटर्स और गारंटर्स को विलफुल डिफॉल्टर्स घोषित कर दिया गया और इस बारे में क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों को सूचना दी गई है।

परदादा ने ही की थी बैंक की स्थापना : कोलकाता स्थित यूको बैंक की स्थापना वर्ष 1943 में घनश्यामदास बिड़ला (जीडी बिड़ला) ने युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक नाम से की थी। यशोवर्धन बिड़ला के परदादा रामेश्वरदास बिड़ला उनके भाई थे। यश बिड़ला के पिता अशोक बिड़ला की बेंगलुरु में एयर क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद यश बिड़ला ने कारोबार की कमान संभाली।

कौन होता है विलफुल डिफॉल्टर

किसी कर्जदार को 'विलफुल डिफॉल्टर' तब घोषित जाता है जब वह जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाता है। यानी, उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, फिर भी वह भुगतान नहीं करता। इसके अलावा कर्जदाता को बिना बताए असेट्स की बिक्री और रकम को दूसरे कामों में लगाने के चलते भी किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। अगर किसी प्रमोटर को किसी कर्जदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो उसे किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अतिरिक्त कर्ज नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही वह अगले पांच वर्षों के लिए कोई नई कंपनी शुरू नहीं कर सकता है। इसके अलावा, कर्जदाता उस कर्जदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू कर सकते हैं।

जेईई-एडवांस्ड में एलन के कार्तिकेय गुप्ता ने किया टॉप

नई दिल्ली, (वि) : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस्ड के परिणामों में एक बार फिर एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सिद्ध की है। एलन के क्लासरूम कोचिंग स्टूडेंट कार्तिकेय गुप्ता ने देशभर में टॉप किया है। टॉप-10 में एलन के तीन तथा टॉप-100 में 38 स्टूडेंट्स शामिल हैं।

संस्था के निदेशक बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर श्रेष्ठ परिणाम दिए हैं। कार्तिकेय गुप्ता ने टॉप-10 में पहली रैंक दी है। कार्तिकेय दो साल से एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के क्लासरूम स्टूडेंट हैं। इससे पहले एलन क्लासरूम स्टूडेंट चित्रांग मूर्दिया ने 2014 में और अमन बंसल ने 2016 में देशभर में टॉप किया है। सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ऑल इंडिया रैंक-वन पर एलन स्टूडेंट नलिन खंडेलवाल रहे। अरूणांग्शु भट्टाचार्य ने जिपमेर में टॉप किया।

निजी बैंकों ने जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में की कटौती

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने पिछले सप्ताह अपनी जमा योजनाओं की ब्याज दरों में 0.25 फीसद तक की कटौती की है। माना जाता है कि कर्ज दरों में कटौती करने से पहले बैंक अपनी जमा दरों में कटौती करते हैं। नकदी की स्थिति सुधरने और इस महीने के शुरू में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मुख्य नीतिगत दरों में कटौती होने के बाद इन बैंकों ने अपनी जमा दरों में कटौती की है।

आरबीआइ का मानना है कि मुख्य नीतिगत दरों में कटौती होने और इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए जाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अधिकारियों के मुताबिक आइसीआइसीआइ बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स की दरों में 0.10-0.25 फीसद कटौती की है। नई दरें सोमवार से ही लागू हो गई। एक्सिस बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके बैंक ने कुछ खास फिक्स्ड डिपॉजिट्स की ब्याज दरें 0.15 फीसद तक घटाई हैं।

तीन बड़े बैंकों ने घटाई दरें। प्रतीकात्मक

निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी जमा दरों की समीक्षा की है और नई दरें पिछले बुधवार से लागू कर दी गई हैं। आरबीआइ ने इस महीने के शुरू में लगातार तीसरी बार अपनी मुख्य नीतिगत दरों में कटौती की थी। आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उनके द्वारा की गई कटौतियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंकों की सराहना की थी। उन्होंने हालांकि यह भी कहा था इस दिशा में और भी अधिक किए जाने की जरूरत है।

भूमि अधिग्रहण की फांस से अटकीं 435 परियोजनाएं

- एसबीआइ की शोध टीम की रिपोर्ट : औद्योगिक परियोजनाओं की राह में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी अड़चन
- संसदीय समिति के पास है भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, बजट सत्र में रिपोर्ट आने की संभावना

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए दो के कार्यकाल में लंबित परियोजनाओं की राह में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों को बताया गया था। लेकिन पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद यह समस्या जस की तस दिखती है। भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन की जो कोशिशें पिछली सरकार में की गई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार खुद मान रही है कि भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों की वजह से 435 औद्योगिक परियोजनाएं लटकी हुई हैं। ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां साफ दिख रही हैं, तो भूमि अधिग्रहण पर स्पष्टता बेहद जरूरी हो गई है। यह बात किसी निजी एजेंसी ने नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की शोध टीम 'इकोरैप' ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कही है।

इकोरैप में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में निश्चित तौर पर कई अच्छी बातें हैं। लेकिन उद्योग जगत की नजर में इसने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने का काम किया है। रिपोर्ट में सरकार के हवाले से कहा गया है कि देश में 435 औद्योगिक परियोजनाओं में से अधिकांश भूमि अधिग्रहण की वजह से लंबित हैं। वर्ष 2017 में शुरू की गई बुलेट ट्रेन परियोजना भी इसी वजह से अटकी हुई है। इसके लिए 1,400 हेक्टेयर में से सिर्फ 0.9 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण हो सका है। देश में लंबित 100 सड़क परियोजनाओं में से 34 इसी वजह से दिक्कत में हैं। इस कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक 2015 में पेश किया गया लेकिन वह राज्यसभा में लंबित है। उस पर गठित संसदीय समिति की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं। रिपोर्ट के संसद के मौजूदा बजट सत्र में आने की उम्मीद है। संशोधन में सरकार ने निजी जमीन को पांच कार्यों में अधिगृहित करने का प्रस्ताव किया है। इनमें रक्षा, ग्रामीण परियोजनाएं, ढांचागत परियोजनाएं, औद्योगिक कारीडोर और सस्ते मकान शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबकि राज्यों ने अपना भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है जिससे स्थानीय स्तर पर कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिली है। लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में एक पारदर्शी और समग्र राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों में परिभाषाओं आदि को लेकर कोई गफलत न हो।

रिपोर्ट में सरकार से कहा गया है कि वह जल्द से जल्द संशोधित कानून को पारित करवाने की कोशिश करे। इसके लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं। एक सुझाव यह है कि जिन पांच उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण की जाएगी, उनकी परिभाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 60 फीसद से ज्यादा लोगों की सहमति को ही अधिग्रहण के लिए अनिवार्य माना जाना चाहिए। संशोधन में अधिग्रहण प्रक्रिया को 42 महीने में पूरा करने की बात है। इकोरैप के मुताबिक यह अवधि 12 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मुआवजे को बाजार मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए। बाजार मूल्य से कई गुणा ज्यादा मुआवजे के प्रावधान से देश में औद्योगिक विकास की राह मुश्किल होगी।

दिक्कत

जीएसटी लागू होने के बाद नहीं हुई राजस्व में अपेक्षित वृद्धि, जीएसटी काउंसिल कर सकती है हाइब्रिड कारों पर जीएसटी की दर की समीक्षा

हाइब्रिड कारों पर ऊंची जीएसटी से नहीं हुआ फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आमतौर पर यह माना जाता है कि टैक्स की दर अधिक होने से खजाने में राजस्व अधिक आएगा, लेकिन हर मामले में ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद हाइब्रिड कारों पर टैक्स की दर काफी बढ़ा दी। लेकिन इससे खजाने में आने वाली राशि बढ़ने के बजाय कम हो गई है। यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल आने वाली बैठक में हाइब्रिड कारों पर जीएसटी की दरें तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है।

सूत्रों ने कहा कि काउंसिल 21 जून को होने वाली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है क्योंकि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी की दर बढ़ने से ऐसे वाहनों से प्राप्त होने वाली टैक्स राशि में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि ऐसे वाहनों पर टैक्स की दर अधिक होने के चलते उनकी मांग में भी व्यापक गिरावट आई है।

सूत्रों ने कार कंपनी टोयोटा की कैमरी कार पर जीएसटी की उच्च दर का उदाहरण देते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने से पूर्व पहली जनवरी, 2016 से जून, 2017 तक 18 महीने में कंपनी ने कैमरी पर केंद्र और राज्य सरकारों को लगभग 78 करोड़ रुपये टैक्स का भुगतान किया था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर दिसंबर, 2018 के दौरान यह आंकड़ा घटकर 51 करोड़ रुपये रह गया।

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने से पूर्व हाइब्रिड कारों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट दोनों की कुल दर अलग-अलग राज्यों में 20 से 28 फीसद थी। सरकार ने हाइब्रिड वाहनों को जीएसटी की 28 फीसद की स्लैब में रखते हुए इन पर 15 फीसद की दर से क्षतिपूर्ति सैस लगा दिया जिससे इन पर कुल टैक्स बढ़कर 43 फीसद हो गया। इसके चलते इन वाहनों की कीमत में काफी इजाफा हो गया। इससे राजस्व पर असर पड़ा। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी लागू होने से ठीक पहले 18 महीने में 1900 से अधिक टोयोटा कैमरी की बिक्री हुई। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद के 18 महीनों में यह आंकड़ा घटकर मात्र 482 रह गया। इसके चलते टैक्स की दर अधिक होने बावजूद सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा। सूत्रों ने कहा कि काउंसिल आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह की टैक्स संरचना का अध्ययन कर उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय कर सकती है।

टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड की

6 आतंकियों को दस साल की कैद हुई है जमात-ए-मुजाहिद्दीन-बांग्लादेश के। पुलिस ने इन्हें सीमावर्ती जिले चपाई नवाबगंज से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद प्रशासन ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता वांग जेल से रिहा

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वांग को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि वह चीन समर्थित सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होंगे। हांगकांग में इन दिनों प्रत्यर्पण कानून को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विवादास्पद कानून में आरोपितों और संदिग्धों को मुकदमा चलाने के लिए चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है।

वांग ने भी हांगकांग की कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, 'लैम हांगकांग की नेता बने रहने के योग्य नहीं हैं।' हांगकांग में 2014 में लोकतंत्र के समर्थन में बड़ा आंदोलन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने तब व्यापक लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर शहर में दो माह तक विरोध प्रदर्शन किया था। इससे पूरा हांगकांग ठहर गया था। इस आंदोलन की अगुआई करने के लिए वांग को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया है।

हांगकांग में सोमवार को रिहाई के बाद जेल से बाहर आते लोकतंत्र समर्थक पूर्व छात्र जोशुआ वांग। इन्हें अंब्रेला मूवमेंट का जनक माना जाता है। रायटर

हांगकांग में सोमवार को लोकतंत्र समर्थक पूर्व छात्र जोशुआ वांग की रिहाई के बाद विधायी काउंसिल के बाहर उनका भाषण सुनने आए समर्थक। एपी

लैम के दफ्तर के बाहर जमा हैं प्रदर्शनकारी : हांगकांग की कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम के इस्तीफे की मांग और प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ रविवार को लाखों लोगों ने रैली निकाली थी। आयोजकों ने यह दावा किया था कि सरकार विरोधी इस रैली में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अपनी मांग को लेकर लैम के दफ्तर के पास सोमवार को भी सैकड़ों लोग जमा रहे।

इंडोनेशिया ने भी कनाडा से आया 100 टन कचरा लौटाया

जकार्ता, रायटर : इंडोनेशिया ने कनाडा से रद्दी के नाम पर भेजा गया 100 टन कचरा वापस लौटा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका के रास्ते भेजे गए कचरे में भारी मात्रा में प्लास्टिक, रबर जैसे हानिकारक पदार्थ थे। मंत्रालय ने कहा, 'कनाडा से रद्दी आनी थी लेकिन उसकी जगह प्लास्टिक की बोतलें और हानिकारक पदार्थ आए। इसलिए उसे वापस कनाडा भेज दिया गया। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इंडोनेशिया कचरे का आयात नहीं करता।'

इंडोनेशिया किसी देश से आया कचरा लौटाने वाला पहला दक्षिण-एशियाई देश नहीं है। इससे पहले मलेशिया ने अमीर देशों से आया करीब तीन हजार टन प्लास्टिक कचरा वापस भेजने की घोषणा की थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने भी अपनी सरकार को 69 कंटेनर कचरा वापस कनाडा भेजने का आदेश दिया है। दरअसल, चीन ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के चलते सालाना कई लाख टन के कचरे के निस्तारण को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। इसी वजह से कई देश अपना कचरा ठिकाने लगाने के लिए जगह तलाश रहे हैं।

पाक में सेना की आलोचना करने वाले ब्लॉगर की हत्या

- राजधानी के जंगल में छुरे से किया गया हमला, चचेरे भाई की हालत गंभीर

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार रात 22 साल के ब्लॉगर और पत्रकार मुहम्मद बिलाल खान की हत्या कर दी गई। बिलाल मुल्क की ताकतवर सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ के आलोचक के तौर पर चर्चित थे।

डॉन अखबार में पुलिस अधीक्षक सदर मलिक नईम के हवाले से कहा गया है कि बिलाल को रविवार रात किसी का फोन आया था। इसके बाद वह अपने चचेरे भाई के साथ इस्लामाबाद के जी-9 इलाके गए थे। वहां एक व्यक्ति मिला जो उन्हें जंगल में ले गया, जहां खान और उनके चचेरे भाई पर छुरे से हमला किया गया। इस हमले में खान की मौत हो गई और उनका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुछ लोगों ने गोलियां चलने की आवाज भी सुनीं। पुलिस ने आतंक रोधी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बिलाल के पिता ने कहा, 'मेरे बेटे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पैगंबर के बारे में बोला था।'

सोशल मीडिया में सेना और आइएसआइ पर फूटा गुस्सा : बिलाल की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस

मुहम्मद बिलाल खान। फाइल

फॉरमुहम्मदबिलालखान ट्रेंड करने लगा। कई ट्विटर यूजरों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आइएसआइ) की आलोचना के चलते ही खान की हत्या की गई है।

ट्विटर पर 16 हजार फॉलोअर : बिलाल खान को ट्विटर पर 16 हजार और फेसबुक पर 22 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते थे। उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करने वालों की संख्या 48 हजार से ज्यादा थी।

न्यूज गैलरी

चीन के राष्ट्रपति इस सप्ताह जाएंगे उत्तर कोरिया

बीजिंग : चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह दो दिन के दौरे पर उत्तर कोरिया जाएंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि चिनफिंग गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर कोरिया के दौरे पर होंगे। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में किसी चीनी राष्ट्रपति का यह पहला उत्तर कोरियाई दौरा होगा। इस दौरे के लिए उन्हें उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने न्योता दिया था। चीन और उत्तर कोरिया के बीच करीबी संबंध रहे हैं। चीन दुनिया के हर मंच पर उत्तर कोरिया का बचाव करता रहा है। (एएफपी)

नाइजीरिया में आत्मघाती हमले में 30 की मौत

कानो : नाइजीरिया में रविवार को एक आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत हो गई। बोर्नो प्रांत की राजधानी मैदुगुरी से 38 किलोमीटर दूर कोंदुगा में फुटबॉल मैच देख रहे लोगों को इस हमले का निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। नाइजीरिया का एक बड़ा इलाका लंबे समय से आतंकवाद की चपेट में रहा है। (एएफपी)

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मुर्सी का कोर्ट में सुवाई के दौरान निधन

काइरो : मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति और मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी का कोर्ट में सुनवाई के दौरान निधन हो गया। मुर्सी को 2012 में देश का राष्ट्रपति चुना गया था। यह चुनाव मिस्र के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे होस्नी मुबारक को पद से हटाने के बाद हुआ था। (एपी)

ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार : अमेरिका

तेल टैंकर मामला ▶ पोंपियो ने कहा, हमले का जवाब देना जरूरी

ईरान ने कहा- आर्थिक आतंकवाद की नीति पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका ने लगाए आरोप

वाशिंगटन, आइएएनएस : ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों पर हमले के जवाब में अमेरिका, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने यहां कहा, 'तेल टैंकरों पर हुए हमले का करारा जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बारे में सूचित किया गया है।'

पोंपियो ने यह भी कहा कि हमले का जवाब दिया जाना जरूरी है लेकिन हम ईरान के साथ तनाव और नहीं बढ़ाना चाहते। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पोंपियो ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया है। हम युद्ध नहीं चाहते।' हाल में होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के करीब तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि ईरान ने इससे साफ इन्कार किया है।

ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक आतंकवाद की नीति पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका यह आरोप लगा रहा है। वर्ष 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इसकी वजह से दोनों देशों में टकराव की स्थिति है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो। एएफपी

सऊदी के प्रिंस सलमान ने लगाए थे आरोप

इससे एक दिन पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर आरोप लगाया था कि जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो के स्वागत में ईरान ने जापान के ही टैंकर पर हमला कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में एबी शिंजो बीते हफ्ते ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे। इसी दौरान टैंकरों पर हमले का मामला सामने आया। सऊदी प्रिंस ने कहा, 'हम क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने लोगों, अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हितों पर कोई खतरा दिखा, तो हम उससे निपटने में हिचकेंगे नहीं।' इससे पहले अमेरिका भी इस हमले में ईरान का हाथ बता चुका है।

नेतन्याहू ने ट्रंप पर रखा गोलान की पहाड़ियों का नाम

तेलअवीव, आइएएनएस : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक रूप से विवादित गोलान पहाड़ी क्षेत्र की एक बस्ती का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि गोलान की बस्ती को 'रामत ट्रंप' के नाम से जाना जाएगा। नेतन्याहू ने रविवार को कहा, 'हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में गोलान पहाड़ियों में एक नई बस्ती बसाने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिन है। ट्रंप के नाम पर बस्ती स्थापित करना अमेरिकी राष्ट्रपति के उन फैसलों के प्रति सम्मान जाहिर करना है जो इजरायल के हित में रहे हैं।' यरुशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के साथ ही ट्रंप गोलान पहाड़ियों पर उसके अधिकार पर भी अपनी मुहर लगा चुके हैं। ट्रंप के इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तीखी आलोचना की थी। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण गोलान पहाड़ियों को इजरायल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से जीत लिया था। इसके बाद इजरायल ने 1981 में इस क्षेत्र को अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय जगत में इसका प्रबल विरोध होने पर यथास्थिति बहाल कर दी गई थी।

ईरान ने दी धमकी-दस दिन बढ़ा देंगे यूरेनियम संवर्द्धन

- दी धमकी, कहा- समझौते को यूरोप बचाना चाहे तो बचा ले
- अमेरिका ने कहा, ईरान कर रहा ब्लैकमेलिंग

दुबई, रायटर/एएफपी : ईरान ने कहा है कि जो माहौल बन गया है उसमें वह दस दिन बाद से यूरेनियम संवर्द्धन की मात्रा बढ़ा देगा। यूरोप अगर उसके साथ हुए परमाणु समझौते को बचाना चाहे तो बचा ले। यूरोपीय देशों से ईरान का आशय ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से है जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं। ये देश ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते में शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान की ताजा बयान को ब्लैकमेलिंग की संज्ञा दी है। जबकि इजरायल ने ईरान के रुख को गंभीरता से लेने की बात कही है। कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी अब प्रतिबंधों को बढ़ाए।

ईरान ने हाल ही में दो तेल टैंकरों और मई में हुए चार टैंकरों पर हमले की घटनाओं में अपना हाथ होने से एक बार फिर इन्कार किया है। हालांकि अमेरिका अपने दावे पर अड़ा हुआ है कि इन हमलों को ईरान ने अंजाम दिया है। ईरानी सेनाओं के प्रमुख मेजर जनरल मुहम्मद बकेरी ने कहा है कि तेहरान किसी तेल जहाज पर हमला क्यों करेगा। अगर वह इलाके से जहाजों का आवागमन रोकना चाहेगा तो होरमूज के समुद्री रास्ते को बंद कर देगा, जो उसके अधिकार में है। ऐसा वह सार्वजनिक बयान जारी कर करेगा। ईरान की सुप्रीम सिक्युरिटी कौंसिल के सचिव अली शामखानी ने कहा है कि खाड़ी की सुरक्षा का उनका देश जिम्मा लेता है लेकिन इसके लिए अमेरिकी सेनाएं इलाका छोड़ दें। अमेरिका के साथ संबंधों में

बेहरूज कमलवंदी। फाइल

तनातनी के बीच ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमलवंदी ने कहा है कि हम दस दिन बाद से 300 किलोग्राम प्रतिदिन से ज्यादा यूरेनियम का संवर्द्धन शुरू कर देंगे। उल्लेखनीय है कि परमाणु बम बनाने के लिए संवर्द्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। 2015 में अमेरिका समेत दुनिया के शक्तिशाली देशों ने ईरान के यूरेनियम संवर्द्धन की सीमा तय कर दी थी, बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए थे। इन देशों को आशंका थी कि ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अमेरिका अब इस समझौते से अलग हो गया है और उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

चीनी शौहर ने पाकिस्तानी युवती को वेश्यावृत्ति में धकेला

फैसलाबाद, एपी : पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर की 19 साल की नताशा मसीह के गरीब मां-बाप ने चंद रुपयों के लालच में अपनी बेटी की शादी एक चीनी से करा दी थी। उन्हें लगा था कि विदेश जाकर उनकी बेटी आराम से रहेगी लेकिन हुआ इसका उल्टा। मसीह का पति ना सिर्फ उसे मारता-पीटता था बल्कि उसे वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर करता था। यह सब सहने वाली नताशा अकेली नहीं है। उसके जैसी सैकड़ों ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां हैं जिनकी शादी के नाम पर चीन में तस्करी की जा रही है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां पाकिस्तान के सबसे गरीब ईसाई समुदाय की हैं।

पाकिस्तान और चीन के दलाल आपसी मिलीभगत कर देश में मानव तस्करी का गिरोह चला रहे हैं। वह गरीब परिवारों को रुपयों का लालच देकर उनकी बेटियों से चीनी नागरिकों की शादी कराते हैं। फिर उन लड़कियों को चीन भेज दिया जाता है जहां उनके पति जबरन उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। पंजाब प्रांत के मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एजाज आलम के अनुसार अब तक 500 लड़कियों की चीन में तस्करी की जा चुकी है। कुछ कार्यकर्ताओं के अनुसार यह आंकड़ा हजार तक पहुंच गया है।

जांचकर्ताओं को चुप रहने का आदेश : नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन से भारी आर्थिक मदद मिल रही है। पाक सरकार दोनों देशों के आर्थिक संबंध खराब नहीं करना चाहती।

चीन ने किया इन्कार : पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने लड़कियों की तस्करी होने के आरोप से इन्कार किया है। इस महीने पाकिस्तान आए चीन के उपराष्ट्रपति वांग क्वीशन ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

चांद आधारित कैलेंडर को लेकर पाकिस्तान में उभरा विवाद

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान सरकार के बनाए ल्यूनर कैलेंडर (चांद की स्थिति बताने वाले) को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को उसकी विश्वसनीयता को पेशावर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कैलेंडर इस्लामी मान्यताओं के अनुसार नहीं है। इस्लामी मान्यताओं को दरकिनार करने के लिए देश के विज्ञान और तकनीक मामलों के मंत्री फवाद चौधरी को तत्काल बर्खास्त किया जाए।

फवाद चौधरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खास सहयोगी हैं और उन्होंने ही मई में कैलेंडर और चांद को दिखाने वाली वेबसाइट लांच की थी। सरकार के इस कदम पर पाकिस्तान के तमाम मौलाना और मौलवियों ने नाराजगी जताई थी। मई में ही फवाद ने घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान में पांच जून को ईद मनाई जाएगी जबकि सऊदी अरब ने चार जून को ईद मनाई। उल्लेखनीय है कि सुन्नी इस्लामी जगत में सऊदी अरब की मान्यताओं को ही तवज्जो दी जाती है।

फवाद चौधरी। फाइल

याचिकाकर्ता ने कहा है कि मंत्री ने पहले ईद-उल-फितर पांच जून को मनाने के लिए लोगों पर दबाव डाला, अब वह ईद-उल-अजहा 12 अगस्त को मनाए जाने के लिए माहौल बना रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को ऐसी किसी घोषणा करने से रोके और हज करने की तारीख में सरकारी दखल न होने दे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कुरान पढ़े बगैर ही मंत्री ईद की तारीख घोषित कर रहे हैं। यह पूरी तरह से गैर इस्लामी कदम है। याचिका में ल्यूनर कैलेंडर को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।

शिक्षा नीति के विरोध में हड़ताल

फ्रांस के रेंस शहर में सोमवार को हजारों शिक्षकों ने फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री जीन-मिशेल ब्लांकेर की नीतियों के विरोध में देश की सबसे प्रमुख परीक्षा फ्रेंच जनरल बैक्लेरॉएट (बीएसी) के प्रथम दिन प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिक्षकों ने स्लोगन लिखे प्ले कार्ड ले रखे थे जिन पर लिखा था, 'सस्ती शिक्षा, खतरे में समाज'। दरअसल, इसी साल फरवरी में शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रणाली में सुधार के लिए कानून पारित कराया था, जिसे लोई ब्लांकेर कहा जाता है। इसको लेकर शिक्षक और अभिभावक दोनों नाराज हैं। अप्रैल माह में भी नई शिक्षा प्रणाली को लेकर देशव्यापी हड़ताल की गई थी। रायटर

भारत को नाटो मित्र जैसा दर्जा देने की तैयारी

बिल किया गया पेश
- अमेरिका में सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर लाए प्रस्ताव
- पारित हुआ तो भारत को मिलेगी अत्याधुनिक हथियार

वाशिंगटन, प्रेट्र : रूसी हथियारों की खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भले ही चिक-चिक चल रही हो लेकिन दोनों देशों के संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाने की मुहिम में कहीं से फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद सीनेट (संसद) में भारत को नाटो सहयोगियों की बराबरी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव लाए हैं। अगर यह प्रस्ताव पारित हुआ तो भारत को अत्याधुनिक हथियार और संवेदनशील तकनीक देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अमेरिका आर्म्स कंट्रोल एक्ट में संशोधन का यह प्रस्ताव डेमोक्रेट मार्क वार्नर और रिपब्लिकन जॉन कॉर्निन ने रखा है। प्रस्ताव में भारत को अमेरिका के बड़े रक्षा सहयोगी से ऊपर का दर्जा देने का प्रावधान है। प्रस्ताव के अनुसार भारत को नाटो सहयोगी वाला दर्जा मिलेगा। इसके चलते भारत अमेरिका का इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया जैसा सहयोगी हो जाएगा। तब भारत अमेरिका से नाटो सहयोगियों जैसे अत्याधुनिक हथियार और संवेदनशील तकनीक प्राप्त कर सकेगा।

ज्ञात हो, अमेरिका ने अपना अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टीएचएएडी (थाड) अभी तक दक्षिण कोरिया में ही तैनात किया है। रूस के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बदले अमेरिका ने अपना यह सिस्टम देने का प्रस्ताव भी भारत के समक्ष रखा है। संभव है कि इसी प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए अमेरिकी संसद में भारत से सहयोग का दर्जा बढ़ाने की कवायद हो रही हो।

इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ 2018 में कम्युनिकेशंस, कॉम्पैटिलिटी एंड सिक्युरिटी एग्रीमेंट किया था। इसके चलते दोनों देश संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहे हैं। भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में काफी मदद मिल रही है। दोनों देश बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी दस्तखत करने के काफी करीब हैं। इससे सहयोग का दायरा और विस्तृत हो जाएगा। यह सब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले हफ्ते जापान में जी 20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से ऐन पहले हो रहा है। अगले सप्ताह ही अमेरिकी विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने पिछले दिनों मोदी है तो मुमकिन है का नारा देकर भारत और अमेरिका के बीच गर्मजोशी वाले संबंधों का संकेत दिया था। भारत में गत आम चुनाव के दौरान भाजपा ने मोदी है तो मुमकिन का नारा दिया था। पोंपियो ने इसी का जिक्र अपनी बात कहने के लिए किया।

सख्ती के बाद वीजा मिलने के इंतजार में अमेरिका में फंस गए हैं सैकड़ों विदेशी छात्र

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वीजा नीति में सख्ती देखने को मिल रही है। इससे छात्र वीजा भी अछूता नहीं रहा है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए सैकड़ों छात्रों को वीजा का इंतजार है, लेकिन इस साल वीजा प्रक्रिया में ज्यादा समय लग रहा है। इससे काफी छात्र अमेरिका में फंस गए हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी हैं।

विदेशी छात्रों ने अमेरिका के कई शीर्ष विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर बताया है कि उनके इंटर्नशिप की तारीखें बीत गईं लेकिन संघीय सरकार ने वीजा देरी पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें अपने रोजाना के खर्च के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को नौकरी का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वीजा के इंतजार में उन्हें स्वदेश वापसी के लिए विवश होना पड़ रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले चीनी छात्र यलिंग जियांग ने कहा, 'हर सुबह मैं इसी चिंता के साथ उठता हूं कि आज क्या करने जा रहा हूं? कब मैं काम शुरू करूंगा?' कोलंबिया से ही स्नातक करने वाली भारतीय छात्रा जीविका वर्मा (23) ने कहा, 'जब आप इंटर्न के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप आगे कदम बढ़ाने के लिए सक्षम होना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शुरुआत नहीं कर सकती।'

वीजा का कई भारतीय छात्रों को भी इंतजार है।

पांच माह तक लगने का अनुमान

वीजा मामलों को देखने वाली एजेंसी अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) के एक अधिकारी ने कहा कि वीजा प्रक्रिया में पांच महीने तक का वक्त लगने का अनुमान है। यह बड़ी संख्या में आवेदन मिलने का नतीजा है।

पहले अधिकतम 90 दिन करना पड़ता था इंतजार

अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने या नौकरी शुरू करने से 90 दिन पहले विदेशी छात्र काम करने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले अधिकतम 90 दिन इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आमतौर पर 60 दिनों के अंदर ही काम करने की अनुमति मिल जाती थी।

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्रिस्टोफर एल की अगुआई में न्यूजर्सी के कई कॉलेजों ने सांसदों को पत्र लिखकर कहा है कि वीजा में देरी के बढ़ते मामले परेशान करने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन में विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ने और काम करने की राह में बाधा खड़ी हो रही है।

वीजा प्रक्रिया में लग रहा ज्यादा वक्त : कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने कहा कि अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। पिछले दो साल के दौरान विदेशी छात्रों की वीजा प्रक्रिया में लगने वाले समय में 46 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिका में 17 फीसद भारतीय छात्र : अमेरिका में पिछले साल करीब दस लाख 78 हजार विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया था। इनमें करीब 17 फीसद भारतीय छात्र हैं।

कनाडाई प्रांत में सरकारी कर्मियों के धार्मिक पहनावे पर रोक

- क्यूबेक में बुर्का, हिजाब, पगड़ी, टोपी और क्रॉस पहनने पर रोक
- प्रांतीय सरकार ने धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए बताया जरूरी

मॉन्ट्रियल : कनाडा के क्यूबेक प्रांत में स्कूल शिक्षकों, पुलिस कर्मियों और जजों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों के धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रांतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून रविवार को 35 के मुकाबले 73 वोटों से पारित हो गया। इस कानून में मुस्लिमों के बुर्का व हिजाब, सिखों की पगड़ी, यहूदियों की टोपी और ईसाइयों के क्रॉस समेत सभी तरह के धार्मिक चिह्नों या पहनावे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रांतीय सरकार के प्रमुख फ्रैंकाइस लीगॉल्ट ने इस कानून की पैरवी करते हुए कहा कि सरकार को धर्मनिरपेक्ष रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस कानून को नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात बताया है।

मानवाधिकार और धार्मिक संगठनों का कहना है कि यह कानून कनाडा की बहु-सांस्कृतिक छवि को खराब करेगा। इसके चलते सिख, मुस्लिम और यहूदी अपना सरकारी पद छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।

कई लोग समर्थन में भी

कानून के समर्थकों के अनुसार उदारवादी सिद्धांतों को बचाकर रखने के लिए यह जरूरी है। मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमानी बेन अम्मार ने कहा, 'सरकारी कर्मियों का निष्पक्ष रहना जरूरी है। यह तभी संभव है जब वह किसी तरह का धार्मिक चिह्न या पहनावा ना पहने।'

मॉन्ट्रियल के कई सरकारी अधिकारियों, मेयर और स्कूल बोर्ड ने इस कानून को लागू नहीं होने देने की बात की है। ऐसे में प्रांत में सांस्कृतिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इस कानून के विरोध में गत अप्रैल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक चिह्न पहनना व्यक्ति का निजी फैसला है, इससे उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। नेशनल काउंसिल ऑफ कनाडियन मुस्लिम और द कनाडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन के साथ कुछ वकील भी कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इस बिल में 'नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज' का इस्तेमाल किया है। संविधान में इसके तहत प्रांतीय सरकारों को धार्मिक और अभिव्यक्ति से जुड़ी कुछ स्वतंत्रताएं रद करने का अधिकार दिया गया है।

ये भी जानिए
इंग्लैंड व अफगानिस्तान के बीच एक ही वनडे मैच खेला गया है। बारिश से प्रभावित यह मैच 2015 विश्व कप में खेला गया था जिसमें इंग्लैंड नौ विकेट से जीता था।

कमजोर पाकिस्तान खत्म कर रहा रोमांच

भारत और पाक के बीच मैदान में कम हो रहा है प्रतिद्वंद्विता का रोमांच हारने के बावजूद लड़ती थी इमरान और अकरम की टीमें

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी ● मैनचेस्टर

एक दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में रोंगटे खड़े कर देने वाली भिड़ंत देखने को मिलती थी। मैच की आखिरी गेंद तक पता नहीं चलता था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी लेकिन समय के साथ वह दौर और वह प्रतिद्वंद्विता खत्म होती जा रही है। क्रिकेट के जानकार इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होना बता रहे हैं लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि टीम इंडिया ने अपने रुतबे को इतना बड़ा कर लिया है कि क्रिकेट के मैदान में उसके सामने हर टीम बौनी नजर आ रही है। वहीं, पाकिस्तान की टीम का कमजोर होना भी इस रोचकता को खत्म कर रहा है।

पाकिस्तानी प्रशंसकों में निराशा : हमेशा की तरह इस बार भी जब विश्व कप में भारत-पाक की टीमें मैनचेस्टर में भिड़ने पहुंची थीं तो दोनों देशों के प्रशंसक पूरे उत्साह के साथ टीमों का समर्थन करने पहुंचे लेकिन एकबार फिर पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। एकतरफा मुकाबले में भारत 89 रनों से जीता और पाकिस्तानी समर्थक एकबार फिर अपनी टीम को बुरा-भला कहते हुए वापस लौटे। एक प्रशंसक ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खाने-पीने से फुरसत नहीं है और वह अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिकेट छोड़कर कुश्ती लड़नी चाहिए। उधर, पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी टीम की हार से मायूस है और भारत के खिलाफ हार की वजह कप्तान सरफराज अहमद के साथ कई खिलाड़ियों के झगड़े को बता रही है।

लड़कर हारती थी इमरान-अकरम की टीम : एक समय था जब इमरान खान और वसीम अकरम की अगुआई वाली टीम में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के बारे में भारतीय प्रशंसकों तक को भी पता होता था लेकिन आज सरफराज अहमद की पूरी टीम के बारे में शायद ही भारतीय प्रशंसक जानते हों। द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने के बावजूद आइसीसी टूर्नामेंट के पिछले छह वनडे में से पांच बार भारत ने पाक को हराया है। इसमें सिर्फ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ओवल में भारत को हार मिली थी। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले एकतरफा ही रहे हैं लेकिन वह दौर भी था जब दोनों देशों के बीच आखिरी गेंद पर फैसले होते थे। 2007 के टी-20 विश्व कप के ग्रुप चरण में टाई होने के बाद मुकाबले का फैसला बॉल आउट के जरिये हुआ था जहां भारत ने बाजी मारी थी। वहीं, खिताबी मुकाबले का रोमांच आखिरी ओवर तक चला था जहां भारत चैंपियन बना था। 2011 विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला भी पाकिस्तान ने लड़कर गंवाया था लेकिन 2015 और अब 2019 के नतीजे एकतरफा रहे। चार साल पहले विश्व कप में भारत 76 रनों से जीता था।

उलझन में थे सरफराज : सचिन

मैनचेस्टर : मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में उलझन में थे और उनकी टीम में कोई सूझ-बूझ नहीं दिखी। मैच के बाद एक टीवी इंटरव्यू में सचिन ने कहा 'मुझे लगा कि सरफराज कन्फ्यूज (उलझन) में थे क्योंकि जब वहाब रियाज गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने शॉर्ट मिडविकेट पर फील्डर लगा रखा था। इसके बाद जब शादाब खान आए तो उन्होंने स्लिप में एक फील्डर लगाया। ऐसे हालात में लेग स्पिनर के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल होता है, खासकर जब सही लाइन और लेंथ नहीं हो। यह बड़े मैच में खेलने का सही तरीका नहीं है। उनके पास सूझ-बूझ का बिल्कुल अभाव दिखा।' तेंदुलकर ने कहा कि पाकिस्तान का कोई गेंदबाज परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सका और उन्हें कभी नहीं लगा कि भारत के विकेट विरोधी टीम की रणनीति की वजह से गिरे। उन्होंने कहा, 'गेंद अगर घूम नहीं रही है तो आप ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी नहीं रख सकते। वहाब ने विकेट के आस-पास गेंद डालने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका थी। हसन अली ही इकलौते गेंदबाज थे जिनकी गेंदें घूम रही थीं। ऐसे में अगर मैं होता तो उसे कोण बदलकर कुछ अलग तरह की गेंदबाजी करने को कहता।'

पाक की मदद के लिए आगे आए मुक्केबाज आमिर

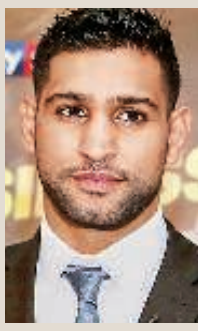

मैनचेस्टर : खराब दौर से गुजर रही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ब्रिटेन के मुक्केबाज आमिर खान ने मदद करने पेशकश करते हुए कहा कि वह फिटनेस और एकाग्रता बढाने में टीम की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी मूल के इस मुक्केबाज ने भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के सामने यह पेशकश रखी। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फिटनेस और मजबूती बनाए रखने के लिए सुझाव देने पर मुझे खुशी होगी। मैं टीम को खाना, डाइट और प्रशिक्षण जैसी चीजों के बारे में बता सकता हूं। टीम के पास कौशल है लेकिन उन्हें फिटनेस और एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। आमिर का जन्म और लालन-पालन मैनचेस्टर में हुआ है। उन्होंने ब्रिटेन के लिए ओलंपिक में रजत पदक जीता है जिनका पेशेवर सर्किट में अगला मुकाबला भारत के नीरज गोयत से है। उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट में मिली हार का बदला अगले महीने जेद्दाह में होने वाले मुकाबले में लेंगे।

सरफराज ने माना, बेहतर है भारतीय टीम

मैनचेस्टर : भारत से मिली हार को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद की जमकर आलोचना हो रही है। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या इतने साल में भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता का रोमांच खत्म हो गया है तो सरफराज ने कहा कि हम दबाव का ठीक से सामना नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के मैचों में दबाव का सामना करने वाली टीम जीतती है। पाकिस्तान की टीम बीती सदी के अंतिम दशक में बेहतर थी लेकिन अब भारतीय टीम हमसे अच्छी है और यही वजह है कि वे जीत रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान ने अपनी टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की सलाह दी थी लेकिन सरफराज ने पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि तीनों विभागों में नाकामी के कारण उनकी टीम हारी। सरफराज ने कहा कि पूरी टीम तीनों विभागों में अच्छा नहीं खेल पा रही है। यदि आप क्षेत्ररक्षण की बात करें तो विराट कोहली ने भी कहा था कि वह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते। पिच पर नमी थी लिहाजा मैंने क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया लेकिन गेंदबाज अनुशासित प्रदर्शन नहीं कर सके। उधर, टीम की फिटनेस के सवाल पर सरफराज ने कहा कि किसी के साथ फिटनेस का कोई मसला नहीं था। इमाद वसीम को पेट संबंधी तकलीफ थी लेकिन बाकी सभी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था। अब हारने पर तो आप कोई भी मसला उठा सकते हैं। सरफराज ने आने वाले चार मैचों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उधर, पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपनी टीम की हार पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक है। बारिश के बाद जब हम दोबारा खेलने आए तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अब इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हमारे पास गलती करने की कोई संभावना नहीं बची है।

पाक पर एक और स्ट्राइक : अमित शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद देशभर से टीम इंडिया को शुभकामनाएं मिल रही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की इस जीत को पाकिस्तान पर किया गया एक और स्ट्राइक बताया है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि टीम इंडिया की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक और परिणाम पहले जैसा ही रहा। पूरी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन पर बहुत-बहुत बधाई। देश का हर नागरिक इस जीत पर गर्व महसूस कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय टीम की इस जीत पर हम सभी को गर्व है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि मैने पहले से बोला था, हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा! शानदार प्रदर्शन। टीम इंडिया को बधाई।

पाकिस्तानी कप्तान पर भड़के शोएब अख्तर

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत से मिली हार को सरफराज अहमद की बेवकूफाना कप्तानी को कसूरवार ठहराया। शोएब ने कहा, 'मुझे समझ में नहीं आता कि कोई कप्तान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। सरफराज को क्या पता नहीं था कि हम लक्ष्य का पीछा करने में कितने कमजोर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी है। आप टॉस जीतकर आधा मैच तो वही जीत गए लेकिन उसके बाद आपने क्या किया। आपने मैच हारने की पूरी कोशिश की। बेवकूफाना कप्तानी और बेवकूफाना प्रबंधन।'

भारत की सफलता के पीछे आइपीएल : अफरीदी

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने आइपीएल को विश्व क्रिकेट में भारत के आगे बढ़ने का कारण बताया है। विश्व कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद अफरीदी ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि आइपीएल युवा खिलाड़ियों को दबाव से जूझना सिखा रहा है। अफरीदी ने मैच के बाद ट्विटर पर लिखा जीत के लिए बीसीसीआइ को शुभकामनाएं। भारतीय टीम ने बहुत उच्च स्तर की क्रिकेट खेली और इसका श्रेय आइपीएल को जाता है। यह न केवल प्रतिभा को खोजने और निखारने का काम करता है बल्कि युवा खिलाड़ियों को दबाव झेलना भी सिखाता है। इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारत द्वारा दिए गए ध्यान को उसकी सफलता राज बताया।

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ● फाइल फोटो, एपी

स्टीव स्मिथ ने की विराट की प्रशंसा

लंदन, प्रेट्र : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ नौ जून को विश्व कप के मुकाबले के दौरान उनके खिलाफ हूटिंग कर रहे दर्शकों से ऐसा नहीं करने की विराट कोहली की अपील को सराहनीय काम करार दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ के विवादास्पद मामले के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी करने वाले स्मिथ को प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के प्रत्येक मैदान पर दर्शकों की हूटिंग झेलनी पड़ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को भी दर्शकों ने स्मिथ को धोखेबाज कहा था, तब ऑस्ट्रेलियाई टीम क्षेत्ररक्षण कर रही थी। कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका और इसके बजाय उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने को कहा। स्मिथ ने कहा, 'विराट ने दर्शकों की हूटिंग को रोककर सराहनीय काम किया है। सच्चाई से कहूं तो दर्शक क्या कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उसे नजरअंदाज कर रहा हूं लेकिन कोहली ने शानदार काम किया।'

वॉ बोले, खुलकर नहीं खेल रहे वार्नर : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि डेविड वार्नर मौजूदा विश्व कप में दूसरे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपनी फरारी नहीं निकाली है। वार्नर ने विश्व कप में अब तक दो अर्धशतक और एक शतकीय पारी खेली है, लेकिन वॉ ने कहा कि इस विस्फोटक बल्लेबाज ने अभी गति नहीं पकड़ी है और विश्व कप का सेमीफाइनल इसके लिए सही मंच होगा।

पिता बनने के बाद ज्यादा जिम्मेदार बने शर्मा, पाकिस्तान के खिलाफ 140 रन की खेली यादगार पारी

बेटी के जन्म के बाद से बदल गई रोहित की जिंदगी

अभिषेक त्रिपाठी ● मैनचेस्टर

रोहित शर्मा की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी उनका शांत स्वभाव रहा है। वक्त के साथ उन्होंने अपने खेल में जो स्थिरता दिखाई है वह उन्हें यूं ही हासिल नहीं हुई। करियर के शुरुआती दिनों में रोहित के आलोचकों की कमी नहीं थी। उन्हें गैरजिम्मेदार बल्लेबाज करार दिया जाता था लेकिन समय और अनुभव के साथ रोहित ने एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में खुद को विकसित किया और नतीजा सामने है। रोहित वनडे में तीन दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं। हालांकि इतनी लंबी-लंबी पारियां खेलने के बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती जबकि संयम से भरी उनकी शैली टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा सूट करती है।

पिता रोहित बने जिम्मेदार : 2019 विश्व कप में अब तक दो शतक जड़ चुके रोहित पिता बनने के बाद ज्यादा जिम्मेदार बल्लेबाज बन गए हैं और बेटी के जन्म के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। भारतीय उप कप्तान ने दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 113 गेंद में 140 रन बनाने वाले रोहित ने कहा कि मैं इस समय अपनी जिंदगी के अच्छे मुकाम पर हूं। जिंदगी में बेटी के आने से यह हुआ और मैं अपने क्रिकेट का भी पूरा मजा ले रहा हूं। एक टीम के तौर पर हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे लिए हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है और हम वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन से हम यहां हैं और पिच कवर में थी। शुरुआत में थोड़ी नमी थी। ऐसे हालात में नई गेंद काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और शुरुआती विकेट गंवाने से दबाव बन सकता था। मैं नहीं जानता की अपनी बल्लेबाजी से मैं संतुष्ट हूं कि नहीं। किसी एक पारी को सर्वश्रेष्ठ कहना कठिन है क्योंकि देश के लिए खेली गई हर पारी अहम है।

पाकिस्तान के गेंदबाज हसन अली और वहाब रियाज ने रोहित शर्मा के खिलाफ शॉर्ट पिच और बाहर जाती गेंदें डाली। इस रणनीति पर रोहित ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनकी टीम मीटिंग में क्या हुआ। वह फुल लेंथ गेंद डालना चाहते थे या शॉर्ट पिच। पहले 10 ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। हमें पता है कि इंग्लैंड में एक बार दबाव में आने के बाद गेंदबाज के लिए वापसी करना मुश्किल है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।' वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान की टीम को वह क्या सलाह देंगे तो इस पर रोहित ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान टीम का कोच बनूंगा, तब इसका जवाब दूंगा।'

वेंगसरकर बोले, रोहित ने खेली बेहतरीन पारी

मुंबई, प्रेट्र : भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की शतकीय पारी को शानदार करार दिया। वेंगसरकर ने सोमवार को कहा कि वह (रोहित) परिपक्व हो गया है। वह कई वर्षों से खेल रहा है और अनुभवी खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से है। रविवार को उसने जो पारी खेली वह कमाल की थी। भारत के लिए 116 टेस्ट खेलने वाले इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, 'यह दबाव वाला मैच था। सलामी बल्लेबाजी में रोहित के नियमित जोड़ीदार धवन चोटिल होने के कारण नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उन्होंने काफी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की। वह विश्वस्तरीय खिलाड़ी है।'

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ● फाइल फोटो, एएफपी

बाबर को आउट करने वाली गेंद सर्वश्रेष्ठ थी : कुलदीप

मैनचेस्टर : भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का कहना है कि उन्होंने जिस गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को आउट किया वो उनके लिए ख्वाब की तरह थी। कुलदीप ने एक बेहतरीन गेंद पर बाबर आजम को बोल्ड किया था और यहां से पाकिस्तान हार की तरफ जाने लगी थी। कुलदीप ने कहा कि बाबर को आउट करने वाली गेंद मेरे लिए इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गेंद थी। मैंने उसे एशिया कप में भी आउट किया था। वह स्पिन का अच्छा खिलाड़ी है। बारिश से मिले ब्रेक के बाद मैं गया और मैंने वह गेंद देखी। यह एक शानदार ख्वाब सरीखे और टेस्ट क्रिकेट की गेंद थी जिसने बल्लेबाज को हवा में छकाया और उसे गलती करने को मजबूर किया। यह एक ऐसी गेंद थी जिसे स्पिनर पसंद करते हैं। एक शानदार गेंद थी और मैं इसे याद रखूंगा।

दो दिन आराम करेंगे भारतीय खिलाड़ी

विशेष संवाददाता, मैनचेस्टर : कप्तान विराट कोहली की अगुआई में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम दो दिनों तक आराम के साथ खुद को तरोताजा करेगी। दो बार के पूर्व चैंपियन भारत ने एक और दमदार प्रदर्शन से चिर प्रतिद्वंद्वी और 1992 विश्व कप के विजेता पाकिस्तान को 89 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की ओर कदम बढ़ाया। भारतीय टीम प्रबंधन ने बताया कि टीम के खिलाड़ी दो दिन आराम करेंगे। भारत का अगला मैच 22 जून को साउथैंप्टन में अफगानिस्तान से होगा। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोट के कारण कम से कम अगले दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ जून को 117 रन की पारी खेल कर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले शिखर धवन भी अंगूठे में चोट के कारण कुछ मैचों के लिए टीम से बाहर है।

मैं अपनी गेंदबाजी से हैरान नहीं हूं : शंकर

मैनचेस्टर :भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के दो विकेट लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर को भरोसा है कि वह भारत के अभियान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शंकर ने कहा कि मुझे अपनी भूमिका में लचीलापन दिखाना होगा। मेरा मानना है कि एक क्रिकेटर होने के नाते आपको परिस्थितियों को स्वीकार करना बेहद जरूरी होता है। शंकर को अंतिम एकादश में धवन की जगह शामिल किया गया था। वहीं इस मुकाबले में भुवनेश्वर को मैदान छोड़ना पड़ा था जिसके बाद शंकर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट झटका। शंकर ने कहा कि मैं अच्छी बल्लेबाजी करता रहा हूं और गेंदबाजी एक ऐसी चीज है जो मुझे उपयोगी बनाती है। यह बहुत जरूरी है कि जब परिस्थितियां आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहूंगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप में पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ पदार्पण करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था जहां मुझे कई लोग खेलते देख रहे थे। मैंने हर पल का लुत्फ उठाने का प्रयास किया।

हार्दिक के माता-पिता बेटे के प्रदर्शन से खुश: हार्दिक पांड्या के माता-पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मैच में उनके प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या ने कहा कि हम खुश हैं कि हमारा बेटा नियंत्रित आक्रामकता के साथ खेला और भारत की जीत में मदद की।

जेंटलमैन मैच के दौरान जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज गिर गए थे तब विराट ने पूछा था उनका हालचाल

कोहली ने खेल भावना से जीता पाकिस्तानियों का दिल

विशेष संवाददाता, मैनचेस्टर : भारत और पाकिस्तान के मैच में माहौल गर्म था और दोनों तरफ तेवर तीखे थे, लेकिन इसी माहौल में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कुछ मौकों पर खेल भावना का परिचय देते हुए कई लोगों की तारीफें बटोरीं। कोहली और रोहित शर्मा की पाकिस्तानी प्रशंसकों ने उनकी बल्लेबाजी के लिए काफी तारीफें कीं, लेकिन कोहली की खेल भावना के सभी मुरीद हो गए। मैच के दौरान जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज गिर गए थे तब कोहली उनके पास उनका हालचाल पूछने पहुंचे। इस समय वहाब और कोहली ने एक दूसरे का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। इस पल को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रशंसकों ने कोहली की तारीफ की।

इसी मैच में कोहली अपने करियर के 42वें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन तभी मुहम्मद आमिर की एक गेंद कोहली के बल्ले से टकरा विकेटकीपर सरफाज अहमद के दस्तानों में चली गई। यहां अंपायर ने कोहली को आउट नहीं दिया लेकिन भारतीय कप्तान खुद ही पवेलियन की तरफ चल दिए। रिप्ले में हालांकि बताया गया था कि बल्ले और गेंद में काफी दूरी थी। सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक ने लिखा कि विराट कोहली बेहतरीन इंसान हैं। जो खेल भावना उन्होंने दिखाई है वो बहुत बड़ी है। वह जानते थे कि गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया है इसलिए उन्होंने अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं किया और पवेलियन लौट लिए। उन्होंने प्रशंसकों का दिल जीता। कोई कैसे उनसे नफरत कर सकता है।

श्रीकांत बोले, भारत से डरती हैं कई टीमें: पूर्व भारतीय बल्लेबाज के श्रीकांत का मानना है कि कई टीमें विराट कोहली की टीम से डरती हैं। उन्होंने कहा कि टीमें भारत का सामना करने से डरती हैं और ऐसा होता भी है। भारतीय टीम बहुत जल्द विरोधी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। रोहित पर श्रीकांत ने कहा कि सभी जानते हैं कि वह कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अच्छी चीज केएल राहुल थे। धवन के चोटिल होने के बाद यह सवाल था कि इस जगह कैसे भरेगी, लेकिन राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

मलिक का करियर लगभग खत्म : पूर्व खिलाड़ी

मैनचेस्टर : पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ विश्व कप मैच में पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट होने वाले शोएब मलिक की आलोचना की। दिग्गजों ने कहा कि इस अनुभवी खिलाड़ी को यह मान लेना चाहिए की उसका करियर लगभग खत्म हो गया। 37 वर्षीय मलिक ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि विश्व कप के बाद वह वनडे क्रिकेट को अलविदा कह देंगे और अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप पर ध्यान देंगे। पूर्व टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने कहा, 'उन्होंने खुद ही विश्व कप से पहले कहा था कि वह इसके बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे। टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाकी बचे चार (लीग) मैचों में मौका मिलेगा।'

भारतीय कप्तान विराट कोहली ● फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत-पाक का मैच एक तरफा मुकाबला : सहवाग

नई दिल्ली, एएनआइ : विश्व कप के मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान को हराने वाली भारतीय टीम की हर तरफ तारीफ हो रही है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि आप भारत बनाम पाक मुकाबले की विश्व कप में उम्मीद रखते हैं, तो लगता है कि यह मुकाबला नजदीकी होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि यह मुकाबला एकतरफा बन गया है।

पाकिस्तान को मिली इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हुसैन की सहानुभूति

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत के हाथों शिकस्त झेलने वाली पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की सहानुभूति मिली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस हार के बाद निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ वापसी करनी चाहिए। हुसैन ने कहा कि मैंने रविवार को भारत-पाक मुकाबले का लुत्फ लिया। यह देखकर खुशी हुई कि दोनों टीम के खिलाड़ियों और प्रशंसकों में गजब का उत्साह था। मेरी सहानुभूति पाक टीम के लिए हैं, जिन्होंने इस मैच में बहुत कुछ सहा। विश्व क्रिकेट को उनके दोबारा मजबूत होने की जरूरत है।

पाक खिलाड़ियों का बना मजाक : विश्व कप में भारत के हाथों शिकस्त झेलने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक बनना शुरू हो गया। इनमें से ट्विटर पर पाकिस्तान के लोगों ने अलग-अलग तरह से सरफराज अहमद की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम को खूब आड़े हाथों लिया। मैच में जैसे ही बारिश आई पाकिस्तान के लोगों ने अपनी टीम की खूब धज्जियां उड़ाईं। चाहें सरफराज की उबासी हो या शोएब मलिक क जीरो पर आउट होना, पाकिस्तानी प्रशंसकों ने खूब मजे लिए। एक प्रशंसक ने ट्वीट किया कि आप मुझे बेवफा मत कहिएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को देखें, वो पूरी तरह से एथलीट लग रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दो प्लेट निहारी वो भी फीके की लस्सी और बेनजीर कुल्फी खाकर आए हैं, वो भी एक बार में। पाकिस्तान के एक और समर्थक ने ट्वीट किया कि प्रिय इंडिया, थोड़ा हाथ हौले रखें.. हमारा सरफराज रो ना दे अभी। पाकिस्तानी कप्तान ने इस मैच में 30 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस पर एक यूजर ने पोस्ट किया कि जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि सरफराज मुझे कब्र में दफनाए ताकि वह एक बार और मुझे नीचा दिखा सके।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन। फाइल फोटो

जब 2016 में चार खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था तब से चीजें बदली हैं। ऐसा भी समय था तब मेरे और मौमा दास जैसे सीनियर खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे।
– शरथ कमल, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी

जोशना चिनप्पा ने जीता राष्ट्रीय खिताब

पुणे, आइएएनएस : देश की अग्रणी महिला स्क्वॉश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने रिकॉर्ड 17वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में सुनयना कुरुविल्ला को 11-5, 11-4, 7-11, 11-5 से मात दी। इस जीत से जोशन्ना ने भुवनेश्वरी कुमारी के 16 राष्ट्रीय खिताब जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भुवनेश्वरी ने 1977 से 1992 के बीच 16 राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किए थे।

गैरी वुडलैंड ने जीता 2019 यूएस ओपन गोल्फ का खिताब

यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले वुडलैंड। एपी

पेबल बीच, एएफपी : अमेरिका के गैरी वुडलैंड ने पेबल बीच गोल्फ लिंक्स पर आयोजित 2019 यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। वुडलैंड ने वर्ष 2000 के यूएस ओपन में टाइगर वुड्स द्वारा बनाए गए 12 अंडर 272 के रिकॉर्ड स्कोर को पीछे छोड़ा। वुडलैंड ने 13 अंडर स्कोर बनाया था। यह वुडलैंड का पहला बड़ा खिताब है। बता दें कि यह लगातार पांचवीं बार है, जब किसी अमेरिकी गोल्फर ने यूएस ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले 2014 में जर्मनी के मार्टिन केमर ने एक विदेशी के तौर पर यह खिताब जीता था। वुडलैंड ने खिताबी जीत के बाद कहा, 'मेरे लिए यह जीत खास है। पेबल बीच पर मिली इस सफलता से मैं बहुत खुश हूं।'

टक्कर ▸ सात विकेट से जीता बांग्लादेश, शाकिब अल हसन ने बनाए नाबाद 124 रन

बांग्लादेश ने धूमिल की विंडीज की उम्मीद

हासिल किया विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

शाकिब अल हसन और लिटोन दास की बेहतरी पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने टांटन में खेले गए मुकाबले में सोमवार को वेस्टइंडीज को सात विकेट से शिकस्त दे दी। क्रिस गेल जैसे दिग्गज बल्लेबाज के शून्य पर आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की पारी को विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप (96) ने संभाला। होप और इविन लुइस (70) के दम पर विंडीज ने बड़े स्कोर की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। बीच में शिमरोन हेटमायर ने तेजतर्रार 50 रन बनाकर उसकी उम्मीदों को और आगे पहुंचा दिया लेकिन अंतिम के ओवरों में इन सभी के न होने से एक समय 340 के आस-पास जाती दिख रही विंडीज की टीम 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 321 रन तक ही सीमित हो गई। जवाब में बांग्लादेश ने 41.3 ओवर में तीन विकेट पर 322 रन बनाकर जीत हासिल की। बांग्लादेश के लिए शाकिब ने नाबाद 124 और लिटोन दास ने नाबाद 94 रनों की पारी खेली। इसी के साथ बांग्लादेश ने विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है। जिन्होंने 2011 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 329 रन हासिल कर लिए थे।

बांग्लादेश ने शुरुआत बेहतरीन की। कप्तान मशरफे मुर्तजा ने पहले ओवर में क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को एक रन भी नहीं बनाने दिया। मुहम्मद सैफुद्दीन ने अगले ओवर की पांच गेंदों पर भी गेल का खाता नहीं खुलने दिया। सैफुद्दीन ने आखिरकार चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर गेल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। गेल ने 13 गेंदें खेलीं लेकिन खाता नहीं खोल पाए। दूसरे सलामी बल्लेबाज लुइस ने इस खराब शुरुआत का दवाब नहीं लिया और होप के साथ स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी। लुइस, शाकिब की गेंद पर इस साझेदारी को तोड़कर चलते बने। लुइस ने 67 गेंदों पर छह चौके और दो छक्कों की मदद से अर्धशतक बनाया। होप दूसरे छोर पर खड़े रहे। निकोलस पूरन ने उनका साथ देने की कोशिश की लेकिन 25 रनों के निजी स्कोर से आगे नहीं जा पाए। होप अभी भी खड़े थे लेकिन इस बार उन्हें हेटमायर का साथ मिला जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। होप और हेटमायर ने चौथे विकेट के लिए 83 रन बनाए। मुस्तफिजुर ने हेटमायर को आउट कर बांग्लादेश के गेंदबाजों को राहत दी और तीन गेंद बाद रहमान ने अपनी टीम को एक और बड़ा विकेट दिलाया। इस बार शिकार आंद्रे रसेल बने जो खाता भी नहीं खोल पाए। होप को मुस्तफिजुर ने अपना शिकार बना उन्हें चार रनों से शतक से रोक दिया। होप ने 121 गेंदों की पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। अंत में जेसन होल्डर ने 33, डेरेन ब्रावो ने 19, ओशाने थॉमस (नाबाद 06) ने टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रहे। आखिरी के पांच ओवरों में टीम ने सिर्फ 33 रन ही जोड़े। बांग्लादेश की तरफ से रहमान और सैफुद्दीन ने तीन-तीन विकेट लिए। शाकिब को दो सफलताएं मिलीं।

स्कोर बोर्ड

टॉस : बांग्लादेश (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : शाकिब अल हसन

वेस्टइंडीज — **321/8** (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्रिस गेल का. रहीम बो. सैफुद्दीन	00	13	00	00
लुइस का. सब (शब्बीर) बो. शाकिब	70	67	06	02
शाई होप का. लिटन बो. मुस्तफिजुर	96	121	04	01
निकोलस पूरन का. सरकार बो. शाकिब	25	30	02	01
शिमरोन का. तमीम बो. मुस्तफिजुर	50	26	04	03
रसेल का. मुश्फिकुर बो. मुस्तफिजुर	00	02	00	00
होल्डर का. महमूदुल्लाह बो. सैफुद्दीन	33	15	04	02
डेरेन ब्रावो बो. सैफुद्दीन	19	15	00	02
ओशाने थॉमस नाबाद	06	11	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-6, वा-16) 22

कुल : 50 ओवर में आठ विकेट पर 321 रन

विकेट पतन : 1-6 (गेल, 3.2), 2-122 (लुइस, 24.3), 3-159 (पूरन, 32.2), 4-242 (हेटमायर, 39.3), 5-243 (रसेल, 39.6), 6-282 (होल्डर, 43.4), 7-297 (शाई, 46.6), 8-321 (डेरेन, 49.6)

गेंदबाजी :
मशरफे मुर्तजा 8-1-37-0
मुहम्मद सैफुद्दीन 10-1-72-3
मुस्तफिजुर रहमान 9-0-59-3
मेहदी हसन मिराज 9-0-57-0
मुसद्दक हुसैन 6-0-36-0
शाकिब अल हसन 8-0-54-2

परिणाम : बांग्लादेश सात विकेट से जीता

वेस्टइंडीज के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाले बांग्लादेश के शाकिब अल हसन। एपी

अफगानिस्तान के सामने इंग्लैंड की चुनौती

मैनचेस्टर, प्रेट्र : खिलाड़ियों की चोटों से परेशान इंग्लैंड कमजोर प्रतिद्वंद्वी अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को विश्व कप के मुकाबले में अपने टीम संयोजन को ठीक करके सेमीफाइनल में प्रवेश का दावा प्रबल करने के इरादे से उतरेगी।

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को कमर में दर्द के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान मैदान छोड़कर जाना पड़ा था जबकि सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय भी बायें पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान से वापस पवेलियन लौट गए थे। वह चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच में भी नहीं खेल सकेंगे। वहीं, मोर्गन का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा और फिट होने पर ही वह इस टीम के खिलाफ खेल सकते हैं। मोर्गन के फिट नहीं होने पर उप कप्तान जोस बटलर टीम की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान से हारने के बाद इंग्लैंड ने तीनों विभागों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और अब वह अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराने के इरादे से उतरेगा। दूसरी ओर अफगानिस्तान पहली जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बार विश्व कप में खेल रही अफगान टीम अब तक दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से हार चुकी है। अफगानिस्तान की चिंता का सबब उसकी बल्लेबाजी है क्योंकि किसी भी मैच में वे 40 ओवर भी नहीं टिक सके। राशिद को छोड़ कोई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाया। विकेट अगर स्पिनरों की मददगार होती है तो राशिद और मुहम्मद नबी की भूमिका अहम होगी।

अफगानिस्तान के कप्तान गुलाबदीन नायब। एपी

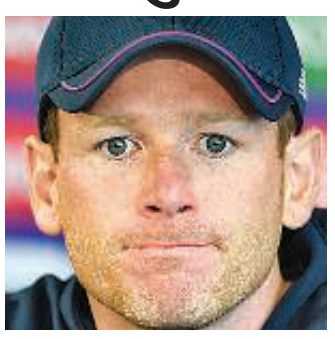

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन। एपी

क्रिस मॉरिस ने कहा न्यूजीलैंड विश्व कप जीतने की दावेदार

बर्मिंघम, एएनआइ : दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मैच से पहले कहा कि यह टीम डार्क होर्स नहीं है, बल्कि इस टूर्नामेंट को जीतने की दावेदारों में से एक है। मॉरिस ने कहा कि मेरा मानना है कि एक और टीम है जो इस टूर्नामेंट की दावेदार है। मैं न्यूजीलैंड को डार्क होर्स नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है कि यह टीम उससे ज्यादा पाने की हकदार है। यह टीम विश्वस्तरीय है। ऐसे में हमारा अनुशासन उनके खिलाफ और भी कड़ा होगा। यह टीम वाकई अच्छी है। न्यूजीलैंड की टीम ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है और वह एक भी मुकाबला अभी तक हारी नहीं है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराया है। न्यूजीलैंड का चौथा मैच भारत के खिलाफ था, जो बारिश के कारण धुल गया था।

उरुग्वे की जीत में सुआरेज-कवानी के गोल

एडिंसन कवानी। एपी

बेलो होरिजोंते (ब्राजील), प्रेट्र : अनुभवी फुटबॉलर लुइस सुआरेज और एडिंसन कवानी के गोल की बदौलत उरुग्वे ने 10 खिलाड़ियों से खेल रही इक्वाडोर की टीम को कोपा अमेरिका के ग्रुप-सी में 4-0 से हरा दिया।

खेल के छठे मिनट में ही निकोलस लोडीरो ने गोल करके उरुग्वे को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद खेल के 24वें मिनट में इक्वाडोर के फुल-बैक जोस क्वेंतेरो को रेड कार्ड दिखाया गया जिसका फायदा उठाकर कवानी (33वें मिनट) सुआरेज (44वें मिनट) ने गोल करके उरुग्वे को हाफ टाइम तक तीन गोल से आगे कर दिया। कवानी ने डिएगो गोडिन से मिले पास पर बॉक्स के अंदर से बाईसकिल किक के जरिये गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और अपने अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 47 पहुंचा दी। वहीं सुआरेज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 57वां गोल दागा। इसके बाद निर्धारित समय से 12 मिनट पहले इक्वाडोर के अर्तुरो मिना आत्मघाती गोल कर बैठे जिससे उरुग्वे ने एक आसान जीत दर्ज की। अपने चौथे कोपा अमेरिका में पहला गोल करने वाले कवानी ने कहा कि पहले हाफ में हमारे पास मौके थे और हमने उन्हें भुनाया जिससे मुकाबले को स्थिर बनाने में मदद मिली। ग्रुप-सी में उरुग्वे की यह शानदार शुरुआत है। इस ग्रुप में चैंपियन चिली और मेहमान टीम जापान शामिल हैं।

फुटबॉल

▸ कोपा अमेरिका में उरुग्वे ने 10 खिलाड़ियों से इक्वाडोर को 4-0 से हराया

कतर ने पराग्वे को बराबरी पर रोका : उधर रियो डि जेनेरियो में ग्रुप-बी में खेले गए कोपा अमेरिका के एक मुकाबले में एशियन चैंपियन कतर ने पराग्वे को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। 0-2 से पिछड़ने वाली कतर की टीम ने बॉलेम खौखी द्वारा निर्धारित समय से 13 मिनट पहले किए गए गोल की बदौलत मुकाबले को ड्रॉ कराया।

विविध

हवा साफ हो जाएगी, धूल जल जाएगी

वैज्ञानिकों ने विकसित की तकनीक, कोल डस्ट के प्रदूषण से मिलेगी निजात

तापस बनर्जी, धनबाद

दशकों से कोयला व अन्य खनिजों का उत्पादन करनेवाले धनबाद जैसे कई शहर कोयले के कण मिश्रित धूल के गुबार से परेशान हैं। हवा में घुलकर ये कण जहां सांसों में जहर घोल रहे हैं वहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ाकर कई बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं। अब एक नई तकनीक इस समस्या का समाधान लेकर आई है। इस तकनीक के तहत हवा में उड़ने वाली धूल को ठोस रूप देना संभव है। ऐसा करते ही हवा भी शुद्ध हो जाएगी। इस सोच को संभव कर दिखाया है केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिंफर) धनबाद के वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने तकनीक विकसित कर टाटा मोटर्स मुंबई को सौंप दी है, जो इसका वाणिज्यिक उपयोग जल्द शुरू करेगी। अगर यह शोध धरातल पर उतर जाता है तो कोयला खदानों की वजह से प्रदूषण से थर्रा रहे धनबाद सरीखे शहरों को संजीवनी मिल जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण

ओपन कास्ट माइंस से निकलने वाले वाहनों से 80 फीसद तक वायु प्रदूषण फैलता है। नई तकनीक धूल को ठोस रूप में तब्दील कर ब्रिकेट (ठोस रूप) बना देगी, जो जलाने के काम आ सकेगी। इसके लिए रोड डस्ट कलेक्टिंग व ब्रिकेटिंग सिस्टम तैयार हो गया है। जो ओपन कास्ट माइंस (खुली खदानों) में दौड़ने वाले वाहनों के लिए विकसित किया गया है। सिंफर ने अपनी इस तकनीक को पेटेंट कराने की तैयारी कर ली है।

वाहन में लगा रोड डस्ट कलेक्टिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम। जागरण

सिंफर की ओर से जनता के हितों को ध्यान में रख लगातार शोध हो रहे हैं। इस तकनीक से पूरी दुनिया के लिए समस्या बने कोयला धूल प्रदूषण को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

– डॉ. प्रदीप कुमार सिंह, निदेशक, सिंफर

इस तकनीक का सफल ट्रायल हो चुका है। कोलियरी में चलनेवाले वाहनों में इसका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट के लिए भी ऐसी ही विशेष तकनीक पर शोध जारी है।

– डॉ. एसके चौल्या, प्रोजेक्ट लीडर, सिंफर

घरेलू जलावन के काम आएगा ब्रिकेट : प्रोजेक्ट लीडर सिंफर वैज्ञानिक डॉ. एसके चौल्या ने बताया कि इस प्रणाली से खदान और कोयला उद्योग क्षेत्र की कोल डस्ट को एकत्रित किया जा सकेगा। एकत्रित किए गए कोयले के कणों को विभिन्न रसायनों के माध्यम से कोल ब्रिकेट में बदला जाएगा। इनका घरेलू जलावन के रूप में उपयोग हो सकेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह तकनीक बेहद कारगर होगी। क्योंकि हवा को यह साफ कर देगी। इससे कोल डस्ट से होने वाले प्रदूषण के कारण हो रही बीमारियों को भी कम किया जा सकेगा।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

छह माह तक पता ही नहीं चला कहां ले गई पुलिस

आपातकाल के दौरान अंबाला की जेल में बंद रहे लाला श्यामसुंदर के परिवार ने झेला असहनीय दर्द

अमित पोपली, झज्जर

25 जून 1975। देश में आपातकाल लग गया था। रात दस बजे लाला श्यामसुंदर गोयल रोज की तरह झज्जर स्थित दुकान से घर लौटे। चेहरे पर चिंता और विस्मय का भाव। आते ही बोले, आज घर के बाहर कुछ अनजान चेहरे मुझे घूर रहे थे। कुछ गलत होने का भान तो था, मगर यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो सकता है? खैर, भोजन के बाद अपने शयनकक्ष में चले गए। काफी देर तक नींद नहीं आई। अभी आंख लगी ही थी कि किसी ने दरवाजा पीटा। घड़ी देखी तो सुबह के चार बजे थे। तमाम सवाल जेहन में आने लगे। दोबारा खट-खट की आवाज हुई। पूछा तो सामने से थानेदार की कड़क आवाज थी-दरवाजा खोलो। सोने से पहले की आशंकाएं अब दरवाजे पर खड़ी थीं। थानेदार ने सिर्फ इतना बताया कि ऊपर से गिरफ्तारी का आदेश है।

44 साल पहले की वह काली रात याद कर लाला श्यामसुंदर के पुत्र शिवशंकर की आंखें भर आईं। वह कहते हैं-कैसे भूल सकता हूं उस मनहूस रात को। उस दिन ने हम भाई-बहनों का बचपन छीना है। मां प्रेमवती देवी और हम सात भाई-बहन (घनश्याम गुप्ता, सुरेश चंद, नरेश चंद, दिनेश गुप्ता, डॉ. शिवशंकर, नंद किशोर, उर्मिला रानी) पिताजी की गिरफ्तारी से स्तब्ध थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? कहां जाएं? बस यही सवाल था कि अब क्या होगा, बाबूजी कहां गए, कब आएंगे? मगर किसी के पास सही जवाब नहीं था। हो भी नहीं सकता था। पुलिस से पूछने पर धमकी मिलती थी। शिवशंकर बताते हैं कि सबसे बड़े भाई घनश्याम गुप्ता तब 17-18 साल के थे।

▸ सुबह चार बजे घर में सोते समय उठा ले गई थी पुलिस

▸ पत्नी पर आ गई थी सात बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी

मां गृहिणी थीं। आढ़त की दुकान मुनीम के भरोसे हो गई थी। कारोबार घटने लगा। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि छह माह तक हमें पता नहीं चल पाया कि पिता जी को लेकर वे लोग गए कहां हैं? किसी तरह उनके अंबाला जेल में बंद होने की बात सामने आई तो डर थोड़ा कम हुआ। माता जी के साथ बड़े भाई जेल में मिलने गए। महज दो मिनट की मुलाकात थी। हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले आरएसएस की विचाराधारा वाले पिताजी अब चिंतित थे। शरीर से भी कमजोर हो गए थे। सोचने का अंदाज बदल चुका था। कहते थे-अगर गलती की होगी तो माफी भगवान से मांगेंगे, इंसान से किसलिए?

धीरे-धीरे हालात और बिगड़ते गए। मां अकेली घर संभालने वाली थीं। उन पर हम सात भाई-बहनों के लालन-पालन की जिम्मेदारी आ गई। लगता था कि सभी टूट जाएंगे, मगर मां हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने किसी के सामने दुख नहीं रोया। वह अकेले में आंसू बहाती थीं। कोई देखता तो आंचल से आंसू पोंछ लेतीं और जतातीं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।

अपने परिवार के साथ लाला श्याम सुंदर गोयल का फाइल फोटो।

जेल से आए तो बदला था अंदाज : 11 माह बाद जब पिताजी पैरोल पर जेल से बाहर आए तो पूरी तरह बदल गए थे। बातचीत में संत-योगी जैसा अहसास करा जाते थे। कहते थे कि अब देश में बदलाव जरूरी है। जीवनभर आपातकाल से जुड़े किस्से सुनते-सुनाते रहे। उनके कमरे में डॉ. मंगल सेन, लक्ष्मी चंद गुप्ता, हुक्म चंद गोयल सहित अन्य दिग्गज घंटों चर्चा करते।

चाचा की जबरन नसबंदी करा दी थी पुलिस ने : शिवशंकर ने बताया कि आपातकाल के दौरान चाचा को पुलिस ने उठा लिया और जबरन नसबंदी करा दी गई। कई दिनों तक तो वे सामान्य भी नहीं हो पाए। जेल से पिता जी आए तो चाचा ने रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई।

एक कार्यक्रम में लाला श्याम सुंदर गोयल का फाइल फोटो।

रूस के पर्वतारोहियों ने किया सतोपंथ का सफल आरोहण

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी

▸ 7075 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है सतोपंथ

गंगोत्री हिमालय के सबसे ऊंचे सतोपंथ हिमशिखर (7075 मीटर) का दो विदेशी पर्वतारोहियों सहित चार लोगों ने सफल आरोहण किया। इस सीजन में सतोपंथ का आरोहण करने वाला यह पहला दल है। सतोपंथ पर इन दिनों सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के दल आरोहण के लिए गए हुए हैं। रूस के पर्वतारोही एंड्रे फिल्कोफ व उनके एक अन्य साथी हाई लैंड ट्रैक एंड टूर के नेतृत्व में गत 22 मई को उत्तरकाशी से सतोपंथ चोटी के आरोहण को रवाना हुए। लेकिन, मौसम खराब होने के कारण कई दिनों तक इस दल को भोजवासा क्षेत्र में रुकना पड़ा। मौसम साफ होने पर दल भोजवासा, गोमुख, नंदनवन व वासुकी ताल के दुर्गम रास्तों से होकर सतोपंथ के बेस कैंप पहुंचा। यहां से दोनों पर्वतारोहियों समेत सिक्किम निवासी शेरपा मिग्मा व नेपाल निवासी गेल्बु ने दस जून की सुबह नौ बजे सतोपंथ चोटी का आरोहण किया। हाई लैंड ट्रैक एंड टूर के पीतांबर सिंह पंवार ने बताया कि सतोपंथ चोटी गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस सीजन में इस चोटी का आरोहण करने वाला यह पहला दल है।

गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची सतोपंथ चोटी का आरोहण करते रूसी पर्वतारोही। जागरण

सकलाना में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग

जासं, नई टिहरी : सोमवार देर शाम सकलाना पट्टी के गांवों में हेरीटेज एविशन के दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग से ग्रामीण दहशत में आ गए। जिला प्रशासन के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर को एयर सिग्नल गायब होने से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। थोड़ी देर बाद मौसम सामान्य होने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर देहरादून के लिए हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए टिहरी की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हेरीटेज एविएशन के दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग सकलाना पट्टी के गांवों में हुई है। हालांकि, यह हेलीकॉप्टर किसके थे इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

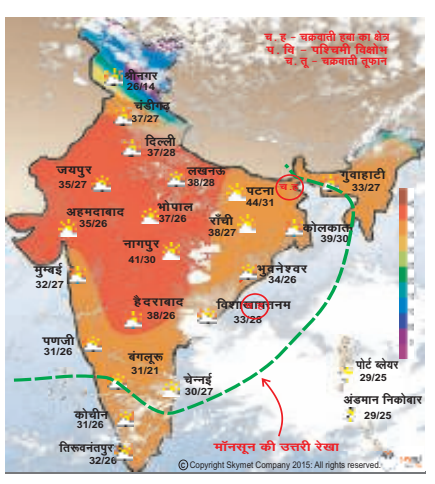

मौसम विशेष

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में हल्की वर्षा जारी रहेगी। जिसके कारण तापमान में कमी आएगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर गरज के साथ वर्षा संभव है। जबकि बाकि हिस्सों के तापमान में वृद्धि हो सकती है। राजस्थान में तेज हवाओं का असर रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/26/व	अहमदाबाद	40/28/व
कोलकाता	38/29/व	बड़ोदा	39/27/आंबा
चेन्नई	40/29/व	नागपुर	41/30/व
हैदराबाद	38/27/व	इन्दौर	39/27/व
बंगलूरू	31/21/व	रांची	38/28/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/व	पटना	41/31/व
गुवाहाटी	32/28/आंबा	जमशेदपुर	39/29/आंबा
गंगटोक	17/09/व	पुणे	25/23/व

भारत का राष्ट्रीय पशु बना बाघ

1972 में आज के ही दिन बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ की चपलता, शालीनता, दृढ़ता और अपार शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। इसी के बाद अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई।

पहली जीएम वैक्सीन की घोषणा हुई

1981 में आज ही दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफायड (जीएम) वैक्सीन की घोषणा हुई। उसे अमेरिकी कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने जानवरों के मुंह की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया था। इसमें वीपी3 नामक प्रोटीन विकसित किया गया था।

आधुनिक बिहार के निर्माता थे अनुग्रह बाबू

महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ रहे अनुग्रह नारायण सिंह का 1887 में आज ही बिहार के गया जिला के पोइवान गांव में जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ये बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री (1946-1957) थे। इन्होंने महात्मा गांधी और डॉ राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। बाद में इनके सबसे बड़े पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बने।

इधर-उधर की

कुत्ता समझ पाला भालू, हुई गिरफ्तारी

कुआलालांपुर, एजेंसी : इसे जानवरों के प्रति प्रेम की शायद इंतेहा ही कहेंगे कि किसी जानवर प्रेमी को कुत्ते और भालू का अंतर नहीं दिखा। मलेशिया की इस जानवर प्रेमी महिला को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा और वे गिरफ्तार कर ली गईं। दरअसल यहां की गायिका जरिथ सोफिया यसीन को कुछ दिन पहले सड़क पर मरणासन्न अवस्था में एक जानवर का बच्चा मिला। दुर्बल जानवर को कुत्ता समझ वे अपने साथ ले आईं। खिलाया-पिलाया उसकी सेवा की। बाद में सेहतमंद होने पर वह जानवर भालू लगने लगा। तब उन्होंने सोचा कि कुछ दिन बाद उसे चिड़ियाघर को सौंप देंगी। लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस से शिकायत कर दी। मलेशिया में जंगली जानवरों को पालने पर रोक है। लिहाजा पुलिस ने उनके घर पर छापामारी करके भालू को बरामद किया। इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया।

शोध अनुसंधान

शैंपू, लोशन और नेल पॉलिस बच्चों के लिए नुकसानदेह

एक नए अध्ययन में आगाह किया गया है कि शैंपू, लोशन, नेल पॉलिस और नेल पॉलिस रिमूवर जैसे पर्सनल केयर के उत्पाद बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले विषाक्त पदार्थों और रसायनों से बच्चों की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका के नेशनवाइड चिल्ड्रन अस्पताल के शोधकर्ताओं ने पाया कि साल 2002 से 2016 के दौरान पांच साल से कम उम्र के करीब 65 हजार बच्चों में इन उत्पादों की वजह से हुई परेशानियों का इलाज किया गया। नेशनवाइड की शोधकर्ता रेबेका मैकएडम्स ने कहा, 'इन उत्पादों पर लिखी चीजों को छोटे बच्चे पढ़ नहीं सकते। वे इन पर लगे रंग-बिरंगे लेबल या इसकी खुशबू से आकर्षित होते हैं। वे इन्हें खाना या पीना चाहते हैं। इसलिए खोलने के प्रयास में यह उन पर गिर सकता है। वे अपने माता-पिता को इन्हें इस्तेमाल करते देखते हैं। इसलिए वे भी इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं।' -प्रेट्र

दवाओं का असर कम कर सकते हैं गट बैक्टीरिया

एक अध्ययन में पाया गया है कि हम जो दवा खाते हैं, उन्हें हमारे गट (आंत) बैक्टीरिया खा सकते हैं। इससे दवा का प्रभाव कम होने के साथ ही खतरनाक दुष्प्रभाव की समस्या भी खड़ी हो सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ठोस साक्ष्य के साथ यह बताया कि किस तरह माइक्रोब्स शरीर में दवा के रास्ते में दखल दे सकते हैं। उन्होंने पार्किंसन के उपचार में काम आने वाली दवा लीवोडोपा (एल-डोपा) को लेकर यह पता लगाया कि इसका प्रभाव कम करने में कौन जिम्मेदार है और इस दखल को किस तरह रोका जा सकता है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए ली-डोपा मस्तिष्क में डोपामाइन की आपूर्ति करती है, लेकिन महज एक से पांच फीसद ही दवा मस्तिष्क तक पहुंच पाती है। -प्रेट्र

अध्ययन ▸ पृथ्वी में मौजूद प्लैटिनम, यूरेनियम के बारे में वैज्ञानिकों ने पेश की नई अवधारणा

सुपरनोवा के कारण पृथ्वी पर आईं धातुएं

कनाडा और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन, नेचर जर्नल में हुआ प्रकाशित

तारों के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। प्रतीकात्मक

टोरंटो, प्रेट्र : दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कीमती धातुओं (सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम आदि) का खजाना दफन है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ये धातुएं पृथ्वी में आईं कैसे। क्या यह भूगर्भ की रासायनिक प्रक्रिया के कारण बने हैं या किसी अन्य कारण से इनका निर्माण हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इन कीमती धातुओं के पृथ्वी पर मिलने के बारे में एक नई अवधारणा पेश की है। एक अध्ययन में उन्होंने दावा किया है कि सुपरनोवा के कारण ही पृथ्वी को सोने और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं का उपहार मिला है। सुपरनोवा किसी तारे में हुए भयंकर विस्फोट को कहते हैं। इससे निकलने वाला प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा धुंधली हो जाती है।

कनाडा की गुएफ यूनिवर्सिटी और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया अध्ययन पृथ्वी पर पाए जाने वाले भारी और कीमती तत्वों के बारे में हमारी समझ को पलट देता है।

नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, ब्रह्मांड में लगभग 80 फीसद भारी और कीमती तत्व कोलैप्सार्स प्रक्रिया के दौरान दुनिया में आईं। कोलैप्सार्स सितारों के टूटने की एक दुर्लभ प्रक्रिया है और यह सुपरनोवा के दौरान ही घटित होती है। इस दौरान भारी मात्रा में धातुएं टूटे तारे से निकलती हैं।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटरों के जरिये सिमुलेशन कर कोलैप्सार्स की गतिशीलता का पता लगाया। गुएफ यूनिवर्सिटी के डेनियल साइगेल ने कहा कि अध्ययन में यह बात सामने आई कि सितारों के टूटने पर भारी तत्वों का बड़े पैमाने पर बिखराव शुरू हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तत्व ब्रह्मांड में इधर-उधर अनेक ग्रहों में फैल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये आश्चर्यजनक लगता है लेकिन इन तत्वों की मात्रा और वितरण सौर मंडल में देखे गए तत्वों के समान ही है।

साइगेल ने कहा कि बहुत समय पहले अंतरिक्ष में हुए विस्फोट के कारण ही परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम से लेकर अन्य रासायनिक तत्व पृथ्वी और अन्य जगहों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक अनुमान ऐसा भी है कि ये कीमती तत्व पृथ्वी के साथ-साथ अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं, क्योंकि विस्फोट के बाद जब धातुओं का बिखराव होना शुरू हुआ होगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तत्व निश्चित तौर पर अन्य ग्रहों पर भी गिरे होंगे। साइगेल ने कहा कि इस शोध से हमारी आकाशगंगा के निर्माण के बारे में सुराग मिल सकता है। शोधकर्ताओं की टीम को उम्मीद है जल्द ही इस अध्ययन को सैद्धांतिक तौर पर मान्यता मिलेगी।

वैज्ञानिकों ने खोजे थे 1800 सुपरनोवा

हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और गतिशील है कि उसमें निरंतर कुछ न कुछ घटित होता रहता है। वैज्ञानिक दिन-प्रतिदिन इसके बारे में नई जानकारियां जुटाते रहते हैं। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने 1800 नए सुपरनोवा खोजे थे। इनकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड किस गति से विस्तार कर रहा है। जापान की कवली इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिक्स एंड मैथमैटिक्स ऑफ द यूनिवर्स (कवली आइपीएमयू) और टोक्यो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिजिटल कैमरों और टेलीस्कोप के डाटा से इनकी खोज की थी।

धारियों से तापमान नियंत्रित करते हैं जेब्रा

▸ धारियों में होती हैं उष्मा संवहन करने वाली धाराएं जो ताप को स्थानांतरित करती हैं

▸ ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का अध्ययन नेचर जर्नल में हुआ प्रकाशित

अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में सर्वाधिक जेब्रा पाए जाते हैं। फाइल

लंदन, प्रेट्र: वैज्ञानिकों ने पहली बार यह पाया है कि जेब्रा अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए काली धारियों में हेरफेर कर सकते हैं। नेचर हिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र अफ्रीका में निवास करने वाले जेब्रा शरीर का तापमान को अपनी काली-सफेद धारियों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इनकी धारियों में उष्मा संवहन करने वाली धाराएं होती हैं जो तापमान को स्थानांतरित करती हैं। इससे पहले यह समझा जाता था कि जेब्रा की ये धारियां केवल अपने शिकार को धोखा देने के लिए होती हैं। अध्ययन में बताया गया कि जेब्रा अपनी काली धारी को मौसम के मुताबिक बढ़ा और घटा सकता है।

ब्रिटेन निवासी जीवविज्ञान तकनीशियन एलिशन कोब और उनके जूलॉजिस्ट पति डॉ. स्टीफन कोब ने बताया कि जेब्रा की धारियों का अद्भुत पैटर्न उसको अपना तापमान नियंत्रित करने की सहूलियत देता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपना ज्यादातर समय अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में जेब्रा पर अध्ययन करने में बिताया है। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के लगातार बदलते तापमान में जेब्रा जिस तरह से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए धारियों का उपयोग करता है। इसे समझना जटिल तो है ही, साथ ही यह रोचक भी है। उन्होंने कहा कि जेब्रा के पसीने के वाष्पीकरण में भी इन धारियों का विशेष योगदान होता है। जिससे जेब्रा को तापमान अनुकूलित करने में मदद मिलती है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में जेब्रा की काली और सफेद दोनों धारियों का तापमान अलग-अलग दर्ज किया गया। काली धारी का तापमान सफेद से 12-15 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा पाया गया।

प्रयोगशाला में भी पैदा की जा सकती है सेलमन मछली

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : समुद्र में सेलमन मछलियों की घटती आबादी को देखते हुए अब इन्हें सप्लीमेंट के जरिये प्रयोगशाला में भी पैदा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेलमन अब 'गिनी पिग' जैसी हो गई है। गिनी पिग कुछ हद तक सूअरों की तरह दिखते हैं लेकिन ये वास्तविकता में सूअर नहीं होते।

राष्ट्रीय मत्स्य संस्थान के अनुसार सीफूड के मामले में मोटी और नारंगी रंग की यह मछली वर्ष 2017 में अमेरिका में झींगे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली थी। उस वर्ष इसकी प्रति व्यक्ति खपत में 11 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी। वैश्विक स्तर पर भी सेलमन की मांग आसमान छू रही है, जिसे देखते हुए वैज्ञानिक अब इसका उत्पादन फॉर्म में करना शुरू कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में फॉर्म में पैदा हुई मछलियों का मांस एक विकल्प के तौर पर हमारे सामने होगा। हाल में ही पोलैंड के एक समूह ने अपने रेस्तरां के लिए फॉर्म में पैदा हुई इस मछली का ऑर्डर भी दिया था।

वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं आदिवासी

स्पेक्ट्रम

▸ आइआइटी के विशेषज्ञों ने कहा कि जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं यदि उनसे बात की जाए तो हमारे प्रयास सार्थक होंगे

जंगलों के बारे बेहतर समझ रखते हैं आदिवासी समुदाय के लोग। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : वन्यजीवों के संरक्षण के लिए शहरों में लोग अक्सर प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और खास तौर पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय का वन्यजीवों के प्रति नजरिया बिल्कुल विपरीत होता है। आइआइटी के विशेषज्ञों का सुझाव है कि जंगली जीव-जतुंओं बचाने के लिए शहरी लोगों की सांकेतिक सक्रियता की बजाय यदि हम आदिवासियों को इस मुहिम से जोड़ें तो निश्चित तौर पर हम वन्यजीवों का बेहतर तरीके से संरक्षण कर पाएंगे।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गांधीनगर के एसिस्टेंट प्रोफेसर अंबिका अय्यादुराई ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने से हम मनुष्य और जानवरों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन का यह सबसे सही समय है।

वन्यजीव संरक्षण पर गहराई से अध्ययन करने वाले अय्यादुराई ने कहा 'हम सोचते हैं कि जंगलों जानवरों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने का विचार उपयुक्त है पर लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इससे कई समस्याओं से जूझना पड़ता है।'

उन्होंने कहा कि भारत में यदि जंगल और जंगली जानवरों को बचाना है तो हमेशा स्थानीय समुदाय के लोगों से हमें बात करनी होगी। वन्यजीव और मनुष्य प्राचीन काल से शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व के भाव के साथ रह रहे हैं लेकिन जंगली जीवों के संरक्षणकी आधुनिक अवधारणाओं के कारण मनुष्य और वन्यजीवों के बीच गहरी खाई बन रही है। लोग अब जंगलों से दूर हो गए हैं और जानवर आबादी में ना घुस आएं इसके लिए हमने जंगलों के चारों ओर बाड़ लगा दी है। अब लोग केवल एक पर्यटक की भांति इन जानवरों को देखते हैं और सबसे बड़ी बात इन जानवरों के ज्यादातर आवासों में खनन कार्य जोरों पर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जंगली जानवर भी आबादी में घुस आएंगे।

अय्यादुराई ने कहा भारत में मध्यम वर्ग की पर्यावरण को बचाने की मुहिम भी बुर्जुवा-सी लगती है। जिसका अर्थ है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक मान्यताएं वस्तु और पूंजी केंद्रित हो गई हैं। पर्यावरण आंदोलनों में वह बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि क्या वास्तविकता में उनके प्रयास सार्थक हो पाएंगे क्योंकि वह खुद तो जंगल के परिवेश से दूर रहते ही हैं साथ ही उन्हें आदिवासियों या ग्रामीणों की चिंताओं का अंदाजा तक नहीं होता। उन्होंने कहा यह जरूर है कि उनके प्रदर्शन चेतनापूर्ण हैं लेकिन दूसरी ओर आदिवासी और ग्रामीण यह सोचते हैं जंगली जानवरों से अपनी फसलों और मवेशियों को कैसे बचाया जाए।

अय्यादुराई ने कहा कि मेरा मानना है कि जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, पर्यावरण के साथ उनका रिश्ता मुश्किल है। यह व्यावहारिक है और उनकी चिंता भी जायज हैं। शहर में रहने वाले लोग जमीनी हकीकत जाने बिना ही संरक्षण अभियान में हिस्सा लेते हैं। उन्हें प्रकृति की एक बहुत अच्छी तस्वीर दी जाती है, जो प्रकृति से जुड़ी होती है न कि प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए।

मनोविकारों का पूर्वानुमान लगा सकता है एआइ टूल

वाशिंगटन, प्रेट्र : आर्टिफिशिल इंटेलीजेंस (एआइ) का प्रयोग कर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लोगों की आवाज के जरिये वह भविष्य में होने वाले मनोविकारों के जोखिम का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। मशीन लर्निंग विधि लोगों के बातचीत की ऐसी भाषा को पकड़ सकती है जो भविष्य में मनोविकारों के लिए उत्तरदायी होती है।

एनपीजे सिजोफ्रेनिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि हमारी भाषा में भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण के जरिये यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य में मनोविकृतियों से ग्रसित हो सकता है या नहीं। शोधकर्ताओं की मानें तो इस विधि से मनोविकारों का 93 फीसद सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

खूबसूरत नजारा

यह बेहद दिलकश नजारा पूर्वी चीन के शैंडोंग प्रांत में समुद्री शैवाल केल्प की खेती की कटाई के दौरान छोटी नावों को एक साथ ले जाने का है। देखकर लग रहा जैसे समुद्र में कोई कलाकृति तैयार की गई है। काबिलेगौर है कि केल्प उत्तरी व दक्षिणपूर्वी चीन के सबसे महत्वपूर्ण खेती में से एक है। रोंगचेंग में इसका सालाना उत्पादन 4 लाख 33 हजार टन पहुंच गया है, जो चीन के कुल केल्प उत्पादन का लगभग आधा है। एएफपी

कोरिया की खूबसरती के दीवाने हुए जापानी

अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दुनियाभर में 'कुख्यात' उत्तर कोरिया के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जापान के युवाओं का एक दल इन दिनों उत्तर कोरिया के भ्रमण पर है। प्रसिद्ध टेडॉन्ग नदी के पास यह खूबसूरत नजारा देखकर युवाओं का दल खुशी से उछल पड़ा। इस दृश्य को युवक ने अपने टेबलेट के कैमरे में कैद कर लिया। पार्श्व में कोरिया का लैंडमार्क जूशे टावर भी नजर आ रहा है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

अगले साल 'सरदार ऊधम सिंह' और 'रैम्बो' में होगी टक्कर

हिंदी सिनेमा में फिल्म की रिलीज तारीख को एडवांस में बुक करने का चलन पुराना हो गया है। ज्यादातर फिल्म निर्माता इस कोशिश में रहते हैं कि उनकी फिल्में किसी त्योहार या छुट्टियों के आसपास रिलीज हों। ऐसे में कई बार फिल्मों का क्लैश होना भी संभव है। अगले साल दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होगी। विक्की कौशल की फिल्म 'सरदार ऊधम सिंह' और टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'रैम्बो' गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होगी। दोनों ही फिल्में अपने विषय को लेकर पहले से ही चर्चा में हैं। 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद विक्की कौशल की यह फिल्म भी देशभक्ति पर आधारित होगी। शूजीत सरकार द्वारा निर्देशित 'सरदार ऊधम सिंह' क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह की कहानी होगी, जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ' डायर की हत्या कर दी थी। बात की जाए अगर टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'रैम्बो' की, तो यह फिल्म वर्ष 1982 में रिलीज हुई सिल्वेस्टर स्टेलॉन अभिनीत हॉलीवुड फिल्म 'रैम्बो' की हिंदी रीमेक होगी।

सलमान खान ने भतीजे योहान को दी नसीहत

सलमान खान का अपने घर के बच्चों के प्रति प्यार अक्सर उनके सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। कभी वह बहन अर्पिता के बेटे आहिल के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, तो कभी अपने भतीजों के साथ उनका वीडियो वायरल हो जाता है। इस बार भाई सोहेल खान के बेटे योहान के आठवें जन्मदिन के मौके पर सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है, जो मजेदार तो है ही, साथ ही उन्होंने योहान को जीवन को लेकर एक नसीहत भी दी है।

सलमान ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें योहान बीन बैग पर बैठे हुए हैं। एक तरफ से जब सोहेल कूदकर उनके बीन बैग पर बैठते हैं, तब उनके प्रेशर से योहान उछलकर सामने खड़े सलमान खान की गोद में चले जाते हैं। इस स्लो मोशन वाले वीडियो के साथ सलमान ने लिखा, 'हैप्पी बर्थ डे योहान...डैड आपके पीछे खड़े होंगे और मैं आपके आगे, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा मत उड़ना।' योहान की जन्मदिन पर सलमान सहित उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। 'भारत' की सफलता के बाद यह पहला मौका था जब सलमान परिवार के साथ वक्त बिताया।

'द ऑफिस' के सेट पर सितारों ने खेले मजेदार खेल

काम करने वाली जगह का माहौल अगर खुशनुमा और अच्छा हो तो काम बेहतर होता है। ऐसा ही माहौल था वेब शो 'द ऑफिस' के सेट पर। जब सेट पर ब्रेक का वक्त होता है तो स्टार्स अक्सर बैडमिंटन या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। लेकिन 'द ऑफिस' शो के सेट पर सितारों ने खेले वह खेल जो बचपन की याद दिलाते हैं। फिल्म की टीम ने सेट पर कार्ड के खेल से लेकर रॉक पेपर सिजर, वीडियो गेम्स, ऊनो और लूडो जैसे कई खेल खेले। शो में खुद को बेस्ट बॉस होने का दावा करने वाले किरदार जगदीप चड्ढा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मुकुल चड्ढा ने बताया, 'हमारे बीच लूडो प्रतियोगिता होती थी। हम सब इस खेल में इतने रम गए थे कि एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए थे। जब हम कैमरे पर नहीं होते थे, तब सेट पर लूडो, रॉक पेपर सीजर्स, डायनासोर वीडियो गेम्स खेलते रहते थे।' 'द ऑफिस' प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडी टीवी सीरीज का भारतीय संस्करण है। अमेरिकी शो में बॉस का किरदार अभिनेता स्टीव कैरल ने निभाया था, जबकि इस शो में बॉस का रोल मुकुल चड्ढा निभा रहे हैं। शो का प्रसारण हॉटस्टार वाईपी पर होगा।

दर्शकों का प्यार हर तरह के रोल करने की हिम्मत देता है : आयुष्मान

अभिनेता आयुष्मान खुराना फिल्मों में अपनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि वे हर तरह का रोल बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं। उनकी अधिकांश फिल्में कुछ न कुछ सामाजिक संदेश जरूर देती हैं। इसलिए वे फिल्मों का चयन करने के पहले यह अच्छे से देखते हैं कि फिल्म कुछ हटकर हो और साथ ही समाज के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हो। वे 'विकी डोनर' से लेकर 'शुभ मंगल सावधान', 'बधाई हो' जैसी फिल्में कर चुके हैं जिनमें उनके किरदार को खूब सराहना मिली। आयुष्मान कहते हैं-लोगों से मिलने वाला प्यार ही मुझे अलग-अलग तरह के रोल करने की हिम्मत देता है। इस तरह की फिल्में चुनता हूं जिन्हें देखने के बाद लोग सोचें और आपस में चर्चा करें। मेरी आने वाली तीनों फिल्में भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर आप 'आर्टिकल 15' की बात करें तो वह रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। जो लोग अच्छी इंवेस्टिगेटिव फिल्म देखना चाहते हैं उन्हें फिल्म आखिरी तक बांध कर रखेगी। 'बाला' जिसके समय से पहले बाल झड़ जाते हैं वह किस तरह से उसे हैंडल करता है। हमने इसे बड़े ही अलग और मनोरंजक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। इसीतरह फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' होमोसेक्सुएलिटी और उससे जुड़े टैबू पर आधारित है।

सोना ने सलमान को कहा पेपर टाइगर

गायिका सोना महापात्रा ने एक बार फिर सलमान खान पर निशाना साधा है। सोना ने इस बार सलमान को 'पेपर टाइगर' कहा है। गायिका ने एक्टर की हाल ही में रिलीज फिल्म 'भारत' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट शेयर की है। सोना ने लिखा है-आप ऐसे फिल्मी सुपरस्टार को क्या कहेंगे जिसकी फिल्म इतने ज्यादा प्रमोशन के बाद भी एक सप्ताह अच्छे से रिटर्न नहीं दे पाए। इसका जबाव सोना खुद देती हैं पेपर टाइगर्स। इन पेपर टाइगर्स की पूजा करना बंद करिए। इनकी जगह कुछ वाकई अच्छे हीरो ढूढ़िए। इसके पहले भी सोना ने कई मौकों पर सलमान पर निशाना साधा है।

चिंताजनक

टिकटॉक और पबजी खेलने के दुष्प्रभावों के सामने आने के बाद मनोचिकित्सकों ने किया आगाह, कहा-इनकी लत नशे जितनी ही खराब है...

स्मार्टफोन की लत से ऐसे पा सकते हैं छुटकारा

खतरनाक है स्मार्टफोन की लत। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : स्मार्टफोन पर टिकटॉक और पबजी खेलने के दुष्प्रभावों की आए दिन खबरें सामने आने के बाद मनोचिकित्सकों ने लोगों को आगाह करते हुए इसकी लत को नशे जितना ही खतरनाक बताया है। यह चेतावनी पिछले सप्ताह तमिलनाडु में टिकटॉक खेलने से रोकने पर 24 वर्षीय एक मां के आत्महत्या करने और मध्यप्रदेश में पिछले महीने लगातार छह घंटे पबजी खेलने वाले एक छात्र की दौरा पड़ने से मौत होने के बाद आई है।

विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल लत से लड़ने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसके बढ़ने का लोगों को अहसास हो। फोर्टिस हेल्थकेयर के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यावहारिक विज्ञान विभाग के निदेशक समीर पारिख ने कहा कि लोगों के लिए अपने ऑफिस, घर के अंदर और बाहर का काम, मनोरंजन तथा अन्य व्यस्तताओं के बीच संतुलन कायम रखना सबसे जरूरी है। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि वे पर्याप्त नींद ले रहे हैं।

पारिख ने कहा कि वयस्कों को चाहिए कि वह प्रति सप्ताह चार घंटे खुद को इन डिजिटल उपकरणों से दूर रखें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इन चार घंटों में परेशानी होती है तो यह चिंताजनक बात है। नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के मनोचिकित्सा विभाग के सीनियर कंसल्टेंट संदीप वोहरा ने कहा कि गैजेट्स के आदी लोग हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते हैं या जब वे इन उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते तो उन्हें अनिद्रा और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। उन्होंने कहा कि यदि आप डिजिटल लत के शिकार हैं तो ये संकेत है कि आप अपने दैनिक जीवन से दूर जा रहे हैं। ऐसे लोग कई बार समाज और अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई मामले ऐसे में सामने आए हैं कि ऐसे लोग अपने नियमित काम करना भी छोड़ देते हैं। वोहरा ने कहा कि ऐसे लोगों में अवसाद, चिंता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन के साथ-साथ अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रीत करने में परेशानी भी आ सकती है। वोहरा ने सलाह दी कि लोगों को जब लगे कि उनका बच्चा मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिता रहा है तो उन्हें सबसे पहले अपने बच्चे से बात करनी चाहिए और डिजिटल गैजेट्स से उपयोग को कम करने के लिए कहना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों के सामने मोबाइल या अन्य डिजिटल गैजेट्स के साथ ज्यादा समय न बिताएं क्योंकि अभिभावकों की देखा देखी में बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे।

फोर्टिस हेल्थकेयर के समीर पारिख ने कहा यदि आप अपने बच्चों को घर में ही व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वे भी डिजिटल लत का शिकार हों, इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को घर से बाहर शारीरिक खेलों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और हो सके तो खुद भी उनके साथ खेलें। उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, कई बार कहने के बाद भी यदि वह स्क्रीन को नहीं छोड़ पाता तो ऐसे में आप उन्हें डॉक्टरों के पास ले जा सकते हैं।